भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची		
विवरण	**संदर्भ**	
	कंडिका	**पृष्ठ**
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii - xii
अध्याय - I		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1 - 1.4	1 - 2
लेखापरीक्षा अधिदेश	1.5 - 1.7	2
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.8 - 1.10	2 - 4
अंश पूँजी, अनुदान/सहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण से संबंधित बजटीय जावक	1.11 - 1.12	4 - 5
वित्त लेखों के साथ समाधान	1.13 - 1.14	6
सा.क्षे.उ. का निष्पादन	1.15 - 1.18	6 - 8
लेखों के अंतिमीकरण में बकाया	1.19 - 1.23	8 - 10
लेखों पर टिप्पणियाँ	1.24 - 1.28	10 - 14
लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली	1.29	14
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प्र.) को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति	1.30	14 - 15
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार	1.31 - 1.32	15 - 16
अध्याय - II		
सरकारी कम्पनी से संबंधित समीक्षा		
झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, उद्योग विभाग सहित, की गतिविधियों की समीक्षा	2	17
कार्यकारी सारांश	-	17-20
परिचय	2.1	20
संगठनात्मक व्यवस्था	2.2	20-21
लेखापरीक्षा की पद्धति एवं क्षेत्र	2.3	21-22
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.4	22
लेखापरीक्षा मानदंड	2.5	22-23
लेखापरीक्षा में बाधायें	2.6	23

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	2.7	23
नियोजन	2.8	24
रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प योजनाओं का क्रियान्वयन	2.9	24-25
रेशम कीट पालन	2.10 - 2.15	25-31
हस्तकरघा	2.16 - 2.21	31-39
हस्तशिल्प	2.22	39-40
विक्रय एवं प्रचार	2.23 - 2.28	40-47
वित्तीय प्रबंधन	2.29 - 2.31	47-50
सामग्री प्रबंधन	2.32 - 2.33	50-52
मानव संसाधन प्रबंधन	2.34	52-53
अनुश्रवण और आंतरिक नियंत्रण	2.35 - 2.37	53-56
निष्कर्ष	-	56
अनुशंसाएं	-	56-57
अध्याय - III		
लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन	3	
सरकारी कम्पनियाँ		
झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड		
केन्दु पत्ती की बिक्री में कमियाँ	3.1	59
प्रस्तावना	3.1.1	59-60
लेखापरीक्षा परिणाम		
अबिक्रीत केन्दु पत्ती लॉट	3.1.2	60-62
दोषपूर्ण धारा के कारण क्रेताओं को अनुचित फायदा	3.1.3	62-63
अनुबंध के शर्तों का अनुपालन न करने से केन्दु पत्ती के बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव	3.1.4 - 3.1.5	63-67
केन्दु पत्ती के स्टॉक के बीमा में अपर्याप्तता	3.1.6	67-68
सांविधिक निगम		
झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड		
अनुपयुक्त नियोजन की वजह से ₹ 85.23 लाख की निधि का अवरोधन	3.2	68-71
जेनरेटर स्टेटर की मरम्मत पर निरर्थक व्यय	3.3	71-73

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
दंड की गैर-उगाही के कारण हानि		3.4	73-75
लाभार्थी राज्यों से प्रस्तावित ऊर्जा परियोजना के खर्चों के अंशों का अवसूलीकरण		3.5	75-77
सामान्य			
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही		3.6	77-79
परिशिष्ट			
क्र.सं.	**विवरण**		
1.1	सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम के संबंध में 31 मार्च 2013 को प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋण तथा मानवशक्ति को दर्शाती अद्यतन विवरणी	1.8	81-83
1.2	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य अंश पूँजी, ऋण, अनुदान तथा सहाय्य, प्राप्त प्रत्याभूति, बकायों की माफी, अपलिखित ऋण तथा अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण तथा मार्च 2013 की समाप्ति पर प्रत्याभूति प्रतिबद्धता, को दर्शाती विवरणी	1.11	84-85
1.3	अद्यतन वर्ष के लिए तैयार लेखे के अनुसार सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.15	86-88
1.4	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के वित्तीय परिणाम को दर्शाती विवरणी	1.15	89
1.5	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकारी परिणाम को दर्शाती विवरणी	1.15	90
1.6	राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया हैं, में किए गए निवेश को दर्शाती विवरणी	1.21	91-92
2.1	झारक्राफ्ट की संगठन संरचना	2.2	93
2.2	वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान उत्पादित कोकून का ब्योरा दर्शाती विवरणी	2.10	94
2.3	क्लस्टर विकास योजना के लिए मंजूर राशि, लक्ष्य एवं उपलब्धि का ब्योरा दर्शाती विवरणी	2.17	95
2.4	ग्रुप एप्रौच योजना के संबंध में स्वीकृत राशि, लक्ष्य एवं उपलब्धि का ब्योरा दर्शाती विवरणी	2.18	96

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.5	पी.डब्ल्यु.सी.एस. योजना से संबंधित स्वीकृत राशि, लक्ष्य एवं उपलब्धि को दर्शाती विवरणी	2.19	97
3.1	अधिसुचित उपज से अधिक संग्रहित केन्दु पत्ते की अतिरिक्त मात्रा के लिये भुगतान की राशि को दर्शाती विवरणी	3.1.3	98
3.2	कंडिकायें/समीक्षायें, जिसका उत्तर अप्राप्त था, की विवरणी	3.6.1	99
3.3	विभागावार लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) की विवरणी	3.6.3	100
3.4	विभागावार प्रारूप कंडिकाओं की विवरणी जिसके उत्तर अप्राप्त थे	3.6.3	101

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन सरकारी उपक्रमों और सांविधिक निगम की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंध रखता है तथा समय-समय पर संशोधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(क) के अंतर्गत झारखण्ड सरकार के समक्ष प्रस्तुति हेतु तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखापरीक्षा परिणाम अलग से प्रस्तुत किया गया है।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी उपक्रमों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है। राज्य के सांविधिक निगम की लेखापरीक्षा संबंधित विधायिका के द्वारा शासित होती है।

3. इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं जो वर्ष 2012-13 के दौरान लेखों की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आए, साथ-साथ वे जो पूर्व के वर्षो में ध्यान में आए किंतु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके। 2012-13 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझे गए, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

4. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के द्वारा भी की जाती है। सांविधिक निगम (झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड) की लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 से शासित होती है। 31 मार्च 2013 तक झारखण्ड राज्य में 14 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा.क्षे.उ.) (13 कम्पनियाँ तथा एक सांविधिक निगम) थे, जिनमें 7,773 कर्मचारी कार्यरत थे। अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार कार्यशील सा.क्षे.उ. ने 2012-13 में ₹ 2,563.83 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2013 को, 14 सा.क्षे.उ. में ₹ 6,606.39 करोड़ का निवेश था। यह 2007-08 में ₹ 3,673.29 करोड़ से 79.85 प्रतिशत बढ़ा। 2012-13 में कुल निवेश का करीब 98.14 प्रतिशत उर्जा क्षेत्र में था। सरकार ने 2012-13 में ₹ 1,764.37 करोड़ पूंजी, ऋण और अनुदान/सहाय्य के रुप में दिये।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

14 सा.क्षे.उ. में से सात सा.क्षे.उ. ने ₹ 26.35 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा चार सा.क्षे.उ. को, उनके अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार ₹ 3,352.95 करोड़ की हानि हुई। शेष तीन सा.क्षे.उ. ने अपने लेखों को प्रस्तुत नहीं किया। अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड तथा तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड ने वर्ष 2011-12 और 1999-2000 में क्रमश: ₹ 3,211.03 करोड़ एवं ₹ 140.51 करोड़ का भारी हानि वहन किया। नियत्रंक-महालेखापरीक्षक के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सा.क्षे.उ. ने ₹ 3,257.35 करोड़ की नियंत्रण योग्य हानि वहन की तथा ₹ 67.81 करोड़ का निवेश निष्फल रहा जिसे बेहतर प्रबंधन से नियंत्रित किया जा सकता था।

बकाया लेखे

सितम्बर 2013 तक सभी 14 सा.क्षे.उ. के कुल 45 लेखे बकाया थे। सा.क्षे.उ. को लेखों की तैयारी से संबंधित कार्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के साथ-साथ बकाया लेखों की निष्पादन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

लेखों की गुणवत्ता

सा.क्षे.उ. के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान बीस पूर्ण हुए लेखों में से चौदह लेखों को सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दोषपूर्ण प्रमाण पत्र दिए। सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन कम्पनियों के आंतरिक नियंत्रण पर कुछ कमजोर क्षेत्रों की ओर संकेत करते हैं।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उपस्थापन की स्थिति

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के 2001-02 से 2011-12 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अगस्त 2010 से मई 2013 के दौरान झारखण्ड सरकार को निर्गत किया गया। परन्तु कोई भी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अब तक राज्य विधान मंडल में उपस्थापित नहीं हुआ (नवम्बर 2013)। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के गैर-उपस्थापन के कारणों को झारखण्ड सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(अध्याय-I)

2. सरकारी कम्पनी से संबंधित समीक्षा

झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, उद्योग विभाग सहित, की गतिविधियों से संबंधित समीक्षा की गयी थी। हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षों के कार्यकारी सारांश निम्नवत है।

परिचय

उद्योग विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार के अधीन हस्तकरघा, रेशम कीट पालन और हस्तशिल्प निदेशालय द्वारा रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प से संबंधित विकास की गतिविधियाँ किए गए थे। इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए, झारखण्ड सरकार ने 23 अगस्त 2006 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना हस्तकरघा और हस्तशिल्प के उत्पादन, प्रसंस्करण, डिजाइन, विकास, विपणन और प्रबंधन सहायता के उद्देश्य से किया।

नियोजन

विभाग ने पंचवर्षीय योजना (2007-12) तैयार किया था, हालांकि, कोई निर्दिष्ट लक्ष्य हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए तय नहीं किए गए थे। झारखण्ड सरकार ने ₹ 303.07 करोड़ विभाग को विमुक्त किए, जिसमें से ₹ 177.51 करोड़ कम्पनी को आवंटित हुए। कुल आवंटन में से ₹ 120.77 करोड़ कम्पनी द्वारा खर्च किये गये और शेष राशि ₹ 59.38 करोड़ 31 मार्च 2013 तक अव्ययित रही। योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी का कारण सरकार से प्राप्त अनुदान का कम उपयोग रहा।

योजनाओं का क्रियान्वयन

रेशम कीट पालन

रोग मुक्त चकत्ते (डी.एफ.एल.) प्रति 40 कोकून के न्यूनतम मानदंडों के खिलाफ वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान 83.36 करोड़ कोकून का कम उत्पादन हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 84.36 करोड़ राजस्व की संभावित हानि हुई। ग्रेनेज गृह के निर्माण और रख-रखाव के लिए पूरी नकद सहायता रेशमदूत (आर.डी.) को प्रदान नहीं की गई और रेशमदूत से प्राप्य राशि के विरुद्ध समायोजित कर दी गई।

कम्पनी सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) के लिए 2008-09 से 2011-12 के दौरान ₹ 12.45 करोड़ के अनुमोदन के विरुद्ध केवल ₹ 7.32 करोड़ मार्च 2013 तक खर्च कर पायी। विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण कम्पनी ने 82 कार्यशालाओं के लक्ष्य के विरुद्ध ₹ 1.06 करोड़ के खर्च से 18 कार्यशालाओं का ही निर्माण करा पायी।

हस्तकरघा

क्लस्टर विकास योजना

भारत सरकार ने 35 क्लस्टर के विकास के लिए ₹ 19.70 करोड़ की मंजूरी दी थी जिसमें से कम्पनी को 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 16.64 करोड़ प्राप्त हुए। हालांकि, कम्पनी ने केवल ₹ 12.61 करोड़ ही खर्च कर सकी। कम्पनी ने रँगाई, बुनाई और डिजाइन प्रत्येक में 700 व्यक्तियों के प्रशिक्षण लक्ष्य की तुलना में कार्यशाला की अनुपलब्धता के कारण रँगाई में 520, बुनाई में 560 और डिजाइन में 280 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया। भूमि की अनुपलब्धता के कारण कम्पनी स्वीकृत योजना के तहत 35 सी.एफ.सी. कार्यशालाओं और 21 रँगाई घरों का निर्माण नहीं करा सकी।

ग्रुप एप्रौच योजना

झारखण्ड सरकार ने ग्रुप एप्रौच योजना के लिए ₹ 5.35 करोड़ स्वीकृत किये जिसके विरुद्ध 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 4.18 करोड़ खर्च हुए। कम्पनी ने भूमि की अनुपलब्धता के कारण 81 कार्यशालाओं के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 70 कार्यशालाओं का निर्माण किया। कार्यशाला की अनुपलब्धता के कारण 180 व्यक्तियों को बुनाई और 260 व्यक्तियों को रँगाई के लक्ष्य के विरुद्ध क्रमश: बुनाई में 140 व्यक्तियों और रँगाई में 220 व्यक्तियों को ही प्रशिक्षण दिया गया।

प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति योजना

झारखण्ड सरकार के ₹ 31.12 करोड़ की स्वीकृति के विरुद्ध कम्पनी ने 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 19.89 करोड़ खर्च किए। कम्पनी ने भूमि की अनुपलब्धता के कारण 236 कार्यशालाओं के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 30 कार्यशालाओं का निर्माण किया। कम्पनी ने कार्यशालाओं की अनुपलब्धता के कारण 4,240 बुनकरों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 3,624 बुनकरों को प्रशिक्षण दिया। 17 क्लस्टर के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला कि कम्पनी ने 2,495 बुनकरों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें से 1,215 बुनकरों को कम्पनी द्वारा बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे कार्यशालायें, कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति और मजदूरी के भुगतान में देरी के कारण काम में नहीं लगा सकी, जिसके परिणामस्वरूप करघा का भी कम उपयोग हुआ।

हस्तशिल्प

झारखण्ड सरकार ने 21,750 शिल्पियों के प्रशिक्षण के लिए 2009-10 से 2011-12 के लिए ₹ 15.08 करोड़ स्वीकृत किए, हालांकि, कम्पनी ने ₹ 13.67 करोड़ की लागत से 23,602 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया। नमूना जाँच के दौरान यह अवलोकित किया गया कि कम्पनी द्वारा कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति के कारण 11,729 प्रशिक्षित शिल्पियों में से केवल 1,734 शिल्पियों को ही काम में लगाया गया।

बिक्री और प्रचार

कम्पनी ने लागत मूल्य में 50 प्रतिशत से कम वृद्धि कर अधिकतम विक्रय मूल्य तय किया जिसके परिणामस्वरूप 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 2.72 करोड़ की कम बिक्री राशि की वसूली हुई। कम्पनी ने इम्पोरियम और फ्रैंचाइजी के माध्यम से बिक्री कर ₹ 8.33 करोड़ की हानि उठाई।

निदेशक मंडल के अनुमोदन और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना, शहरी हाट का प्रबंधन क्राफ्टेज कंसलटेंट्स को दिया गया। इसी प्रकार सिलाई का काम निदेशक मंडल के अनुमोदन के बिना क्राफ्टेज कंसलटेंट्स की अनुषंगी इकाई क्राफ्टेज एप्रैल्स को दे दिया गया। कम्पनी द्वारा उन्हें क्रमश: ₹ 9.35 करोड़ और ₹ 10 लाख का अग्रिम भुगतान बिना किसी सुरक्षा/बैंक गारंटी के दिए गए।

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी अपने परिचालन खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी और झारखण्ड सरकार पर निर्भर थी। विविध देनदार 2008-09 में ₹ 37.22 लाख से बढ़कर मार्च 2013 तक ₹ 8.30 करोड़ हो गए थे। कम्पनी ने विविध देनदारों का उम्र वार विश्लेषण नहीं किया।

सामग्री प्रबंधन

कम्पनी ने न तो कोई ए.बी.सी. विश्लेषण किया और न ही कोई अधिकतम/न्यूनतम मानक स्तर एवं पुन: आदेश स्तर नियत किया था। 2008-09 से 2011-12 के दौरान अंतिम स्टॉक निरंतर उच्च स्तर पर बना रहा जो माह के बिक्री के संदर्भ में 23 और 27 माह के बीच तक रहे।

अनुश्रवण और आंतरिक नियंत्रण

विभाग द्वारा बारीकी से योजनाओं के क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए तंत्र की व्यवस्था नहीं की थी। कम्पनी ने रिलर एवं स्पीनर द्वारा कोकून से धागा उत्पादन का अनुश्रवण करने के लिए कोई भी नियंत्रण तंत्र विकसित नहीं किया था। क्रय और उत्पादन के प्रतिवेदनों को संकलित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अनुश्रवण और प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसरण में कमी आयी। विभाग ने कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था।

आंतरिक लेखा परीक्षा बाह्य एजेंसी द्वारा किया गया, हालांकि कम्पनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल तैयार नहीं किया था।

निष्कर्ष और अनुशंसाएं

विभाग ने पंचवर्षीय योजना में भौतिक आधार पर लक्ष्य तय नहीं किए थे। कोकून का उत्पादन कम था और आर.डी. को नकद सहायता पूरी तरह प्रदान नहीं की गई थी। विभाग/कम्पनी, कार्यशालाओं के निर्माण और बुनकरों के प्रशिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। विभाग ने उपयोगिता प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। सभी इम्पोरियम और फ्रैंचाइजी दूकानें घाटा वहन कर रहे थे। फ्रैंचाइजी की नियुक्ति, शहरी हाट के प्रबंधन और अन्य कार्य निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किये बिना सौंपा गया। कम्पनी अपने परिचालन खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। कम्पनी ने कोई भी क्रय नीति और इनवेंटरी नियंत्रण तंत्र तैयार नहीं किया था। आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र में कमियाँ देखी गईं और

व्यापक एम.आई.एस. प्रणाली का अभाव था। लेखापरीक्षा अनुशंसाओं में विभाग द्वारा योजनाओं के अनुश्रवण और उपयोगिता प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए तंत्र विकसित करना, कोकून का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाना और आर.डी. को पूर्ण नकद सहायता प्रदान करना शामिल हैं। कम्पनी को भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप योजना तैयार करने, रिलर एवं स्पीनर को दिए गए कोकून से रेशम धागों के उत्पादन का अनुश्रवण, बिक्री और विपणन को बढ़ावा देने, अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए वित्तीय नियमों का पालन करने की जरूरत है। इसे वैज्ञानिक इनवेंटरी नियंत्रण पद्धति को अपनाने और विभिन्न आंतरिक नियंत्रण तंत्र और एम.आई.एस. प्रणाली को स्थापित एवं सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(अध्याय-II)

3. लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन

प्रतिवेदन में शामिल किये गये लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबंधन की कमियाँ, जिनके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई, को मुख्य रूप से दर्शाती है। इंगित की गई अनियमितताएँ मुख्यत: निम्न प्रकार की है:

नियमों, दिशा-निर्देशों, प्रक्रियाओं, संविदाओं के शर्तों एवं बंधेजों के अनुपालन न करने के कारण दो मामलों में ₹ 8.35 करोड़ की हानि।

(कंडिकाएं 3.1 एवं 3.4)

त्रुटिपूर्ण/अपर्याप्त योजना के कारण एक मामले में ₹ 0.54 करोड़ की हानि और दो मामलों में ₹ 1.56 करोड़ का निष्फल व्यय।

(कंडिकाएं 3.2 एवं 3.3)

त्रुटिपूर्ण/अपर्याप्त अनुश्रवण के कारण एक मामले में ₹ 1.16 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.5)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों का सारांश निम्नप्रकार है:

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा केन्दु पत्ती की बिक्री में कमियाँ, केन्दु पत्ती के अबिक्रीत लॉट की बिक्री के लिए संभावित उपाय तलाशने के लिए प्रभावी कदम न उठाने, अनुबंध में त्रुटिपूर्ण धारा के तहत केन्दु पत्ती के अतिरिक्त संग्रहण के लिए 50 प्रतिशत प्रोत्साहन देने से ₹ 7.55 करोड़ का अनुचित फायदा पहुँचाने, केन्दु पत्ती की जब्ती और उसके पुन: बिक्रय के लिए

अनुबंध की धारा के प्रावधानों के अनुपालन की कार्यवाही में देरी, क्रेता से संग्रह लागत प्राप्त करने के लिए कम्पनी की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप संग्रहकों को मजदूरी का भुगतान और केन्दु पत्ती के स्टाक के बीमा में अपर्याप्तता, के कारण देखी गईं।

(कंडिका - 3.1)

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आवश्यकता का उचित निर्धारण के बिना ए.सी.एस.आर. पैंथर कंडक्टर की क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 85.23 लाख की निधि अवरोधित रही जिससे ₹ 53.55 लाख ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका - 3.2)

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड ने पतरातू थर्मल पॉवर स्टेशन की बंद पड़ी इकाई संख्या-3 के जेनरेटर (स्टेटर और रोटर) की मरम्मत पर ₹ 71 लाख की राशि का निरर्थक व्यय किया जो इस इकाई के प्रस्तावित पुनर्वास के लिए कोष की उपलब्धता को सुनिश्चत किए बिना किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप जेनरेटर स्टेटर का उपयोग नहीं हो सका।

(कंडिका - 3.3)

प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना के लाभार्थी राज्यों से ₹ 1.57 करोड़ के खर्चों के अंशों का वसूली न होने के परिणामस्वरूप **झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड** पर ₹ 1.16 करोड़ के ब्याज का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

(कंडिका - 3.5)

अध्याय-I

अध्याय-I

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में राज्य की सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के सा.क्षे.उ. की स्थापना लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए की गई है।

1.2 झारखण्ड राज्य में 31 मार्च 2013 को 13[1] सरकारी कम्पनियाँ तथा एक सांविधिक निगम[2] (सभी कार्यरत) थे। कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं थी। सितम्बर 2013 तक अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार राज्य के सा.क्षे.उ. ने ₹ 2,563.86 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। राज्य के सा.क्षे.उ. ने उनके अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार कुल ₹ 3,326.60 करोड़ का घाटा वहन किया। 31 मार्च 2013 को इन्होंने कुल 7,773 कर्मचारियों को नियोजित किया था।

1.3 राज्य के सा.क्षे.उ. में नौ विभागीय उपक्रम (वि.उ.), जो वाणिज्यिक क्रियाकलापों को कार्यान्वित करते हैं किंतु वे सरकारी विभागो के अंग हैं, तथा एक स्वायत्त संस्थान, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा.रा.वि.नि.आ.), जिसका एकमात्र लेखापरीक्षक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हैं, शामिल नहीं हैं।

---

[1] झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.डी.सी.), झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको), झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जिडको), झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.), ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (जी.आर.डी.ए.), झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट), झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.डी.सी.), तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल.), कर्णपूरा ऊर्जा लिमिटेड (के.ई.एल.), झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जे.टी.डी.सी.), झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (जे.एस.बी.सी.एल.), झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल.) और झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.एफ.डी.सी.)।

[2] झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.)।

1.4 वर्ष 2012-13 के दौरान एक[3] सा.क्षे.उ. स्थापित हुआ और कोई भी सा.क्षे.उ. बन्द नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.5 सरकारी कम्पनियों का लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार अधिशासित होता है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसका प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों द्वारा धारित हो। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी सम्मिलित होती है।

1.6 राज्य के सरकारी कम्पनियों के लेखों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के प्रावधानों के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा की जाती है।

1.7 सांविधिक निगम (झा.रा.वि.बो.) का लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 के द्वारा अधिशासित है तथा इसका सी.ए.जी. एक मात्र लेखापरीक्षक है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.8 31 मार्च 2013 को 14 सा.क्षे.उ. (एक सांविधिक निगम सहित) में ₹ 6,606.39 करोड़ का कुल निवेश था जैसा कि ***तालिका - 1.1*** में वर्णित है।

तालिका - 1.1

(₹ करोड़ में)

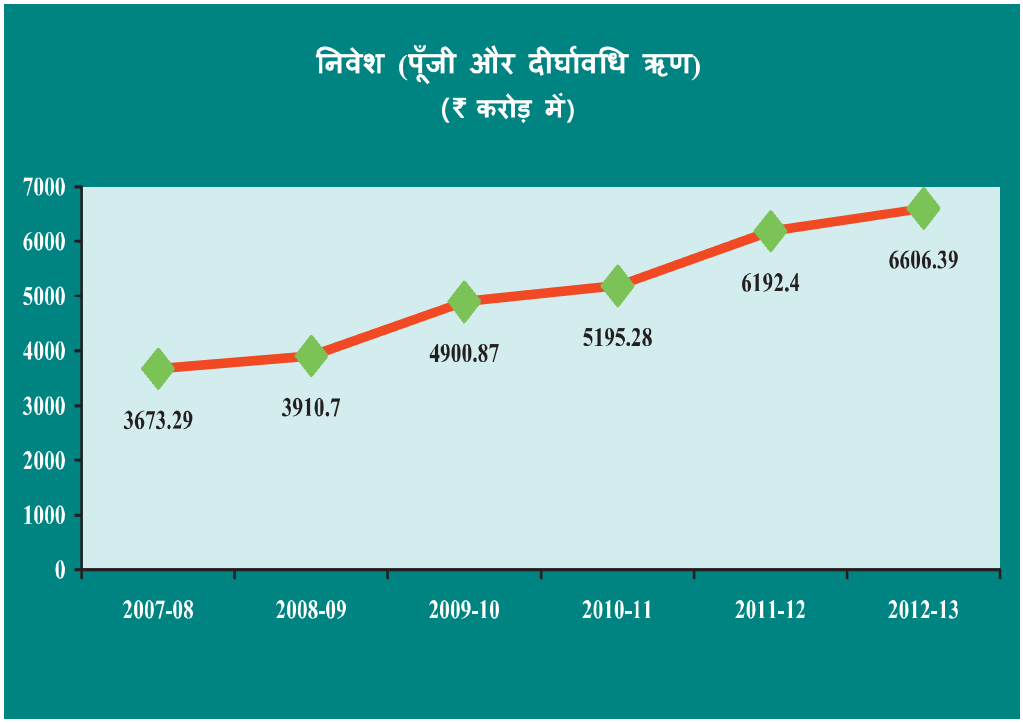
सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुल योग
पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	
171.10	734.57	905.67	-	5700.72	5700.72	6606.39

[3] झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.एफ.डी.सी.)

राज्य के सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश के सारांशीकृत स्थिति का ब्यौरा ***परिशिष्ट-1.1*** में दिये गये हैं।

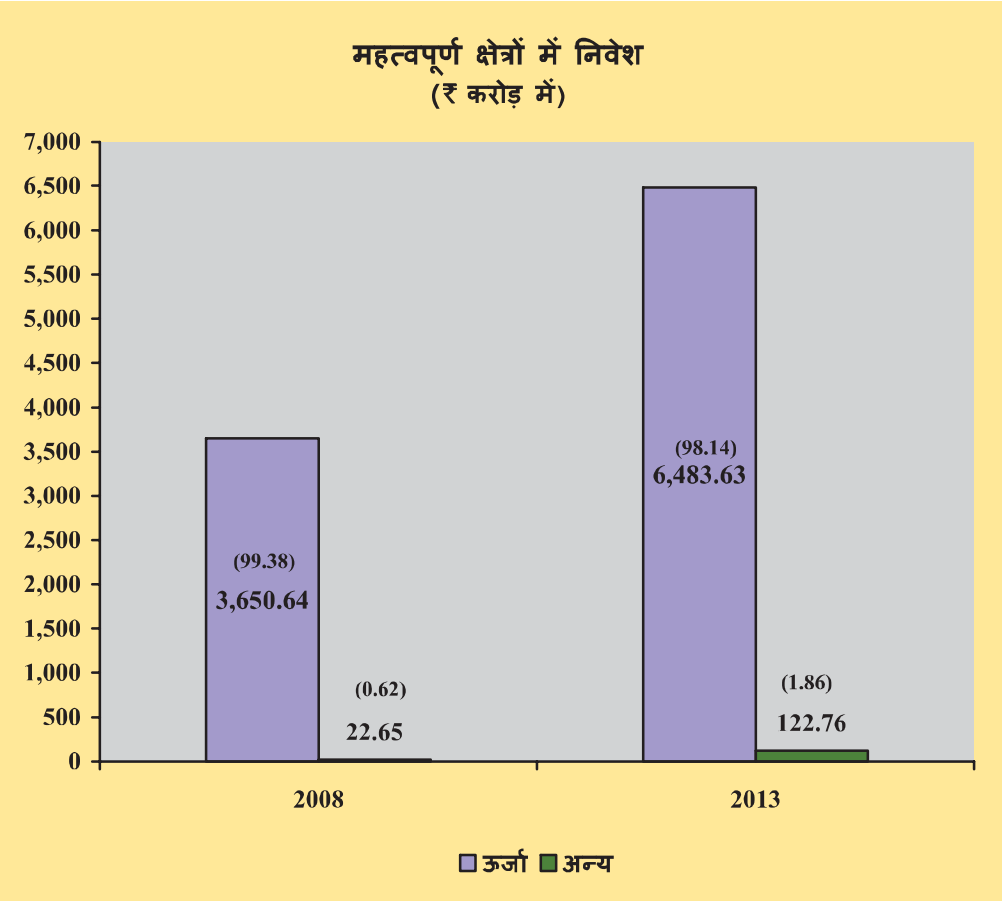
1.9 31 मार्च 2013 को सा.क्षे.उ. में कुल निवेश का 2.59 प्रतिशत पूँजी में और 97.41 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों में था। सा.क्षे.उ. में निवेश 79.85 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2007-08 में ₹ 3,673.29 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹ 6,606.39 करोड़ हो गया, जैसा कि ***रेखाचित्र - 1.1*** में दिखाया गया है:

रेखाचित्र - 1.1



1.10 31 मार्च 2008 तथा 31 मार्च 2013 के अंत तक विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनके प्रतिशत ***रेखाचित्र - 1.2*** में प्रकट किये गये हैं।

रेखाचित्र - 1.2



(कोष्ठक में आंकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं)

सा.क्षे.उ. में निवेश का जोर मुख्यतः विद्युत क्षेत्र में था। पिछले छः वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश बढ़ते प्रवृति को दर्शाता है। यह वर्ष 2007-08 में ₹ 3,650.64 करोड़ से 77.60 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 6,483.63 करोड़ हो गया जो सरकार एवं अन्य निकायों के द्वारा मुख्यतः झा.रा.वि.बो. और टी.वी.एन.एल. को दिये गये ऋण के कारण हुआ।

अंश पूँजी, अनुदान/सहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण से संबंधित बजटीय जावक

1.11 राज्य के सा.क्षे.उ. के संबंध में मार्च 2013 के अंत में अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का विस्तृत ब्यौरा ***परिशिष्ट-1.2*** में दिये गये हैं।

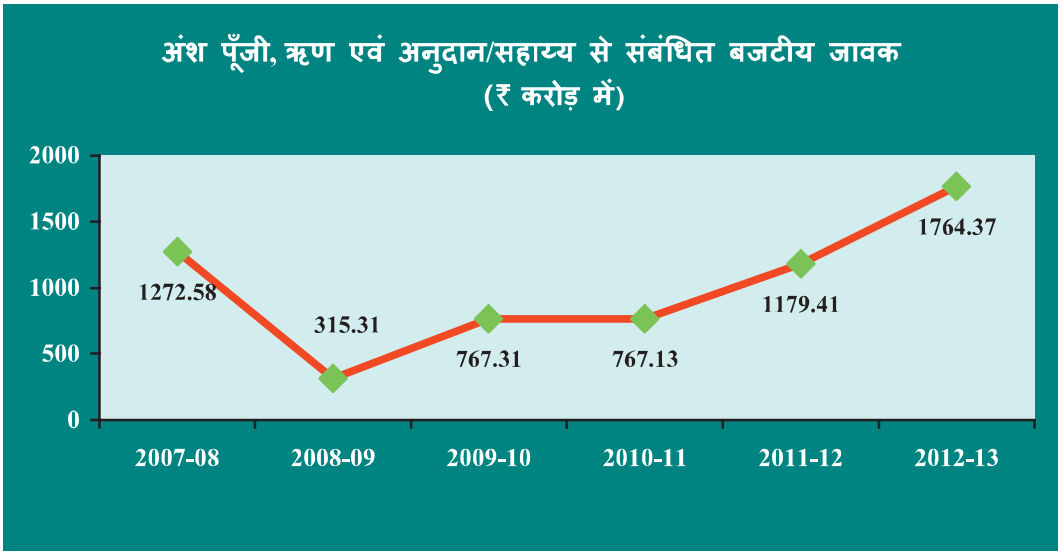
वर्ष 2012-13 को समाप्त हुये तीन वर्षों का अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित जावक का सारांशीकृत ब्यौरा ***तालिका - 1.2*** में दिया गया है।

तालिका - 1.2

क्र.सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		सा.क्षे.उ. की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सा.क्षे.उ. की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सा.क्षे.उ. की सं.[4]	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से अंश पूँजी जावक	3	3.00	4	20.50	3	15.00
2.	बजट से दिये गये ऋण	1	313.55	2	408.91	2	561.70
3.	अनुदान/सहाय्य प्राप्ति	3	450.58	1	750.00	3	1187.67
	कुल जावक		**767.13**		**1179.41**		**1764.37**

1.12 पिछले छः वर्षों में अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का विस्तृत ब्यौरा ***रेखाचित्र - 1.3*** में दर्शाये गये हैं।

रेखाचित्र - 1.3



झा.रा.वि.बो. को ऋण (₹ 541.70 करोड़) एवं अनुदान (₹ 1,107.25 करोड़) और जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल. में अनुदान (₹ 75.00 करोड़) के बजटीय सहायता देने के कारण, बजटीय जावक वर्ष 2011-12 में ₹ 1,179.41 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 1,764.37 करोड़ हो गया।

[4] सात सा.क्षे.उ. का कुल जावक (जी.आर.डी.ए., झारक्राफ्ट, जे.टी.डी.सी., जे.एस.बी.सी.एल., जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल., झालको और झा.रा.वि.बो.।

वित्त लेखों के साथ समाधान

1.13 राज्य के सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति से संबंधित आँकड़े राज्य के वित्त लेखों में अंकित आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो संबंधित सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग द्वारा अंतर का समाधान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2013 तक की स्थिति ***तालिका - 1.3*** में दी गई है:

तालिका - 1.3

(₹ करोड़ में)

संबंधित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
अंश पूँजी	23.30	171.05	147.75
ऋण	7121.41	6198.17	923.24

1.14 हमने पाया कि दस[5] सा.क्षे.उ. के आँकड़ों में अंतर पाया गया और इन अंतरों का समाधान 2001-02 से ही लम्बित था। यद्यपि वित्त लेखों में दर्ज और सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि के अंतर को पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था, राज्य सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

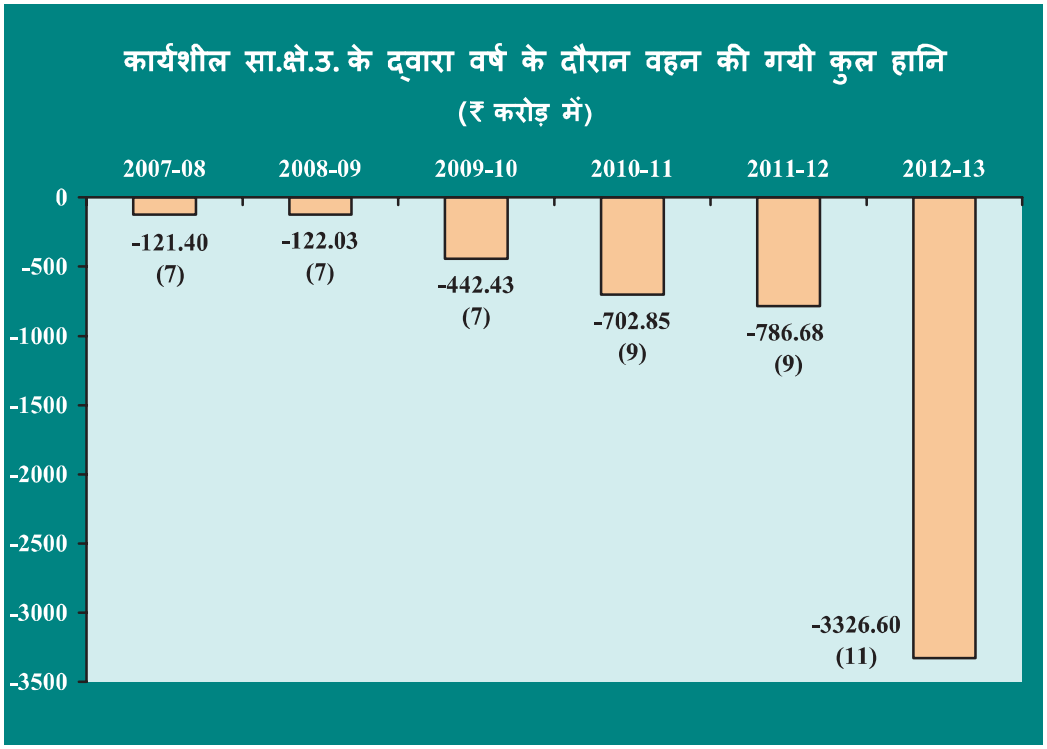
सा.क्षे.उ. का निष्पादन

1.15 सा.क्षे.उ. के वित्तीय परिणामों और सांविधिक निगम के वित्तीय स्थिति तथा कार्यपरिणामों का विस्तृत ब्यौरा क्रमशः ***परिशिष्ट-1.3, 1.4, एवं 1.5*** में दिये गये है।

1.16 2007-08 से 2012-13 के दौरान राज्य के सा.क्षे.उ. के द्वारा उनके अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार वहन किये गये कुल हानि (शुद्ध) ₹ 121.40 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,326.60 करोड़ हो गयी है जैसा की ***रेखाचित्र - 1.4*** में दिया गया है:

[5] टी.वी.एन.एल., जिडको, जे.टी.डी.सी., झारक्राफ्ट, जी.आर.डी.ए., जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल., झालको, जे.एस.बी.सी.एल., जे.एस.एम.एफ.डी.सी. और झा.रा.वि.बो.।

रेखाचित्र - 1.4



(कोष्ठक में आँकड़े अद्यतन अंकेक्षित लेखों के आधार पर संबंधित वर्ष में कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या दर्शाते हैं)

अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार 14 सा.क्षे.उ. में से सात[6] सा.क्षे.उ. ने ₹ 26.35 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जबकि चार[7] सा.क्षे.उ. ने ₹ 3,352.95 करोड़ की कुल हानि वहन की। सितम्बर 2013 तक शेष तीन[8] सा.क्षे.उ. ने अपना कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया। 2011-12 और 1999-2000 के अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार क्रमशः झा.रा.वि.बो. (₹ 3,211.03 करोड़) और टी.वी.एन.एल. (₹ 140.51 करोड़) द्वारा भारी हानि उठायी गयी।

शुद्ध हानि 2011-12 में ₹ 786.68 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 3,326.60 करोड़ हो गया जो मुख्य रुप से झा.रा.वि.बो. के हानि 2010-11 में ₹ 722.82 करोड़ से 2011-12 में ₹ 3,211.03 करोड़ होने के कारण हुई।

---

6 जे.एस.एफ.डी.सी., जे.पी.एच.सी.एल., झारक्राफ्ट,, जे.एस.एम.डी.सी., जिडको, जी.आर.डी.ए., और जे.टी.डी.सी.।

7 झालको, जे.एस.बी.सी.एल., टी.वी.एन.एल. और झा.रा.वि.बो.।

8 जे.एस.एम.एफ.डी.सी., के.ई.एल. और जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल.।

1.17 सी.ए.जी. के तीन साल के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सा.क्षे.उ. ने ₹ 3,257.35 करोड़ की नियंत्रणीय हानियाँ वहन की एवं ₹ 67.81 करोड़ का निरर्थक निवेश किया जो अच्छे प्रबंधन के द्वारा नियंत्रणीय थी जैसा कि ***तालिका - 1.4*** में दिया गया है।

तालिका - 1.4

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
शुद्ध हानि	702.85	786.68	3326.60	4816.13
सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा के अनुसार नियंत्रणीय हानियाँ	2650.89	487.27	119.19	3257.35
निरर्थक निवेश	46.17	10.61	11.03	67.81

1.18 राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति प्रतिपादित नहीं किया था जिसके अंतर्गत सभी सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रदत्त पूँजी पर न्यूनतम वापसी देने की आवश्यकता हो। अपने अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार सात[9] सा.क्षे.उ. ने ₹ 26.35 करोड़ का संचयी लाभ अर्जित किया लेकिन कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

1.19 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619-बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं का समापन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः महीने के भीतर करना होता है। उसी तरह सांविधिक निगम के मामले में लेखों का समापन, लेखापरीक्षा और विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार होता है। ***तालिका -1.5*** कार्यरत सा.क्षे.उ. के विवरण तथा उनके लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति (सितम्बर 2013) को दर्शाता है।

[9] जे.एस.एफ.डी.सी., जे.पी.एच.सी.एल., झारक्राफ्ट,, जे.एस.एम.डी.सी., जिडको, जी.आर.डी.ए., और जे.टी.डी.सी.।

तालिका - 1.5

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या	10	11	12	13	14
2.	वर्ष के दौरान अंतिमीकृत लेखों की संख्या	7	14	12	8	20
3.	बकाया लेखे की संख्या	48	46	46	52	45*
4.	प्रत्येक सा.क्षे.उ. का औसत बकाया (3/1)	4.80	4.18	3.83	4.00	3.21
5.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लेखों का अंतिमीकरण होना बाकी था	10	11	12	13	14
6.	बकाये की अवधि (वर्ष)	1 से 15	1 से 16	1 से 17	1 से 16	1 से 13

1.20 2008-09 में दस सा.क्षे.उ. के संदर्भ में बकाये लेखों की संख्या वर्षों के दौरान 48 से घटकर 2012-13 में 14 सा.क्षे.उ. के संदर्भ में 45 हो गयी थी।

1.21 राज्य सरकार ने एक सांविधिक निगम सहित आठ सा.क्षे.उ. में, ₹ 2,171.33 करोड़ (अंश पूँजी: ₹ 27.00 करोड़, ऋण: ₹ 662.66 करोड़, अनुदान: ₹ 1,481.67 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया जिनमें लेखें अंतिमीकृत नहीं हुये हैं जिसका विवरण ***परिशिष्ट-1.6*** में दिया गया है। लेखों और उनके अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गए निवेश और व्यय का लेखा-जोखा उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था उसकी प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार, सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य के विधायिका के संवीक्षा से वंचित रहा। इसके अतिरिक्त, लेखाओं के अंतिमीकरण में विलंब से कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ सार्वजनिक कोष की धोखाधड़ी एवं बर्बादी के जोखिम की सम्भावना हो सकती है।

* जे.एस.बी.सी.एल. ने 26.11.2010 से 31.03.2012 के अवधि के लिए एक लेखे बनाये जिसपर असमीक्षा प्रमाणपत्र निर्गत किया गया, अत: 2010-11 के लेखे कुल बकाया लेखों से कम हो गया।

1.22 प्रशासनिक विभागों को इन इकाईयों के क्रियाकलापों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है और यह सुनिश्चित करना है कि ये सा.क्षे.उ. अपने लेखों का अंतिमीकरण एवं उनका अंगीकरण नियत अवधि में कर लिए हैं। यद्यपि, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं अधिकारियों को बकाया लेखों के अंतिमीकरण के तथ्य को आकृष्ट किया गया, पर कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप इन सा.क्षे.उ. के निवल परिसंपत्तियों का निर्धारण लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। सितंबर 2013 में प्रधान महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग का ध्यान इन लेखों के अंतिमीकरण में बकाया के तरफ आकृष्ट किया गया था एवं बकाये लेखों को समयबद्ध तरीके से शीघ्र निष्पादन की आवश्यकता को उजागर किया था।

1.23 उपर्युक्त बकाये की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को इसका अनुश्रवण एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लेखों का अंतिमीकरण समय पर सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.24 वर्ष 2012-13 के दौरान नौ कम्पनियों ने अपने उन्नीस लेखाओं (बकाये लेखों सहित) को प्रधान महालेखाकार को 30 सितम्बर 2013 तक अग्रसारित किया। इसमें से छः कम्पनियों[10] के सोलह लेखाओं का पूरक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने पाँच लेखों पर दोष-रहित प्रमाण पत्र एवं चौदह लेखों पर दोष-पूर्ण प्रमाण पत्र दिये। सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और सी.ए.जी. के पूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इंगित करते हैं कि लेखाओं के रख-रखाव की गुणवत्ता में वृहद रूप से सुधार की जरूरत है। सी.ए.जी. के टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विस्तृत विवरण ***तालिका - 1.6*** में दिये गये है।

[10] झारक्राफ्ट, जे.एस.एम..डी.सी-2, जिडको-2, टी.वी.एन.एल.-4, जी.आर.डी.ए.-6 और झालको।

तालिका - 1.6

क्र.सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में वृद्धि	-	-	1	0.23	1	0.01
2.	लाभ में कमी	2	7.70	3	3.52	3	5.29
3.	हानि में वृद्धि	-	-	-	-	1	0.08
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	1	0.36
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	-	-	-	-	3	-

1.25 कम्पनियों के लेखों से संबंधित सी.ए.जी की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी है:

झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड
वर्ष 2011-12 के लेखे

निम्न कारणों से वर्ष का लाभ ₹ 15.17 लाख अधिक आकलित किया गया-

- योजना के क्रियान्वयन पर किए गए व्यय के अनुपात में ₹ 13.10 लाख का पर्यवेक्षण शुल्क का लेखांकन न करना;
- मार्च 2012 के महीने के लिये ₹ 1.13 लाख के विद्युत व्यय का प्रावधान न करना; और
- ₹ 0.94 लाख के बकाया वेतन का प्रावधान न करना

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड
वर्ष 2006-07 के लेखे

सिकनी कोयला खदान के खदान बंदी से संबंधित लागत का प्रावधान न करने के कारण वर्ष का लाभ ₹ 2.48 करोड़ अधिक आकलित किया गया।

वर्ष 2007-08 के लेखे

निम्न कारणों से वर्ष का लाभ ₹ 2.65 करोड़ से अधिक आकलित किया गया-

- सिकनी कोयला खदान के खदान बंदी से संबंधित लागत ₹ 2.61 करोड़ का प्रावधान नहीं किया जाना;
- सिकनी कोयला खदान मे उपभोग किए गए विस्फोटक के लिए ₹ 14.68 लाख का प्रावधान नहीं किया जाना; और
- मार्च 2008 के सिकनी कोयला खदान के संवेदक से वसूलीय विस्फोटक के लागत ₹ 10.27 लाख का प्रावधान न करना।

झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्‌वह सिंचाई निगम लिमिटेड

वर्ष 2009-10 के लेखे

निम्न कारणो से वर्ष की हानि ₹ 36.28 लाख से अधिक आकलित किया गया-

- 31.03.2012 को मियादी जमा पर प्रोदभूत ब्याज ₹ 38.68 लाख का लेखांकन न करना; और
- वर्ष 2009-10 के दौरान अंश दायी भविष्य निधि पर कर्मचारियों तथा कम्पनी द्‌वारा दिए गए अंशदान पर ₹ 2.40 लाख के ब्याज का प्रावधान न करना।

झारखण्ड राज्य विद्‌युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.) के वार्षिक लेखे

1.26 वर्ष के दौरान, 2011-12 के वार्षिक लेखे झा.रा.वि.बो. जिसका सी.ए.जी. एकल लेखापरीक्षक है, से प्राप्त किया गया जिस पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किया गया था। सी.ए.जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन यह इंगित करता है कि खातों के रख रखाव की गुणवत्ता में वृहद सुधार की जरुरत है। झा.रा.वि.बो. के लेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दिए गए है:

निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 26.22 करोड़ कम आकलित किया गया-

- सामान्य भविष्य निधि की शेष राशि पर ₹ 18.55 करोड़ का ब्याज का कम प्रावधान;
- वर्ष 2011-12 के दौरान डिपोजिट कार्य के लिए पर्यवेक्षन शुल्क के रूप में प्राप्त अग्रिम राशि ₹ 1.76 करोड़ का लेखांकन आय

के रुप में किया गया, जबकि 31.03.2012 तक वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ था;

- 31.03.2012 तक बैंक में मियादी/फैलेक्सी जमा के रूप में निवेश पर प्रोदभूत ब्याज ₹ 5.23 करोड़ का लेखांकन न करना;
- कोयले के उपभोग की लागत ₹ 3.89 करोड़ का कम लेखांकन तथा अंतिम स्टाक का ₹ 0.28 करोड़ का कम आंकलन;
- वर्ष 2012-13 से संबंधित टैरिफ याचिका शुल्क ₹ 35.00 लाख का वर्ष 2011-12 में लेखांकन;
- लाइन एवं केवल नेटवर्क पर कम दर से ₹ 1.70 करोड़ ह्रास का कम लेखांकन; और
- बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज एवं वित्त शुल्क का ₹ 6.18 करोड़ कम आंकलन।

1.27 झा.रा.वि.बो. के लेखों पर सी.ए.जी. की टिप्पणियों का कुल मौद्रिक मूल्य ***तालिका - 1.7*** में दर्शायी गयी है।

तालिका - 1.7

क्र.सं.	विवरण	2012-13	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	1	5.58
2.	हानि में वृद्धि	1	31.80
कुल		**1**	

आंतरिक नियंत्रण पर टिप्पणियाँ

1.28 सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउंटेंट) को सी.ए.जी. के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ए) के अंतर्गत जारी किये गये दिशा निर्देशों के अंतर्गत उनके द्वारा लेखापरीक्षित की गई कम्पनियों के आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा उन क्षेत्रों की पहचान करना होता है जहाँ सुधार की आवश्यकता थी। वर्ष 2012-13 के दौरान आठ[11] कम्पनियों के अंतिमीकृत लेखों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण में

[11] झालको, जिडको, जे.पी.एच.सी.एल., जी.आर.डी.ए., झारक्राफ्ट, जे.एस.एम.डी.सी., टी.वी.एन.एल. तथा जे.एस.बी.सी.एल.

संभावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा किये गये मुख्य टिप्पणियों का सारांश सोदाहरण ***तालिका - 1.8*** में दिये गये है।

तालिका - 1.8

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जहाँ अनुशंसाये की गई थी	कम्पनियों का क्रम संख्या परिशिष्ट-1.3 के अनुसार
1.	भंडार एवं पूर्जे की न्यूनतम/अधिकतम सीमा का तय न होना	3	क-08, क-06, क-07
2.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यापार के आकार के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का अभाव	3	क-03, क-05, क-11
3.	अचल परिसम्पत्तियों की पंजिका, जो पूर्ण विवरण जैसे मात्रात्मक विवरण तथा अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति दर्शाती हो, का संधारण नहीं होना	3	क-02, क-04, क-08

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

1.29 2012-13 में लेखापरीक्षा के दौरान में ₹ 71.06 लाख की वसूली हेतु झा.रा.वि.बो. प्रबंधन को इंगित किये गये थे, जिनमें से ₹ 4.05 लाख के मामले झा.रा.वि.बो. द्वारा स्वीकार किये गये, अपितु अभी तक झा.रा.वि.बो. द्वारा वसूली नहीं की गयी थी (अक्टूबर 2013)।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प्र.) को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.30 ***तालिका - 1.9*** झा.रा.वि.बो. के लेखों पर सी.ए.जी. द्वारा जारी किये गये पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प्र.) को विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दिखलाती है।

तालिका - 1.9

क्र.सं.	सांविधिक निगम	वर्ष जहाँ तक पृ.ले.प्र. विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की गयी	वर्ष जहाँ तक पृ.ले.प्र. विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गयी		
			पृ.ले.प्र. का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	विलम्ब का कारण
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	--	2001-02	20.08.2010	पृ.ले.प्र. को उपस्थापित नहीं करने का कारण सरकार ने नहीं बताया।
			2002-03	07.02.2011	
			2003-04	07.03.2011	
			2004-05	07.06.2011	
			2005-06	09.11.2011	
			2006-07	15.12.2011	
			2007-08	31.01.2012	
			2008-09	30.03.2012	
			2009-10	30.03.2012	
			2010-11	26.04.2012	
			2011-12	22.05.2013	

पृ.ले.प्र. को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर विधायिकी नियंत्रण कमजोर होता है एवं बाद में वित्तीय जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधान महालेखाकार द्वारा इस विषय को झारखंड सरकार के मुख्य सचिव तथा वित्त एवं विद्युत विभाग के विभागीय सचिवों के ध्यान में लाया गया (सितंबर/नवंबर 2013)। परंतु अभी तक उत्तर अप्राप्त है।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.31 झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा.रा.वि.नि.आ.) का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के तहत अप्रैल 2003 में विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने, विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण के संबंध में सुझाव देने और लाईसेंस निर्गत करने हेतु किया गया है। 2012-13 के दौरान झा.रा.वि.नि.आ. ने वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं पर सात एवं अन्य मामलों में 16 आदेश जारी किये।

1.32 चिन्हित लक्ष्यों के साथ विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार के मध्य एक संयुक्त वचनबद्धता के रुप में समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर अप्रैल 2001 को किया गया। महत्वपूर्ण लक्ष्यों के संबंध में अभी तक हुई उपलब्धि की प्रगति को ***तालिका - 1.10*** में बतलाया गया है।

तालिका - 1.10

क्र.सं.	लक्ष्य		उपलब्धि
1.	बिक्री हेतु प्राप्त विद्युत में से तंत्र हानि को कम कर 18 प्रतिशत तक लाना		वर्ष 2012-13 में संचरण एवं वितरण हानि 33.46 प्रतिशत थी जो 18 प्रतिशत के लक्ष्य से बहुत ज्यादा थी।
2.	100 प्रतिशत उपभोक्ताओं का मीटरीकरण	एकल चरण (शहरी)	100.00 प्रतिशत
		एकल चरण (ग्रामीण)	79.02 प्रतिशत
		निम्न विभव (एल.टी.)	99.86 प्रतिशत
		उच्च विभव (एच.टी.)	100.00 प्रतिशत

अध्याय-II

अध्याय-II

2. सरकारी कम्पनी से संबंधित समीक्षा

झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, उद्योग विभाग सहित, की गतिविधियों की समीक्षा

कार्यकारी सारांश

परिचय

उद्योग विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार के अधीन हस्तकरघा, रेशम कीट पालन और हस्तशिल्प निदेशालय द्वारा रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प से संबंधित विकास की गतिविधियाँ किए गए थे। इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए, झारखण्ड सरकार ने 23 अगस्त 2006 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना हस्तकरघा और हस्तशिल्प के उत्पादन, प्रसंस्करण, डिजाइन, विकास, विपणन और प्रबंधन सहायता के उद्देश्य से किया।

नियोजन

विभाग ने पंचवर्षीय योजना (2007-12) तैयार किया था, हालांकि, कोई निर्दिष्ट लक्ष्य हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए तय नहीं किए गए थे। झारखण्ड सरकार ने ₹ 303.07 करोड़ विभाग को विमुक्त किए, जिसमें से ₹ 177.51 करोड़ कम्पनी को आवंटित हुए। कुल आवंटन में से ₹ 120.77 करोड़ कम्पनी द्वारा खर्च किये गये और शेष राशि ₹ 59.38 करोड़ 31 मार्च 2013 तक अव्ययित रही। योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी का कारण सरकार से प्राप्त अनुदान का कम उपयोग रहा।

योजनाओं का क्रियान्वयन

रेशम कीट पालन

रोग मुक्त चकत्ते (डी.एफ.एल.) प्रति 40 कोकून के न्यूनतम मानदंडों के खिलाफ वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान 83.36 करोड़ कोकून का कम उत्पादन हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 84.36 करोड़ राजस्व की संभावित हानि हुई। ग्रेनेज गृह के निर्माण और रख-रखाव के लिए पूरी नकद सहायता रेशमदूत (आर.डी.) को प्रदान नहीं की गई और रेशमदूत से प्राप्य राशि के विरूद्ध समायोजित कर दी गई।

कम्पनी सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) के लिए 2008-09 से 2011-12 के दौरान ₹ 12.45 करोड़ के अनुमोदन के विरूद्ध केवल ₹ 7.32 करोड़ मार्च 2013 तक खर्च कर पायी। विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण कम्पनी ने 82 कार्यशालाओं के लक्ष्य के विरूद्ध ₹ 1.06 करोड़ के खर्च से 18 कार्यशालाओं का ही निर्माण करा पायी।

हस्तकरघा

क्लस्टर विकास योजना

भारत सरकार ने 35 क्लस्टर के विकास के लिए ₹ 19.70 करोड़ की मंजूरी दी थी जिसमें से कम्पनी को 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 16.64 करोड़ प्राप्त हुए। हालांकि, कम्पनी ने केवल ₹ 12.61 करोड़ ही खर्च कर सकी। कम्पनी ने रँगाई, बुनाई और डिजाइन प्रत्येक में 700 व्यक्तियों की प्रशिक्षण लक्ष्य की तुलना में कार्यशाला की अनुपलब्धता के कारण रँगाई में 520, बुनाई में 560 और डिजाइन में 280 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया। भूमि की अनुपलब्धता के कारण कम्पनी स्वीकृत योजना के तहत 35 सी.एफ.सी. कार्यशालाओं और 21 रँगाई घरों का निर्माण नहीं करा सकी।

ग्रुप एप्रौच योजना

झारखण्ड सरकार ने ग्रुप एप्रौच योजना के लिए ₹ 5.35 करोड़ स्वीकृत किये जिसके विरूद्ध 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 4.18 करोड़ खर्च हुए। कम्पनी ने भूमि की अनुपलब्धता के कारण 81 कार्यशालाओं के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 70 कार्यशालाओं का निर्माण किया। कार्यशाला की अनुपलब्धता के कारण 180 व्यक्तियों को बुनाई और 260 व्यक्तियों को रँगाई के लक्ष्य के विरूद्ध क्रमश: बुनाई में 140 व्यक्तियों और रँगाई में 220 व्यक्तियों को ही प्रशिक्षण दिया गया।

प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति योजना

झारखण्ड सरकार के ₹ 31.12 करोड़ की स्वीकृति के विरूद्ध कम्पनी ने 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 19.89 करोड़ खर्च किए। कम्पनी ने भूमि की अनुपलब्धता के कारण 236 कार्यशालाओं के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 30 कार्यशालाओं का निर्माण किया। कम्पनी ने कार्यशालाओं की अनुपलब्धता के कारण 4,240 बुनकरों के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 3,624 बुनकरों को प्रशिक्षण दिया। 17 क्लस्टर के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला कि कम्पनी ने 2,495 बुनकरों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें से 1,215 बुनकरों को कम्पनी द्वारा बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे कार्यशालायें, कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति और मजदूरी के भुगतान में देरी के कारण काम में नहीं लगा सकी, जिसके परिणामस्वरूप करघा का भी कम उपयोग हुआ।

हस्तशिल्प

झारखण्ड सरकार ने 21,750 शिल्पियों के प्रशिक्षण के लिए 2009-10 से 2011-12 के लिए ₹ 15.08 करोड़ स्वीकृत किए, हालांकि, कम्पनी ने ₹ 13.67 करोड़ की लागत से 23,602 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया। नमूना जाँच के दौरान यह अवलोकित किया गया कि कम्पनी द्वारा कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति के कारण 11,729 प्रशिक्षित शिल्पियों में से केवल 1,734 शिल्पियों को ही काम में लगाया गया।

बिक्री और प्रचार

कम्पनी ने लागत मूल्य में 50 प्रतिशत से कम वृद्धि कर अधिकतम विक्रय मूल्य तय किया जिसके परिणामस्वरूप 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 2.72 करोड़ की कम बिक्री राशि की वसूली हुई। कम्पनी ने इम्पोरियम और फ्रैंचाइजी के माध्यम से बिक्री कर ₹ 8.33 करोड़ की हानि उठाई।

निदेशक मंडल के अनुमोदन और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना, शहरी हाट का प्रबंधन क्राफ्टेज कंसलटेंट्स को दिया गया। इसी प्रकार सिलाई का काम निदेशक मंडल के अनुमोदन के बिना क्राफ्टेज कंसलटेंट्स की अनुषंगी इकाई क्राफ्टेज एप्रैल्स को दे दिया गया। कम्पनी द्वारा उन्हें क्रमश: ₹ 9.35 करोड़ और ₹ 10 लाख का अग्रिम भुगतान बिना किसी सुरक्षा/बैंक गारंटी के दिए गए।

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी अपने परिचालन खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी और झारखण्ड सरकार पर निर्भर थी। विविध देनदार 2008-09 में ₹ 37.22 लाख से बढ़कर मार्च 2013 तक ₹ 8.30 करोड़ हो गए थे। कम्पनी ने विविध देनदारों का उम्र वार विश्लेषण नहीं किया।

सामग्री प्रबंधन

कम्पनी ने न तो कोई ए.बी.सी. विश्लेषण किया और न ही कोई अधिकतम/न्यूनतम मानक स्तर एवं पुन: आदेश स्तर नियत किया था। 2008-09 से 2011-12 के दौरान अंतिम स्टॉक निरंतर उच्च स्तर पर बना रहा जो माह के बिक्री के संदर्भ में 23 और 27 माह के बीच तक रहे।

अनुश्रवण और आंतरिक नियंत्रण

विभाग द्वारा बारीकी से योजनाओं के क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए तंत्र की व्यवस्था नहीं की थी। कम्पनी ने रिलर एवं स्पीनर द्वारा कोकून से धागा उत्पादन का अनुश्रवण करने के लिए कोई भी नियंत्रण तंत्र विकसित नहीं किया था। क्रय और उत्पादन के प्रतिवेदनों को संकलित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अनुश्रवण और प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसरण में कमी आयी। विभाग ने कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था।

आंतरिक लेखा परीक्षा बाह्य एजेंसी द्वारा किया गया, हालांकि कम्पनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल तैयार नहीं किया था।

निष्कर्ष और अनुशंसाएं

विभाग ने पंचवर्षीय योजना में भौतिक आधार पर लक्ष्य तय नहीं किए थे। कोकून का उत्पादन कम था और आर.डी. को नकद सहायता पूरी तरह प्रदान नहीं की गई थी। विभाग/कम्पनी, कार्यशालाओं के निर्माण और बुनकरों के प्रशिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। विभाग ने उपयोगिता प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। सभी इम्पोरियम और फ्रैंचाइजी दूकानें घाटा वहन कर रहे थे। फ्रैंचाइजी की नियुक्ति, शहरी हाट के प्रबंधन और अन्य कार्य निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किये बिना सौंपा गया। कम्पनी अपने परिचालन खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। कम्पनी ने कोई भी क्रय नीति और इनवेंटरी नियंत्रण तंत्र तैयार नहीं किया था। आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र में कमियाँ देखी गईं और व्यापक एम.आई.एस. प्रणाली का अभाव था। लेखापरीक्षा अनुशंसाओं में विभाग द्वारा योजनाओं के अनुश्रवण और उपयोगिता प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए तंत्र विकसित करना, कोकून का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाना और आर.डी. को पूर्ण नकद सहायता प्रदान करना शामिल हैं। कम्पनी को भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप योजना तैयार करने, रिलर एवं

स्पीनर को दिए गए कोकून से रेशम धागों के उत्पादन का अनुश्रवण, बिक्री और विपणन को बढ़ावा देने, अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए वित्तीय नियमों का पालन करने की जरूरत है। इसे वैज्ञानिक इनवेंटरी नियंत्रण पद्धति को अपनाने और विभिन्न आंतरिक नियंत्रण तंत्र और एम.आई.एस. प्रणाली को स्थापित एवं सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

परिचय

2.1 उद्योग विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार के अधिन हस्तकरघा, रेशम कीट पालन और हस्तशिल्प निदेशालय द्वारा रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प से संबंधित विकास की गतिविधियाँ की गयी थी। झारखण्ड सरकार का उद्देश्य रिलिंग, स्पीनिंग और बुनाई केन्द्रों के स्थापना द्वारा रेशम कीट पालन, हस्तकरघा तथा हस्तशिल्प के क्षेत्र में कौशल विकसित करना एवं इस प्रक्षेत्र का विस्तार करना था। इस प्रक्षेत्र में विशेष ध्यान देने के लिए झारखण्ड सरकार ने 23 अगस्त 2006 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना की। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य हस्तकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, डिजाइन, विकास इत्यादि का व्यापार करना और राज्य में हस्तकरघा, रेशम, हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योगों की स्थापना में वित्त पोषण, वित्तीय अनुदान, तकनीकी सहायता, विपणन एवं प्रबंधन सहायता के द्वारा स्थापना, बढ़ावा, मदद, सहायता करना था। इसमें सहकारी समितियों एवं शिल्पियों के माध्यम से उत्पादन तथा हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा के उत्पादों के प्रदर्शनी और विपणन के लिए शहरी या ग्रामीण हाट के आयोजन या प्रायोजित करने की परिकल्पना की गई है। विभाग द्वारा प्रस्तावित, नियोजित एवं स्वीकृत की गई योजनाएँ कम्पनी द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। राज्य के शिल्पियों तथा बुनकरों के हितों की रक्षा एवं बढ़ावा के के लिए कम्पनी राज्य के सभी प्रकार के हस्तकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को क्रय और विक्रय करती है।

संगठनात्मक व्यवस्था

2.2 कम्पनी उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। संस्था अन्तर्नियम के अनुसार कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है जिसमें झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत छः शासकीय निदेशक[1]

[1] (i) सचिव, उद्योग, पदेन अध्यक्ष (ii) वित्त सचिव या उनके प्रतिनिधि (iii) श्रम सचिव या उनके प्रतिनिधि (iv) निदेशक (हस्तकरघा, रेशम कीट पालन और हस्तशिल्प) (v) सहकारी संस्था के पंजीयक और (vi) प्रबन्ध निदेशक (सदस्य सचिव)

और छः गैर शासकीय निदेशक[2] समाविष्ट हैं। हालांकि, झारखण्ड सरकार द्वारा निदेशक मंडल का पुनर्गठन कर विकास आयुक्त, झारखण्ड को अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया (अगस्त 2010) जिससे निदेशकों की संख्या सात हो गई। कम्पनी के संस्था अन्तर्नियम के प्रावधानों के आवश्कतानुसार झारखण्ड सरकार ने किसी भी गैर सरकारी व्यक्तियों को निदेशक मंडल में शामिल नहीं किया है (नवम्बर 2013)। प्रबंध निदेशक (एम.डी.) ही एकमात्र पूर्णकालीन निदेशक हैं। एम.डी.[3] कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। एम.डी. को दिन प्रतिदिन के कार्यचालन में महाप्रबंधक (प्रशासन), लेखा और वित्त प्रमुख, महाप्रबंधक (परिचालन) और महाप्रबंधक (विपणन) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कम्पनी में एक पूर्णकालीन कम्पनी सचिव भी है। कम्पनी के संगठनात्मक चार्ट ***परिशिष्ट - 2.1*** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा की क्षेत्र एवं पद्धति

2.3 जून 2013 से अगस्त 2013 के दौरान की गई समीक्षा में रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प की विकास और राज्य में हस्तकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के संबंध में 2008-09 से 2012-13 के लिए कम्पनी और विभाग के प्रदर्शन को शामिल किया गया है। 3 जून 2013 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में हमने सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार और कम्पनी के प्रबंध निदेशक को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंडों, पद्धति और चयनित नमूने से अवगत कराया।

लेखापरीक्षा में विभाग के अभिलेखों, कम्पनी के निगमित कार्यालय के अभिलेखों, 35 क्लस्टर में से नौ क्लस्टर[4], दो में से एक प्रशिक्षण केन्द्र[5] और कम्पनी के शहरी हाट के अभिलेखों की जाँच शामिल थी। समीक्षा अवधि में व्यय किये गये कुल राशि ₹ 120.77 करोड़ में से ₹ 97.84 (81 प्रतिशत) करोड़ के खर्च की नमूना जाँच की गयी।

प्रारूप समीक्षा 26 सितम्बर 2013 को प्रबंधन और सरकार को निर्गत किया गया था। प्रबंधन का उत्तर प्राप्त हुआ (नवम्बर 2013)। सरकार ने प्रबंधन के

---

[2] इनमें से प्रत्येक के एक प्रतिनिधि: (i) हस्तकरघा क्षेत्र (ii) हस्तशिल्प क्षेत्र (iii) रेशम कीट पालन क्षेत्र (iv) वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (v) भारतीय उद्योग संघ, पूर्वी क्षेत्र और (vi) एन.आई.एफ.टी., कोलकाता

[3] उद्योग विभाग. झारखंड सरकार के अधीन हस्तकरघा, रेशम कीट पालन और हस्तशिल्प के विशेष सचिव और निदेशक

[4] मनियारडीह, राजीडुम्मा, गोड्डा, पोरैयाहाट, भगैया, जियाजोरी, पोखरीकला, सिकनी और सिठियो

[5] शहीद निर्मल महतो प्रशिक्षण केन्द्र, भगैया

उत्तर का समर्थन किया (दिसम्बर 2013)। निकासी सम्मेलन 11 दिसम्बर 2013 को सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार और कम्पनी के एम.डी. के साथ हुआ। सरकार के उत्तर और सरकार एवं प्रबंधन द्वारा निकासी सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचार को उपयुक्त रूप से समीक्षा में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.4 कम्पनी और विभाग की गतिविधियों की समीक्षा यह आकलित करने हेतु किया गया था कि:

- विभाग द्वारा राज्य में रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनायें तैयार की गई थीं;
- रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए योजनाओं का निष्पादन कुशलतापूर्वक, मितव्ययी और प्रभावी ढंग से कम्पनी/विभाग द्वारा किया गया और बुनकरों और शिल्पियों के हितों की रक्षा हुई थीं;
- राज्य में हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए कम्पनी के पास प्रभावी और कुशल विपणन नीति थी;
- कम्पनी के पास कुशल और प्रभावी वित्त प्रबंधन प्रणाली थी और उसने अपने संसाधनों का मितव्ययी रूप से प्रयोग किया;
- कुशल और प्रभावी इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली विद्यमान थी;
- कम्पनी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कम्पनी के पास कुशल मानव संसाधन थे; और
- कम्पनी के पास प्रभावी और कुशल आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र थी और विभाग द्वारा कम्पनी की गतिविधियों की कुशलतापूर्वक निरीक्षण किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा मानदंड

2.5 लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का आंकलन करने के लिए मानदंड के स्रोत थे:

- ❖ राज्य सरकार की औद्योगिक नीति और उसके निर्देश;
- ❖ केन्द्र प्रायोजित योजना/राज्य प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दिशा-निर्देश;
- ❖ विभिन्न योजनाओं के तहत परिकल्पित लक्ष्य;
- ❖ विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कम्पनी द्वारा तय मानदंड और मानक;
- ❖ कम्पनी की बिक्री और प्रचार नीति और
- ❖ कम्पनी का संस्था अन्तर्नियम।

लेखापरीक्षा में बाधायें

2.6 विभाग/कम्पनी ने करघा एवं उपसाधन, रिलिंग मशीनरी और उपकरणों के निविदा/क्रय की संचिकायें और स्टाक रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया था। कम्पनी ने योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था। कम्पनी ने धागे और कपड़े के उत्पादन से संबंधित आँकड़े संकलित नहीं किया था। कम्पनी ने कपड़े की सिलाई इकाई की स्थापना के लिए, क्राफ्टेज एप्रैल्स के लिये संस्तुति एवं भूमि आवंटन से संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.7 विभाग रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए योजनाएं तैयार करता है। विभाग सभी पूर्व-कोकून क्रियाएं जैसे कोकून के बनने तक रेशम कीट पालन और कोकून पालनकर्ता को सहायता भी प्रदान करता है। कम्पनी कोकून के बनने के बाद की गतिविधियों जैसे कि कोकून का क्रय, कोकून से धागा एवं धागों से कपड़े का उत्पादन और हस्तशिल्प उत्पादों से संबंधित कार्य संचालित करती है। यह बुनकरों और शिल्पियों को विपणन सहायता भी प्रदान करती है। कम्पनी रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं की कार्यकारी एजेंसी है।

नियोजन

पंचवर्षीय योजना में कोई विनिर्दिष्ट भौतिक लक्ष्य हस्तकरघा और हस्तशिल्प के संबंध में तय नहीं की गई थी।

2.8 विभाग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के तहत राज्य में रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए योजनाएं तैयार की। रेशम कीट पालन के तहत 12 अतिरिक्त पायलट परियोजना केन्द्र (पी.पी.सी.) की स्थापना के निर्धारित लक्ष्य को विभाग द्वारा प्राप्त किये गये और पी.पी.सी. की संख्या 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान 28 से बढ़कर 40 हो गई। हालांकि, हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए कोई विनिर्दिष्ट लक्ष्य तय नहीं थे और केवल केन्द्रित क्षेत्रों को पंचवर्षीय योजना अभिलेखों में उल्लेखित किया गया था।

पंचवर्षीय योजना के आधार पर झारखण्ड सरकार ने अपने वार्षिक बजट में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये धनराशि का प्रावधान किया जो सीधे विभाग द्वारा और कम्पनी द्वारा कार्यान्वित हुई। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 343.43 करोड़ के बजट प्रावधान में से ₹ 303.07 करोड़ की राशि विभाग को विमुक्त की गई जिसमें से राज्य में ₹ 277.37 करोड़ खर्च हुए।

विभाग ने कम्पनी को योजना आवंटन/बजट प्रावधान में से ₹ 177.51 करोड़ रेशम उत्पादन[6], हस्तकरघा[7] और हस्तशिल्प[8] से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदान किए जिसमें से कम्पनी ने ₹ 120.77 करोड़ (68.04 प्रतिशत) खर्च किए और 31 मार्च 2013 तक ₹ 59.38 करोड़ खर्च नहीं किए जा सके। सरकार से प्राप्त अनुदानों के कम उपयोग के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हुई जिसकी चर्चा आने वाली कंडिका में है।

रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प योजनाओं का क्रियान्वयन

2.9 रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान आठ[9] योजनाओं को स्वीकृत किया जिसे विभाग/कम्पनी द्वारा कार्यान्वित किया

---

[6] रिलर एवं स्पीनर का प्रशिक्षण, उपस्कर का क्रय, समान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) वर्कशेड का निर्माण।

[7] करघे एवं सहायक उपस्कर का क्रय, कच्ची सामाग्री, प्रशिक्षण, समान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) वर्कशेड का निर्माण, रँगाई घर।

[8] डिजाइन विकास और प्रशिक्षण।

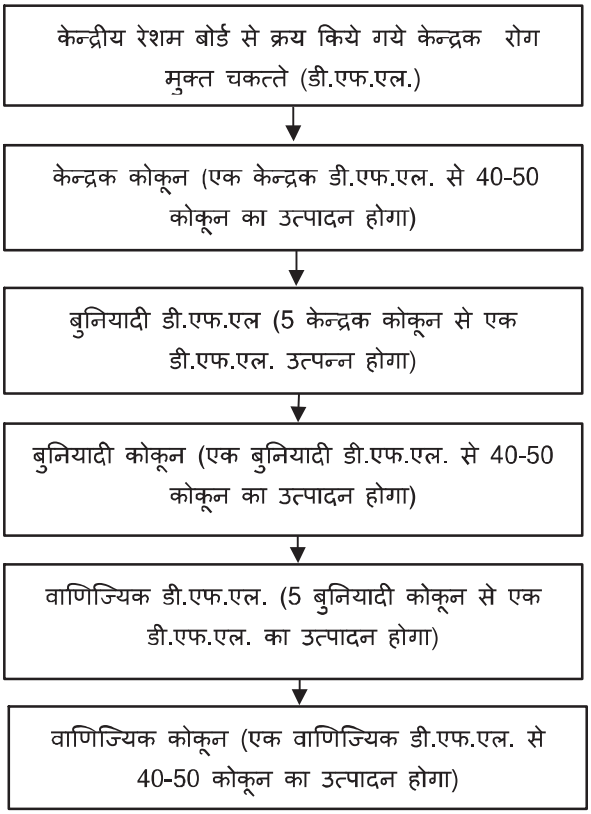
[9] सी.एफ.सी, कीटपालकों की सहायता अनुदान, क्लस्टर विकास, ग्रुप एप्रौच, प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियाँ, पी.डब्ल्यु.सी.एस., डिजाइन, विकास और प्रशिक्षण, शहरी हाट एवं मेला और प्रदर्शनी का आयोजन।

जाना था। उसमें से लेखापरीक्षा ने छः[10] योजनाओं की संवीक्षा की, जिस पर नीचे चर्चा की गई है।

रेशम कीट पालन

2.10 रेशम कीट पालन एक कृषि आधारित, निर्यात उन्मुख उद्योग है। इसका प्रत्यक्ष प्रासंगिकता समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण से है जिसमें ग्रामीण किसानों को बड़े पैमाने पर तसर खाद्य पौधों के वृक्षारोपण और रेशम कीट पालन में नियोजन किया जाता है। कोकून का उत्पादन विभाग द्वारा किया जाता है।

रोग मुक्त चकत्ते (डी.एफ.एल.)/कोकून के उत्पादन के विभिन्न स्तर निम्न प्रकार के है:



केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) के मानक के अनुसार प्रत्येक चरण में प्रति इकाई डी.एफ.एल. से कोकून का उत्पादन 40-50 की संख्या के बीच होना चाहिए तथा कोकून से 5:1 के अनुपात में डी.एफ.एल. का उत्पादन होना चाहिए।

[10] सी.एफ.सी., क्लस्टर विकास, ग्रुप एप्रौच, प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति (पी.डब्ल्यु.सी.एस.), डिजाइन, विकास एवं प्रशिक्षण, मेला और प्रदर्शनी।

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान उत्पादित कोकून के उत्पादन में कमी को ***परिशिष्ट - 2.2*** में दर्शाया गया है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि सी.एस.बी. के निर्धारित मानकों के अनुसार 83.36 करोड़ कोकून का कम उत्पादन[11] हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 84.36 करोड़ के संभावित राजस्व की हानि हुई। तथापि, वर्ष 2008-09 में कोकून के उत्पादन में कमी 32.37 प्रतिशत थी जो बढ़कर 2010-11 में 58.16 प्रतिशत हो गई तथा 2011-12 में घटकर 25.87 प्रतिशत हो गई। कोकून का उत्पादन अण्डा देने की अवधि के दौरान रोग नियंत्रण एवं मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। विभाग ने अण्डा देने की अवधि के दौरान रोगों के आकलन का ब्यौरा संकलित नहीं किया था। संकलित आंकड़ों के अभाव में विभाग समय से सुधारात्मक उपाय नहीं कर सका। अण्डा देने के अवधि के दौरान रोग के नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश तथा कोकून के उत्पादन में वृद्धि का प्रयास विभाग द्वारा किया जाना चाहिए था क्योंकि यह क्रियाविधि वर्ष 2007-08 के पूर्व से किया जा रहा था। विभाग ने केवल जुलाई 2012 में अण्डा देने के दौरान रोग से नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किया। हांलाकि, दिशा-निर्देश में केवल रोग के नियंत्रण पर जोर दिया परन्तु कोकून के उत्पादन के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया। यदि दिशा-निर्देश समय से निर्गत किया जाता तो कोकून के उत्पादन को अधिकतम किया जा सकता था। कोकून के अधिक उत्पादन से राज्य, रेशम के उत्पादन को उच्च स्तर पर लाने में सक्षम होगा एवं वाणिज्यिक बीज उत्पादकों की आय की क्षमता को सुधारने में सहायक होता।

कोकून के कम उत्पादन के कारण ₹ 84.36 करोड़ के राजस्व की हानि।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि आने वाले वर्षों में उत्पादन में सुधार होगा।

बुनियादी डी.एफ.एल. के बिक्री के विरुद्ध कम वसूली

2.11 पी.पी.सी. के ग्रेनेज[12] गृह में उत्पादित बुनियादी डी.एफ.एल. को वाणिज्यिक डी.एफ.एल. के उत्पादन हेतु रेशमदूत[13] को बेचा जाता था। पाँच पी.पी.सी[14] के नमूना जाँच में हमने देखा कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान पी.पी.सी ने रेशमदूतों को ₹ 52.82 लाख की बुनियादी डी.एफ.एल.

---

[11] संरक्षात्मक आधार पर अधिकतम 50 कोकून के बदले न्यूनतम 40 कोकून मानते हुए कोकून के उत्पादन की गणना की गयी है।

[12] एक स्थान जहाँ कोकून से डी.एफ.एल. के उत्पादन के लिए संग्रहित किया जाता है।

[13] कीटपालकों को 23 व्यक्तियों के समूह में संगठित किया जाता है उनमें से एक को रेशमदूत कहा जाता है, 2 को बीज पालक एवं शेष 20 को वाणिज्यिक कीटपालक कहा जाता है।

[14] बोरियो, गोड्डा, कथिजोरिया, बेंगाबाद, जगदीशपुर।

उधार में बेचा जिसके विरुद्ध केवल ₹ 24.64 लाख की ही वसूली की जा सकी तथा ₹ 28.18 लाख वसूली हेतु शेष रह गया। वसूली की गई ₹ 24.64 लाख की राशि में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा रेशमदूतों को स्वीकृत सहायता अनुदान[15] में से ₹ 18.07 लाख का समायोजन किया गया था। वसूली की संभावना काफी क्षीण है क्योंकि पी.पी.सी. ने बकाया की वसूली के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) और कहा कि संबंधित प्रायोगिक परियोजना पदाधिकारी (पी.पी.ओ.) को निर्देश दिया गया है कि राशि को जमा करें अन्यथा उनके विरुद्ध बकाया की वसूली के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।

ग्रेनेज गृह के लिए नगद अनुदान का भुगतान नहीं किया जाना

2.12 भारत सरकार ने वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान रेशमदूतों की सहायता प्रदान करने के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम स्वीकृत किया था। प्रत्येक रेशमदूतों को अंडों के लिए अस्थायी ग्रेनेज गृह के निर्माण हेतु ₹ 6,000 का प्रारंभिक नगद सहायता प्रदान करना योजना का एक घटक था। झारखण्ड सरकार ने भी रेशमदूतों को सहायता प्रदान करने की योजना वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान स्वीकृत की थी। विद्यमान ग्रेनेज गृह के मरम्मत और रख-रखाव के लिए प्रत्येक रेशमदूतों को ₹ 2,000 प्रति वर्ष नगद सहायता के रूप में प्रदान करना योजना का एक घटक था। तथापि, नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त दोनों योजनाओं के तहत सहायता अनुदान रेशमदूतों को पूरी तरह वितरित नहीं किया गया था बल्कि रेशमदूतों से प्राप्य बुनियादी डी.एफ.एल. के मूल्य से समायोजित किया गया था जैसा कि कंडिका 2.11 में चर्चा किया गया है। इससे अंडों के लिए आवश्यक ग्रेनेज गृह के निर्माण एवं मरम्मत के लिए सहायक अनुदान देने का उद्देश्य विफल हुआ जो कोकून के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है जैसा कि कंडिका 2.10 में विवेचित है।

[15] अस्थायी ग्रेनेज गृह के निर्माण के लिए।

कोकून के भण्डारण का अपर्याप्त सुविधा

2.13 कम्पनी रेशम धागों के उत्पादन हेतू बीज उत्पादकों से कोकून का क्रय करता है। कोकून का भण्डारण कोकून बैंक में करना आवश्यक है। विभाग ने वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान 22 कोकून बैंकों के निर्माण की स्वीकृति दी जो सरकारी अभिकरणों[16] द्वारा बनाया जाना था। तथापि, इस अवधि में केवल छ: कोकून बैंकों का निर्माण[17] किया गया। अपर्याप्त भंडारण सुविधा के कारण कोकून का भण्डारण उचित तरीकों से नहीं किया जा सका, जिसके फलस्वरूप कोकून की गुणवत्ता में गिरावट हुई तथा धागे का कम उत्पादन हुआ जैसा कि अनुवर्ती कंडिका में चर्चित है। लेखापरीक्षा क्लस्टर विकास कार्यपालक के साथ संयुक्त कार्यक्षेत्र दौरा में कोकून के अनुपयुक्त भण्डारण को देखा गया था, जिसे नीचे के चित्र में दर्शाया गया है।




(पी.पी.सी. बेंगाबाद का फोटो)

यह विदित है कि कोकून बैंकों के निर्माण में विलंब के फलस्वरूप कोकून के भण्डारण सुविधा अपर्याप्त रही।

कोकून से धागा का कम उत्पादन

कोकून से 37,824 कि.ग्रा. रेशम धागे का कम उत्पादन।

2.14 सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) में कम्पनी द्वारा नियोजित रिलर एवं स्पीनर के द्वारा सुखाकर एवं पकाकर[18] कोकून से रेशम तन्तु (धागा) को काता जाता है। कम्पनी ने अनुमान लगाया कि 1,000 कोकून से 1 किलोग्राम रेशम धागे का उत्पादन होगा जबकि विभाग ने अनुमान लगाया कि 1,000 कोकून से एक से 1.20 किलोग्राम रेशम धागे का उत्पादन होगा। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान कम्पनी ने 7.24 करोड़ कोकून, रिलर एवं स्पीनर[19] को रेशम धागे के उत्पादन के लिए आपूर्ति किया। रेशम धागे का

[16] झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम, एन.आर.ई.पी. और ग्रामीण विकास विभाग।

[17] 2011-12 में तीन और 2012-13 में तीन।

[18] रिलिंग एंव स्पीनिंग से पहले कोकून को प्रेशर कुकर में उबालते है।

[19] खरसावाँ, बेड़ो, पी.पी.सी. रातु, भगैया और जियाजोरी क्लस्टर्स में।

अनुमानित उत्पादन 72,366 किलोग्राम के विरुद्ध उनके द्वारा 34,542 किलोग्राम का ही उत्पादन किया गया। इस प्रकार रेशम धागे के अनुमानित उत्पादन से 37,824 किलोग्राम रेशम धागे का कम उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त प्रति हजार कोकून से रेशम धागे का उत्पादन वर्ष 2008-09 में 0.77 किलोग्राम से घटकर वर्ष 2012-13 में 0.42 किलोग्राम हो गया जो रेशम धागे के उत्पादन में घटते क्रम को दर्शाता है। रेशम धागे के उत्पादन में कमी का मूल कारण कोकून का अनुचित भण्डारण सुविधा था जैसा कि कंडिका संख्या 2.13 में वर्णित है।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि अगर कोकून श्रेणी-ए के गुणवत्ता का हो तथा रिलर/स्पीनर अनुभवी हों तब वे 1,000 कोकून से एक किलोग्राम धागे का उत्पादन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ए, बी एवं सी श्रेणी के कोकून खरीदे गए थे।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि कम्पनी ने रिलर एवं स्पीनर द्वारा धागे के उत्पादन के अनुश्रवण के लिए नियंत्रण तंत्र का विकास नहीं किया था क्योंकि धागे का उत्पादन रिलिंग एवं स्पीनिंग के लिए निर्गत कोकून के अनुरुप नहीं था। व्यक्तिश: निर्गत कोकून एवं उसके विरुद्ध उत्पादित धागे के मिलान के लिये अभिलेखन की प्रणाली नहीं थी। नियंत्रण तंत्र के अभाव में धागे/कोकून की चोरी को नकारा नहीं जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी/विभाग द्वारा बनाये गये प्राक्कलन में कोकून की श्रेणी को शामिल नहीं किया गया तथा उन्होंने अनुमान लगाया कि 1000 कोकून से एक किलोग्राम से 1.2 किलोग्राम धागा उत्पादित होगा।

इसके अलावा, वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान बेड़ों एवं रातू पी.पी.सी. ने श्रेणी-ए के 21,582 हजार कोकून सामान्य सुविधा केन्द्रों/ स्वयं सहायता समूहों को निर्गत किया जिसके विरुद्ध केवल 8,708 किलोग्राम धागों का ही उत्पादन हुआ जबकि 21,582 किलोग्राम धागा का उत्पादन होना था। वास्तव में वर्ष 2009-10 में प्रति हजार कोकून से धागे का उत्पादन 0.63 किलोग्राम था जो घटकर वर्ष 2012-13 में 0.36 किलोग्राम हो गया। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष में प्रशिक्षित रिलर एवं स्पीनर को ही अनुभवहीन समझा जा सकता था जबकि पूर्व के वर्षों में प्रशिक्षित और उत्पादन से जुड़े हुए रिलर एवं स्पीनर को अनुभवी माना जा सकता है। कम्पनी ने समीक्षा अवधि के दौरान अनुभवी तथा अनुभवहीन दोनों तरह के रिलर एवं स्पीनर को उत्पादन में लगाया था। अत: सरकार का दावा कि अनुभवी रिलर एवं स्पीनर ही एक

हजार कोकून से एक किलोग्राम धागा पायेंगे सही नहीं है। इसके अतिरिक्त अपर्याप्त भंडारण सुविधा भी धागे के कम उत्पादन का कारण था जैसा कि कंडिका 2.13 में दर्शाया गया है।

सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी) की स्थापना

2.15 झारखण्ड सरकार ने कोकून के बाद के कार्यकलाप जैसे कि कोकून को रेशम धागे में बदलना तथा ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने को बढ़ावा देने के लिए योजना स्वीकृत की। वर्ष 2008-09 से 2011-12[20] के दौरान स्वीकृत ₹ 12.45 करोड़[21] के विरुद्ध कम्पनी ने ₹ 7.32[22] करोड़ खर्च किया।

हमने अवलोकित किया कि:

- कम्पनी ने 82 कार्यशालाओं के लक्ष्य के विरुद्ध ₹ 1.06 करोड़ की लागत से केवल 18 कार्यशालाओं (28 प्रतिशत) का निर्माण कराया तथा विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण शेष 64 कार्यशालाओं का निर्माण शुरू नहीं हुआ था। विभाग ने भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना साल-दर-साल योजना की स्वीकृति दिया तथा उसके लिये निधि जारी किया। यद्यपि, कम्पनी 2006-07 से 2011-12 के दौरान जिला प्रशासन से कार्यशालाओं का प्रबंध कर 144 सी.एफ.सी को संचालन कर रही थी।

₹ 97.53 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र का अनियमित प्रस्तुतीकरण।

- इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि कम्पनी ने जनवरी 2009 में झारखण्ड सरकार द्वारा कार्यशालाओं के निर्माण के लिए स्वीकृत ₹ 47.53 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया (अगस्त 2010) जबकि सितम्बर 2013 तक वास्तविक खर्च ₹ 40.88 लाख था। इसी प्रकार, अगस्त 2009 में मशीनरी एवं उपस्कर के क्रय के लिए स्वीकृत एवं निर्गत ₹ 50 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया (नवम्बर 2010) जबकि, सितम्बर 2013 तक वास्तविक खर्च ₹ 41.47 लाख था। उपयोगिता प्रमाण पत्र निधि के व्यय के पश्चात् ही निर्गत किया जाता है। इस प्रकार, राशि के व्यय से पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना स्वीकृति के शर्तों का उल्लंघन था। झारखण्ड सरकार के पास

[20] वर्ष 2012-13 के लिये प्राप्त ₹ 14.66 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं थी।

[21] वर्कशेड ₹ 4.69 करोड़, सयंत्र एवं उपस्कर ₹ 1.76 करोड़, कार्यशील पूँजी ₹ 3.54 करोड़, प्रशिक्षण ₹ 1.57 करोड़ और पर्यवेक्षण शुल्क ₹ 0.89 करोड़।

[22] वर्कशेड ₹ 1.06 करोड़, सयंत्र एवं उपस्कर ₹ 1.40 करोड़, कार्यशील पूँजी ₹ 3.42 करोड़, प्रशिक्षण ₹ 0.55 करोड़ और पर्यवेक्षण शुल्क ₹ 0.89 करोड़।

उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रमाणिकता एवं परिशुद्धता सुनिश्चित करने का कोई तंत्र नहीं था।

इसके अतिरिक्त यह उल्लेख किया जाता है कि विभाग/ कम्पनी रिलिंग एवं स्पीनिंग मशीन एवं उपस्कर के क्रय अभिलेख एवं भंडार पंजी प्रस्तुत नहीं कर सका। मशीनरी एवं उपस्कर के क्रय एवं निर्गत करने के उपयुक्त अभिलेखों के अभाव में क्रय दरों के औचित्य एवं इन उपकरणों के सुरक्षा तथा इनके उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि उन्होंने अब भूमि की व्यवस्था कर ली है तथा कार्यशालाओं के निर्माण का कार्य भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) को सौंप दिया है (मार्च से जून 2013)।

सरकार ने कार्यशालाओं के निर्माण के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया; तथापि, अनियमित उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रस्तुतिकरण तथा अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण अनुत्तरित रहा।

हस्तकरघा

2.16 हस्तकरघे पर बुनाई के उपरांत रेशम एवं सूती धागे से कपड़ा बनाया जाता है। हस्तकरघा के विकास के लिए भारत सरकार ने क्लस्टर विकास योजना (सी.डी.एस.)[23] एवं ग्रुप एप्रौच योजना[24] तथा झारखण्ड सरकार ने प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति (पी.डब्ल्यु.सी.एस.)[25] योजना स्वीकृत किया। योजनाओं का उद्देश्य पी.डब्ल्यु.सी.एस/एस.एच.जी. को नये कार्यशालाएं उपलब्ध कराना, विद्यमान कार्यशालाओं का मरम्मत, करघा एवं उपसाधन प्रदान करना, डिजाइन एवं विकास तथा विपणन में सहायता, दक्षता उन्नयन के लिए प्रशिक्षण तथा बुनकरों की जीविका कायम रखने तथा उनके सामाजिक उत्थान हेतु कार्यशील पूँजी प्रदान करना था। उपर्युक्त वर्णित योजनाओं का कार्यान्वयन की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

---

[23] सी.डी.एस. भारत सरकार के द्वारा ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के दौरान लिया गया समेकित हस्तकरघा विकास योजना का एक भाग है और फरवरी 2011 के बाद नया क्लस्टर स्वीकृत नहीं किया गया।

[24] वैसे बुनकर जो सी.डी.एस. के अधिन नहीं आते वे इस योजना के अधिन थे।

[25] वैसे पी.डब्ल्यु.सी.एस. का पुन:उद्धार जो बीमार और बंद होने के कगार पर थे।

क्लस्टर विकास योजना

2.17 भारत सरकार ने ₹ 19.70 करोड़[26] की कुल लागत से 35 क्लस्टर[27] के विकास के लिए स्वीकृति दिया जो ***परिशिष्ट - 2.3*** में दर्शाया गया है। इसके तहत प्रत्येक क्लस्टर के अधीन 20 बुनकर होने थे। कम्पनी को 26 क्लस्टर के लिए स्वीकृत की गई ₹ 16.64 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। हालांकि, बाकी नौ क्लस्टर के संदर्भ में तीसरा किस्त का मिलना बाकी था। इसमें से ₹ 12.61 करोड़ कम्पनी द्वारा व्यय किया गया।

हमने अवलोकित किया कि:

- झारखण्ड सरकार ने प्रक्रियात्मक देरी के कारण एक महीने की अधिदेशित अवधि के विरुद्ध भारत सरकार से निधि की प्राप्ति के नौ से 12 महीने बाद कम्पनी को निधि निर्गत किया।

- रँगाई, बुनाई एवं डिजाइन में प्रत्येक पर 700 व्यक्तियों के लक्ष्य के विरुद्ध रँगाई में 520, बुनाई में 560 एवं डिजाइन में 280 व्यक्तियों को कम्पनी ने प्रशिक्षण दिया। कम्पनी ने दिसम्बर 2010 एवं फरवरी 2011 की स्वीकृति के विरुद्ध रँगाई एवं डिजाइन में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया था। प्रशिक्षण में कमी का कारण कार्यशालाओं की अनुपलब्धता थी। इस प्रकार, बुनकरों के निरंतर आजीविका एवं सामाजिक उत्थान का उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका।

- 35 सी.एफ.सी कार्यशालायें एवं 21 रँगाई घरों के निर्माण के लिए ₹ 6.24 करोड़ की स्वीकृति थी। हालांकि, विभाग द्वारा निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं कराने के कारण कम्पनी ने अब तक (मार्च 2013) कोई भी सी.एफ.सी कार्यशाला एवं रँगाई घर का निर्माण नहीं किया था। क्लस्टर के क्षेत्र दौरा के दौरान यह पाया गया कि कार्यशालाओं के अनुपलब्धता के कारण बुनकर बरसात के मौसम में अपने घरों में काम करने के लिए विवश थे एवं उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था।

---

[26] केन्द्रीय अंश ₹ 18.85 करोड़ और राज्य अंश रुपये 84.98 लाख।

[27] इरवा चुट्टु, जियाजोरी, बहरागोड़ा, सिठियो, पोखरीकला, उरुगुट्टु, खुंटी, सरायहाट, भगैया, माँडर, (फरवरी 2008), गोड्डा, सुदना, पोरैयाहाट इस्लामपुर, बालधर, जमुनिया, राजीडुम्मा, मनियारडीह, महुआडाबर, हरिहरगंज, लोहरदग्गा (अक्तूबर 2008); पचरुखी, बोरियो, मुरुजुली, सिकनी, फसिया (नवंबर 2009); नयासराय, बरहेत, पाकुड़, मुरुमडेगा, बौरीजोरी (दिसंबर 2010) और ग़ढ़वा, बानापीढ़ी, राजहर, कुन्दरी (फरवरी 2011)

- योजना के उद्देश्यों में से एक, कंसोर्टियम के संस्थापन द्वारा हस्तकरघा बुनकर समूहों को स्वावलम्बी बनाने हेतु सहायता करना था। संबंधित संगठनों जैसे बैंक/वित्तीय संस्थाओं, विपणन संस्थाओं/विपणन विशेषज्ञों, कानूनी विशषज्ञों, सरकारी तंत्रों, बुनकरों इत्यादि के साथ बुनकरों के विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए कम्पनी को स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति, मुख्य बुनकर, निजी उद्यमी, गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) के हितधारकों को शामिल कर कंसोर्टियम संस्थापित करना था। क्लस्टर को स्वावलम्बी आधार पर चलाने हेतु इसकी गतिविधियों को, कंसोर्टियम दवारा इसके गठन के तीन साल में या उसके बाद अधिग्रहण करना था। हांलाकि, 26 क्लस्टरों के निर्माण के अधिदेशित तीन साल के बाद नौ महीने से 32 महीने तक भी कम्पनी द्वारा किसी भी क्लस्टर में कंसोर्टियम की स्थापना नहीं की गई थी।

सरकार ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) कि भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण रँगाई घरों एवं सी.एफ.सी कार्यशालाओं का निर्माण नहीं किया गया और कहा कि रँगाई घरों और रँगाई प्रशिक्षण का उद्देश्य भिन्न था। रँगाई घरों का निर्माण बड़े पैमाने के जरूरतों को पूरा करने के लिए था जबकि बुनकरों को रँगाई का प्रशिक्षण धागे की उनके अपने जरूरतों को पूरा करने हेतु दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि कम्पनी द्वारा प्रत्येक क्लस्टर के लिये कंसोर्टियम की संस्थापन को क्रियान्वित नहीं किया गया था क्योंकि पी.डब्ल्यु.सी.एस. एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा सभी प्रक्रिया को किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक क्लस्टर को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से सभी क्लस्टर में कंसोर्टियम बनाना था जो कि अभी तक हासिल नहीं किया गया था और समूहों के रँगाई की जरूरतों को कम्पनी के रँगाई घर एवं एक निजी रँगाई घर को पुनर्जीवित कर किया गया।

ग्रुप एप्रौच योजना

2.18 इस योजना की संकल्पना बुनकरों के विकास के लिए किया गया, जो क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं थे। स्वयं सहायता समूह/ पी.डब्ल्यु.सी.एस./अन्य स्वतंत्र/व्यक्तिगत बुनकरों के रूप में एक समूह में अधिमानत: 10 या अधिक बुनकर होने चाहिए थे। वर्ष 2008-09 से

2011-12 के दौरान भारत सरकार ने ग्रुप एप्रौच योजना के लिए ₹ 5.35[28] करोड़ स्वीकृत किये जैसा कि ***परिशिष्ट-2.4*** में दर्शाया गया है। भारत सरकार ने ₹ 5.13 करोड़ की स्वीकृत राशि के विरुद्ध ₹ 4.08 करोड़ निर्गत किये और कम्पनी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण शेष ₹ 1.05 करोड़ निर्गत नहीं किए गये। हांलाकि, झारखण्ड सरकार ने अपने भाग की पूरी राशि ₹ 21.80 लाख निर्गत किया। ₹ 4.30 करोड़ के निर्गत निधि के विरुद्ध कम्पनी द्वारा वास्तविक व्यय ₹ 4.18 करोड़ किया गया था (मार्च 2013)।

हमने अवलोकित किया कि:

- कम्पनी ने 90 स्वयं सहायता समूह के लक्ष्य के विरुद्ध 81 स्वयं सहायता समूह का गठन किया था (नवम्बर 2013)।

- कम्पनी ने 81 कार्यशालाओं के विरुद्ध केवल 62 कार्यशालाओं का निर्माण (अगस्त 2013) पी.डब्ल्यु.सी.एस. एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा दान दी गई भूमि पर किया। 14 कार्यशालाओं का निर्माण प्रगति पर था और शेष पाँच कार्यशालाओं के मामले में विभाग भूमि की व्यवस्था नहीं कर सका। कार्यशालाओं के निर्माण में देरी के कारण बुनकरों को वांछित लाभ मुहैया नहीं किया जा सका।

- बुनाई एवं रँगाई पर क्रमश: 180 एवं 260 व्यक्तियों के प्रशिक्षण लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 140 व्यक्तियों को बुनाई एवं 220 व्यक्तियों को रँगाई का प्रशिक्षण दिया गया (अगस्त 2013)। बुनाई एवं रँगाई प्रत्येक पर 40 व्यक्तियों को योजना की स्वीकृति के चार से पाँच साल के बाद भी कार्यशालाओं, जहाँ कि प्रशिक्षण के लिए करघों को स्थापित करना था, की अनुपलब्धता के कारण प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इस प्रकार बुनकरों के स्वावलम्बी जीविका एवं सामाजिक उत्थान का उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (दिसम्बर 2013) कि नौ कार्यशालाओं का निर्माण जारी था और दो कार्यशालाओं के लिए जल्द ही कार्यादेश दे दिया जाएगा। भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई और कहा कि अब उनके पास भूमि उपलब्ध थीं।

[28] केन्द्रीय अंश ₹ 5.13 करोड़ और राज्य अंश ₹ 21.80 लाख।

तथ्य यह है कि अभी तक 11 कार्यशालाओं का निर्माण नहीं किया जा सका था जिसके परिणामस्वरूप बुनकरों को लाभ मुहैया कराने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति योजना

2.19 झारखण्ड सरकार ने प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों (पी.डब्ल्यु.सी.एस.)[29] जो बीमार थे एवं बंद होने के कगार पर थे, को पुर्नजीवित करने की पहल की थी। पी.डब्ल्यु.सी.एस. न्यूनतम 20 बुनकरों एवं एक अध्यक्ष के अध्यक्षता में होते हैं। पी.डब्ल्यु.सी.एस. के सुदृढ़ीकरण हेतु झारखण्ड सरकार ने ₹ 31.12 करोड़ स्वीकृत किया जैसा कि ***परिशिष्ट - 2.5*** में दर्शाया गया है जो कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान प्राप्त हुआ। इसमें से कम्पनी ने केवल ₹ 19.89 करोड़ ही खर्च कर सका (मार्च 2013)।

हमने अवलोकित किया कि 236 कार्यशालाओं के लक्ष्य के विरुद्ध पी.डब्ल्यु.सी.एस. द्वारा दानित भूमि पर केवल 30 कार्यशालाओं का निर्माण पूर्ण हुआ और तीन कार्यशालाओं का निर्माण प्रगति पर था। 203 कार्यशालाओं का निर्माण नहीं शुरु किया जा सका (मार्च 2013) क्योंकि भूमि की व्यवस्था न तो विभाग द्वारा किया गया और न ही पी.डब्ल्यु.सी.एस. द्वारा दान दिया गया। 4,240 बुनकरों के प्रशिक्षण लक्ष्य के विरुद्ध कम्पनी ने 3,624 बुनकरों को प्रशिक्षण दिया। यह अवलोकित किया गया कि विभाग ने योजना के पूर्ण करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया था। इस प्रकार, दिए गए समय सीमा में योजना को पूर्ण करने में तात्कालिकता की भावना की कमी थी।

हमने पुन: अवलोकित किया कि:

₹ 2.88 करोड के उपयोगिता प्रमाणपत्र का अनियमित प्रस्तुतीकरण।

- ₹ 5.74 करोड़[30] की स्वीकृति अगस्त 2012 में दिया गया (राशि मार्च 2013 में प्राप्त हुआ) जिसमे अन्य बातों के साथ 48 कार्यशालाओं का निर्माण, करघें एवं सहायक उपकरणों की खरीद, 48 बुनकर समूहों के प्रशिक्षण एवं भूमि का अर्जन शामिल था। कम्पनी द्वारा कार्यशालाओं के निर्माण के संबंध में अगस्त 2013 में ₹ 2.88 करोड़ का उपयोगिता

[29] सोसायटी अधिनियम के अंर्तगत पंजीकृत।

[30] वर्कशेड के निर्माण के लिये ₹ 2.88 करोड़, करघें एवं सहायक उपस्कर के लिये ₹ 0.91 करोड़, प्रशिक्षण के लिये ₹ 0.53 करोड़, पर्यवेक्षण शुल्क के लिये ₹ 0.42 करोड़ एवं जमीन अधिग्रहण के लिये ₹ 1.00 करोड़।

प्रमाण पत्र जमा किया गया जो अनियमित था क्योंकि योजना के अन्तर्गत कोई भी कार्यशाला का निर्माण नहीं किया गया था।

- झारखण्ड सरकार ने ₹ तीन करोड़ स्वीकृत किया (दिसम्बर 2008) जिसमें अन्य बातों के अलावा भगैया में रँगाई एवं फिनिशिंग कार्यशालाओं के लिए ₹ 16 लाख और रँगाई एवं फिनिशिंग उपकरण के लिए ₹ 20 लाख शामिल था। यह अवलोकित किया गया कि कम्पनी ने फरवरी 2010 में ही पूरे स्वीकृत राशि ₹ तीन करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र झारखण्ड सरकार को जमा कर दिया यद्यपि रँगाई एवं फिनिशिंग कार्यशाला का निर्माण फरवरी 2011 तक नहीं किया गया था। ऐसे ही, रँगाई एवं फिनिशिंग उपकरण बिना खरीदे फरवरी 2010 में इसके लिए स्वीकृत राशि ₹ 20 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र झारखण्ड सरकार को जमा कर दिया गया। उसके बाद (मार्च 2013) दूसरी योजनाओं से ₹ 10.42 लाख की लागत से रँगाई एवं फिनिशिंग उपकरण खरीदे गए। इस प्रकार कम्पनी ने झारखण्ड सरकार को गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया। विभाग के पास कम्पनी द्वारा जमा किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता एवं यथार्थता को पता करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

- कार्यशाला के आकार के अनुसार वर्कशेड के निर्माण ₹ तीन लाख एवं ₹ छः लाख की लागत से करना था। तथापि ग्रुप एप्रौच योजना एवं पी.डब्ल्यु.सी.एस. के अन्तर्गत निर्मित 17 वर्कशेड[31] के संयुक्त कार्य क्षेत्र दौरा[32] के दौरान यह देखा गया कि तीन गाँवों[33] में दूसरी वर्कशेड का निर्माण मौजूदा कार्यशाला के ऊपर पहली मंजिल पर किया गया एवं चार गाँवों[34] में वर्कशेड के दीवारों में से एक दीवार मौजूदा कार्यशाला के साथ सामान्य था। मापी पुस्तिका एवं निष्पादित कार्य के वास्तविक मात्रा के विवरण के अभाव में भुगतेय राशि से काटी जाने वाली राशि की मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सका।

---

[31] सिठियो (दो), बरहु (दो), उपरकोन्की (दो), उरगुट्टु (एक), मोहनपुर (एक), कटमकुल्ली (दो), बरोदीवला (एक), सिकनी (दो), साकेर (एक), पोटामडागा (एक), वासिम (एक), कुंडरुकला (एक)।

[32] कम्पनी के कल्सटर विकास कार्यपालक के साथ।

[33] सिठियो, बरहु और कटमकुल्ली।

[34] कटमकुल्ली, मोहनपुर, उपरकोन्की और सिकनी।

- यद्यपि दो गाँवों[35] में वर्कशेड का निर्माण किया गया पर उन वर्कशेड में कोई करघे नहीं थे।

पुन: यह उल्लेखनीय है कि विभाग/कम्पनी, निविदा/क्रय सम्बन्धित संचिका और करघों एवं सहायक उपकरणों की भंडार पंजी प्रस्तुत नहीं कर सका। करघों एवं उपकरणों के क्रय एवं निर्गम से संबंधित उचित अभिलेख के अभाव में इन उपकरणों की सुरक्षा एवं इनकी उपयोगिता सुनिश्चित नहीं किया जा सका। कम्पनी ने योजनावार करघों एवं उपकरणों के खरीद का आँकड़ा संधारित नहीं किया था। योजनवार आँकड़ों के अभाव में योजना का अनुश्रवण नहीं किया जा सकता था।

सरकार ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) कि भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्यशाला का निर्माण नहीं किया जा सका एवं कहा कि अब भूमि उपलब्ध है और बी.एस.एन.एल. को कार्यादेश दे दिया गया है (मार्च से जून 2013)।

तथापि, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में इंगित अनियमितताओं एवं वर्कशेड के निर्माण में उजागर की गई अनियमितताओं के बारे में उत्तर मौन है।

प्रशिक्षित बुनकरों का उपयोग

2.20 बाजार के बदलते प्रवृत्ति के अनुसार और बेहतर गुणवत्ता के साथ विविध उत्पादों के उत्पादन हेतु हस्तकरघा बुनकरों को स्वयं के अनुकूलन के लिए प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण निवेश है। योजना के अनुसार बुनकरों को प्रशिक्षण दिया गया और कम्पनी को भी रेशम एवं सूती धागे और रंग रसायनों की क्रय के लिए रिवालविंग फण्ड के रूप में कार्यशील पूँजी प्रदान की गई।

17 क्लस्टर[36] के लेखों के नमूना जाँच में उजागर हुआ कि कम्पनी ने वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान 2,495 बुनकरों को प्रशिक्षण दिया उसमें से केवल 1,280 बुनकर (51 प्रतिशत) को कम्पनी द्वारा मार्च 2013 को काम में लगाए गए। कम्पनी द्वारा काम में लगाए गए प्रशिक्षित बुनकरों की संख्या असामान्य रूप से कम थी। जैसा कि क्षेत्र दौरा के दौरान क्लस्टर विकास कार्यपालक ने बताया कि संरचनात्मक सुविधाओं की कमी जैसे वर्कशेड, कच्चे

[35] पोटामडागा और कुंडरुकला।

[36] सिठियो, मनियारडीह, महुआडाबर, जमुनिया, बाल्टहर, बोरियो, बरहेत, जियाजोरी, गोड्डा, सरायहाट, पोरैयाहाट, फसिया, सिकनी, पचरुखी, हजारीबाग एवं खरसावाँ

मालों की अनियमित आपूर्ति और मजदूरी के भुगतान में देरी इत्यादि कारणों से प्रशिक्षित व्यक्तियों को कम्पनी द्वारा काम में नहीं लगाया जा सका। इसके परिणामस्वरूप करघों का अल्प उपयोग हुआ जैसा कि कंडिका संख्या 2.21 में टिप्पणी की गयी है। कम्पनी को प्रशिक्षित बुनकरों के अधिकतम उपयोग के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

इस तरह, ₹ 1.82 करोड़[37] के व्यय के बाद भी 1,215 बुनकरों के स्वावलम्बी बुनकर समूहों के सदस्य बनने हेतू बुनकरों को दिया गया प्रशिक्षण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

करघों का अल्प उपयोगिता

2.21 कम्पनी ने बुनकरों को कपड़े का उत्पादन के लिए हस्तकरघा इस अनुमान के साथ प्रदान किया था कि रेशम बुनकर द्वारा प्रतिदिन पाँच मीटर कपड़े का एवं सूती बुनकर द्वारा सात मीटर कपड़े का उत्पादन किया जायेगा। कम्पनी की नीतियों के अनुसार बुनकरों को एक साल में 260 दिन कार्य में लगाना है। यह देखा गया कि 22 क्लस्टर[38] में जिसके संबंध में उत्पादन का आंकड़ा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया था, निर्धारित उत्पादन न्यूनतम पाँच मीटर[39] प्रति करघा प्रतिदिन की तुलना में रेशम एवं सूती कपड़े का वास्तविक उत्पादन बहुत कम था जैसा कि ***तालिका - 2.1*** में दर्शाया गया है।

तालिका - 2.1

वर्ष	उत्पादन हेतु 1 अप्रैल को उपलब्ध करघों की संख्या	उत्पादित कपड़े (मीटर)	उत्पादन हेतु आवश्यक करघों की संख्या	करघों के अल्प उपयोगिता का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4) =(3)/(5*260)	(5)={(2)-(4)}/(2)*100
2009-10	121	66653	51	58
2010-11	385	133446	103	73
2011-12	842	162650	125	85
2012-13	1062	220126	169	84

(स्रोत: समूहों द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

ऊपर से यह देखा जा सकता है कि बुनकरों को प्रशिक्षण देने के बावजूद करघे के उपयोग में कमी थी एवं करघों की अल्प उपयोगिता वर्ष 2009-10 में 58

---

[37] बुनकर @ ₹ 15,000 प्रति बुनकर x 1,215 = ₹ 1.82 करोड़

[38] जियाजोरी, बौरीजोरी, गोड्डा, फसिया, पोरैयाहाट, सरैयाहाट, मनियारडीह पचरुखी, महुआडाबर, राजीडुम्मा, बालथर, पोखरीकला, सहेर बसेला देवरी नगरी, सिठियो, महुआडांड।

[39] रेशम एवं सूती कपडे के उत्पादित मात्रा अलग-अलग उपल्बध नहीं थे इसलिये न्यूनतम उत्पादन 5 मीटर माना गया है।

प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 84 प्रतिशत हो गया। हमने अवलोकित किया कि कम्पनी ने बुनकरों को एक वर्ष में 260 दिन कार्य में नहीं लगा सकी। बुनकरों के मजदूरी भुगतान में देरी, धागों का अनियमित आपूर्ति एवं वर्कशेड की अनुपलब्धता क्लस्टर विकास कार्यपालक द्वारा करघों के अल्प उपयोगिता के कारण बताये गये थे। पुन: अपर्याप्त अनुश्रवण के कारण करघों का अनुकूलतम उपयोग नहीं किया जा सका।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि प्रति वर्ष कुल उपलब्ध करघों में से कई का उपयोग प्रशिक्षण में किए गए एवं प्रशिक्षण के दौरान उत्पादन उसी गति से नहीं किया जा सकता है। कई करघे साल के बीच में यहाँ तक कि साल के अंत में स्थापित किए गए। इसके सिवाय, बुनकर कम्पनी के कर्मचारी नहीं थे एवं सरकार उन्हें प्रतिदिन मानक घंटों तक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमने वर्ष के शुरुआत मे उत्पादन के लिए उपलब्ध करघों को ध्यान में रखते हुए करघों की अल्प उपयोगिता की मात्रा की गणना की है। पुन: कम्पनी द्वारा बुनकरों को बिना लागत के करघे उनके पूर्णकालीन कार्य के लिए उपलब्ध कराए गये थे।

हस्तशिल्प

2.22 ग्रामीण शिल्पियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से झारखण्ड सरकार द्वारा हस्तशिल्प के विकास हेतु योजना स्वीकृत की गयी थी जिसे कम्पनी द्वारा कार्यान्वित की जानी थी। इस योजनान्तर्गत पारम्परिक हस्तकलाओं[40] का प्रशिक्षण दिया जाना था और प्रशिक्षित शिल्पियों को उत्पादन कार्य में लगाया जाना था। सरकार ने वर्ष 2009-10 से 2011-12 के बीच 21,750 शिल्पियों के प्रशिक्षण हेतु ₹ 15.08 करोड़ की मंजूरी दी। कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार वर्ष 2009-10 से 2012-13 के बीच 23,602 शिल्पियों को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें ₹ 13.67 करोड़ व्यय हुए।

हमने नमूना जाँच में पाया कि कम्पनी ने 11,729 शिल्पियों[41] को प्रशिक्षण दिया जिसमें से सिर्फ 1,734 अर्थात 15 प्रतिशत शिल्पियों को ही वर्ष 2012-13 में उत्पादन में लगाया गया। परियोजना प्रबंधक एवं पी.पी.ओ., खरसावाँ ने प्रशिक्षित शिल्पियों के काम छोड़ने का कारण कच्चे मालों की अनियमित

[40] आदिवासी चित्रकला, ढोकरा क्राफ्ट, ग्रासमेट, बंबु क्राफ्ट, पेपरमेशी, लाख चूड़ियाँ, वुडक्राफ्ट इत्यादि

[41] आकर्षणी, खरसावाँ, शहरी हाट, हजारीबाग, सिठियों क्लस्टर के अंतर्गत देवरी नगरी पी.डब्ल्यु.सी.एस.

आपूर्ति बताया। हालाकि, कच्चे माल के क्रय के लिए कम्पनी को कार्यशील पूँजी उपलब्ध करायी गयी थी।

प्रशिक्षित शिल्पियों के डेटाबेस के अभाव में ₹ 6.93 करोड़ व्यय के बावजुद भी विपणन सहायता प्रशिक्षित शिल्पियों को नहीं दिया जा सका

कम्पनी द्वारा प्रशिक्षित सभी शिल्पियों को कम्पनी के अपने उत्पादन कार्यों में नहीं लगाया था। प्रशिणार्थियों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित ज्ञान एवं कुशलता का उपयोग, जो काम पर नहीं लगाये थे और उनके द्वारा प्राप्त लाभों का कम्पनी/विभाग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया था। कम्पनी ने लाभपूर्ण स्वरोजगार में नियुक्त प्रशिक्षित शिल्पियों का रिकार्ड नहीं बनाया। यह जरूरी था क्योंकि कम्पनी द्वारा प्रशिक्षित शिल्पियों को बाजार सहयोग उपलब्ध कराना आवश्यक था। इस प्रकार ₹ 6.93 करोड़[42] की लागत से 9,995 शिल्पियों का प्रशिक्षण देने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि काम में लगाये गये शिल्पियों की संख्या जो कम्पनी द्वारा दर्शाया गया था, सही नहीं था क्योंकि अकेले हजारीबाग में लगभग 10,000 शिल्पियों को लगाया गया था, पर उनके पास इससे संबंधित सूचना सुलभ नहीं है। सरकार ने आगे कहा कि अंकेक्षक द्वारा उठाये गए इस मुद्दे पर उपयुक्त कारवाई की जायेगी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वर्ष 2010-12 के दौरान हजारीबाग शहरी हाट में प्रशिक्षित 10,275 शिल्पियों में से सिर्फ 1,511 शिल्पियों को वर्ष 2012-13 के दौरान उत्पादन में लगाया गया था।

विक्रय एवं प्रचार

2.23 कम्पनी ने विज्ञापन एवं प्रसार के लिए कोई नीति प्रतिपादित नहीं की थी। कम्पनी ने विज्ञापन एवं प्रचार त्योहार के मौसम में एवं नये इम्पोरियम खोलकर किया।

मूल्य निर्धारण नीति

2.24 कम्पनी ने बिना तर्कसंगत विश्लेषण के हस्तकरघा उत्पादों की लागत मूल्य में लागत का 50 प्रतिशत वृद्धि कर अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया (फरवरी 2008)।

हस्तकरघा उत्पादों के रिकार्ड का नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान उत्पादन के लागत मूल्य ₹ 34.11 करोड़ पर अधिकतम विक्रय मूल्य ₹ 48.45 करोड़ निर्धारित किया था जो कि अपनाए

[42] शिल्पी @ ₹ 6,935 प्रति शिल्पी x ₹ 9,995 = ₹ 6.93 करोड

मूल्य निर्धारण नीति के पालन न करने के कारण ₹ 2.72 करोड़ की कम बिक्री हुई।

गए मूल्य नीति के अनुसार कुल ₹ 51.17 करोड़ होना था। इस प्रकार, कम्पनी ने 50 प्रतिशत लागत जोड़े बिना अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किया तथा स्वयं द्वारा अपनाये गए मूल्य नीति से हटकर काम किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़ कम विक्रय वसूली हुई।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार करते हुए कहा (दिसम्बर 2013) कि कुछ उत्पादों में कम मार्जिन जोड़ा गया ताकि उत्पादों को बेचा जा सके। यह कहा गया कि वर्ष 2013-14 में सभी प्रकार के उपरिव्यय तथा उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करते हुए लागत मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। तथा आश्वस्त किया कि कम्पनी को अधिक प्रतियोगी तथा लाभदायक बनाने के लिए इस मामले की पुन: जाँच की जाएगी।

इम्पोरियम की दक्षता

2.25 कम्पनी हस्तकरघा तथा हस्तशिल्प उत्पादों को वर्ष 2008-09 से अपने इम्पोरियम में बिक्री करता है। इम्पोरिया की संख्या वर्ष 2008-09 में तीन[43] थी, जो बढ़कर वर्ष 2012-13 में 12[44] हुआ। कम्पनी इन इम्पोरियम को खोलने से पहले किसी प्रकार के बाजार सर्वेक्षण तथा इसकी व्यवहार्यता का निर्धारण नहीं किया था। इसने इम्पोरियम के लिए बिक्री का लक्ष्य भी तय नहीं किया था। 31 मार्च 2013 को समाप्त हो रहे पिछले पाँच वर्षों तक की इम्पोरियम की संचालन लाभ-हानि को ***तालिका - 2.2*** में दर्शाया गया है:

तालिका - 2.2

(₹ लाख में)

वर्ष	इम्पोरियम की संख्या	सकल विक्रय	दिया गया छूट	शुद्ध बिक्री	बिक्रीत माल की लागत	इम्पोरियम के खर्चे	परिचालन लाभ/(-)हानि	सकल बिक्री पर परिचालन हानि का प्रतिशत
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8=5-(6+7)	9=8/3x100
2008-09	3	82.57	14.04	68.53	55.32	53.06 (64)	(-) 39.85	48
2009-10	7	150.96	25.99	124.97	101.14	112.63 (75)	(-) 88.80	59
2010-11	9	288.25	43.80	244.45	193.13	223.76 (78)	(-) 172.44	60
2011-12	12	335.77	49.17	286.60	224.97	226.39(67)	(-) 164.76	49
2012-13	12	573.95	105.07	468.88	384.55	409.76 (71)	(-) 325.43	57
कुल परिचालन हानि							**(-) 791.28**	

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

कोष्ठक में दिए गए अंक इम्पोरिया का व्यय को सकल बिक्री का प्रतिशत में बतलाया गया है।

[43] रोसपा टावर, राँची, बंगलुरु और दिल्ली इम्पोरियम

[44] दिल्ली, बंगलुरु, मुम्बई, पुणे, अहमदाबाद, मैसूर, डाल्टेनगंज, हजारीबाग, रोसपा टावर, चर्च कम्पलेक्स, हरमू और मेगा स्टोर, राँची

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान एम्पोरिया के माध्यम से बिक्री से ₹ 7.91 करोड़ की परिचालन हानि।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी को इन इम्पोरियम के संचालन में वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक ₹ 7.91 करोड़ की हानि हुई। वर्ष 2008-09 से 2012-13 में संचालन हानि का प्रतिशत सकल विक्रय के 48 प्रतिशत से बढ़कर 57 प्रतिशत हो गई। हानि का मुख्य कारण इम्पोरियम की लाभ मार्जिन[45] की तुलना में अधिक खर्च था। इस संबंध में यह भी प्रासंगिक है कि हजारीबाग इम्पोरियम को छोड़कर सभी इम्पोरियम को वर्ष 2012-13 के दौरान हानि हुई थी। हजारीबाग में स्थित इम्पोरियम लाभ में चल रही थी, क्योंकि यह शहरी हाट में अवस्थित है जहाँ इस शहरी हाट का किराया देने की जिम्मेदारी कम्पनी की नहीं थी तथा विविध खर्च को शहरी हाट के खाते में दिखाया गया था। वर्ष 2012-13 में इम्पोरियम के संचालन व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि होने के मुख्य कारण राँची स्थित नये मेगा स्टोर पर किये गये ₹ 1.28 करोड़[46] स्थापना व्यय था।

आगे यह भी पाया गया कि वर्ष 2009-10 में स्थापित पूणे एवं मुम्बई स्थित इम्पोरियम एवं वर्ष 2010-11 में स्थापित डाल्टेनगंज इम्पोरियम का संचालन व्यय प्रारम्भ से लेकर 2012-13 तक कुल बिक्री से अधिक थे। कम्पनी को प्रत्येक इम्पोरियम का संचालन व्यय की समीक्षा करते हुए वाणिज्यिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना चाहिए था। कम्पनी ने उपरिव्यय का कोई मानक भी निर्धारित नहीं किया था।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 में बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। मेगा स्टोर का संचालन व्यय भ्रामक था क्योंकि इसमें किराया और कर्मचारियों का वेतन का खर्च ₹ 1.28 करोड़ तथा मेला खर्च ₹ 38 लाख शामिल थे। अगर इन व्ययों को अलग किया जाय, तो संचालन व्यय कम होगा।

उत्तर सही है कि सकल बिक्री में 5.95 गुना की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई लेकिन इसी समय (2008-09 से 2012-13) में संचालन लागत 6.72 गुना बढ़ गया था जो कुल बिक्री में वृद्धि को नकार रहा था। मेगा स्टोर का किराया और उसमे कार्यरत कर्मचारी का वेतन आवर्ती व्यय है। इसलिए इस व्यय को इम्पोरियम के संचालन व्यय से अलग नहीं किया जा सकता है। साथ ही मेगा स्टोर के व्यय में मेला व्यय शामिल नहीं था।

---

[45] शुद्ध विक्रय घटाव बिक्रीत माल की लागत।

[46] इम्पोरियम के किराया ₹ 6.00 लाख प्रतिमाह सम्मिलित।

फ्रैंचाइजी का प्रदर्शन

2.26 कम्पनी अपनी उत्पादों को फ्रैंचाइजी दुकानों द्वारा भी बेचते हैं। कम्पनी ने फ्रैंचाइजी की नियुक्ति के लिए कोई नीति नहीं अपनायी थी और इच्छुक एजेन्सी द्वारा कम्पनी से सीधे सम्पर्क स्थापित करने पर फ्रैंचाइजी के रूप में नियुक्त किये जाते थे। मार्च 2013 तक कम्पनी के पास पाँच[47] फ्रैंचाइजी थे। सभी पाँच फ्रैंचाइजी के खुदरा दुकानों का 2010-11 से 2012-13[48] की अवधि में प्रर्दशन ***तालिका - 2.3*** में दिया गया है:

तालिका - 2.3

(₹ लाख में)

वर्ष	शुद्ध बिक्री	बिक्रीत माल की लागत	सकल लाभ	विक्रय व्यय			परिचालन हानि
				फ्रैंचाइजी को भुगतान	अन्य व्यय	विक्रय पर कुल खर्च	
1	2	3	4=(2-3)	5	6	7=(5+6)	8=(4-7)
2010-11	7.70	6.41	1.29	2.14	-----	2.14(28)	(-) 0.85
2011-12	61.58	50.38	11.20	15.43	11.91	27.34(44)	(-) 16.14
2012-13	104.13	86.82	17.31	22.07	20.07	42.14(40)	(-) 24.83
कुल	**173.41**	**143.61**	**29.80**	**39.64**	**31.98**	**71.62(41)**	**(-) 41.82**

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

कोष्ठक में दिये गए अंक शुद्ध विक्रय में विक्रय व्यय की प्रतिशतता को सूचित करता है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान कम्पनी ने फ्रैंचाइजी दुकानों द्वारा अपनी उत्पादों की बिक्री से ₹ 41.82 लाख हानि वहन किया।

हमने पाया कि कम्पनी ने कलाकृति, वाराणसी के साथ पाँच वर्ष के लिए एक फ्रैंचाइजी अनुबंध किया (मार्च 2011)। अनुबंध के अनुसार फ्रैंचाइजी द्वारा उत्पादों की बिक्री आय का 28 प्रतिशत कम्पनी को देना था तथा कम्पनी के पास ₹ पाँच लाख का बैंक गारण्टी जमा करना था। यद्यपि कम्पनी ने अनुबंध को संशोधित (अक्टूबर 2011) कर भूतलक्षी प्रभाव से जून 2011 से लागू किया, जो फ्रैंचाइजी के आग्रह के बगैर और बिना किसी लिखित कारणों से किया गया। संशोधित अनुबंध के अनुसार फ्रैंचाइजी द्वारा बिक्री आय का 20 प्रतिशत कम्पनी को देने तथा कम्पनी द्वारा मासिक किराया के रुप में ₹ 80,000, रख-रखाव खर्च ₹ 4,000 प्रतिमाह और कम्पनी द्वारा प्रतिनियुक्त एक स्टोर प्रबंधक का वेतन की भुगतान का प्रावधान किया गया था। बैंक

[47] संतोष टेक्सटाइल्स, दुमका; अनामिका, पटना; कलाकृती, वराणसी और दो कोलकाता के फ्रैंचाइजी

[48] कम्पनी ने फ्रैंचाइजी के माध्यम से बिक्री 30 अप्रैल 2010 से शुरू किया

गारण्टी देने की शर्त को भी कम्पनी ने हटा लिया। इस प्रकार, अनुबंध में फेर-बदल करने के कारणों का रिकार्ड में नहीं होने से अनुबंध के संशोधन करने के मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं हो सका। फ्रैंचाइजी को बढ़ावा देने के बावजूद कम्पनी कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकी और इसे हानि वहन करना पड़ा।

समझौते में पूर्वप्रभावी संशोधन के कारण ₹ 16.74 लाख का अतिरिक्त व्यय।

मूल समझौते के अनुसार कम्पनी द्वारा फ्रैंचाइजी को वर्ष 2011-12 और 2012-13 में ₹ 9.25 लाख भुगतान करना था, जबकि संशोधित अनुबंध के अनुसार कम्पनी ने ₹ 25.99 लाख खर्च किया। इस प्रकार, अनुबंध के शर्तों में फेर-बदल कर फ्रैंचाइजी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया तथा कम्पनी के वित्तीय हितों को नजर अंदाज करते हुए ₹ 16.74 लाख अतिरिक्त व्यय किया गया।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि दोनों तरह के फ्रैंचाइजी प्रारूप का अनुसरण किया जा रहा था। जवाब में बिना किसी कारण दर्ज किये पूर्व प्रभाव से कलाकृति, वाराणसी के साथ अनुबंध में संशोधन करने के मामले में कुछ नहीं कहा गया था।

तथापि, वस्तुस्थिति यह है कि कम्पनी ने न तो फ्रैंचाइजी नियुक्त करने से पहले कोई लागत लाभ विश्लेषण किया और न कोई मासिक बिक्री लक्ष्य तय किया जिससे लाभ अर्जन की स्थिति तक पहुँचा जा सके। कम्पनी अनुबंध को पूर्व प्रभाव से बदलते समय अपनी वित्तीय हितों को ध्यान में रखने में असफल रही, जिसके परिणाम स्वरुप बिना किसी बिक्री आय के अतिरिक्त वित्तीय व्यय हुआ।

शहरी हाट

2.27 झारखण्ड सरकार ने भारत सरकार की सहायता से हजारीबाग में एक शहरी हाट स्थापित किया (2005-06) जिसमें कलाकारों एवं बुनकरों को स्थायी विपणन सुविधा प्रदान किया जा सके तथा अपने उत्पादों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे ग्राहकों को बिक्री कर सकें।

कम्पनी ने जिला प्रशासन, हजारीबाग से शहरी हाट का स्वामित्व प्राप्त कर (मार्च 2010) इसके प्रबंधन को क्राफ्टेज कंसल्टेंट (एजेन्सी) को दे दिया (मार्च 2010)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी इसके पहले अक्टूबर 2008 में इस एजेन्सी के साथ एक अधिकृत बाजार साझेदार के रूप में अनुबंध किया था, जिसमें तसर रेशम और हस्तनिर्मित उत्पादों को देश में तथा देश के बाहर

बिक्री करना था। यद्यपि, एजेन्सी मार्च 2010 तक कुछ भी बिक्री नहीं कर सकी।

कम्पनी के कार्यालय आदेश के अनुसार एजेन्सी को आवश्यक बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं की स्थापना, शहरी हाट चालू रखने के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और हस्तनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन के लिए कलाकारों के कार्य दलों को भर्ती करना था। एजेन्सी शहरी हाट के सभी तरह के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी था तथा इसे कम्पनी की देख-रेख में और इसके अधीन रहकर कार्य करना था जिसके लिए एजेंसी को प्रतिमाह कुल ₹ 35,000 का भुगतान करना था।

इसके अलावा, इस संबंध में अवलोकित अनियमितताएं नीचे दी गई हैं:

- शहरी हाट का प्रबंधन मार्च 2010 में कार्यालय आदेश निर्गत कर मनोनयन के आधार पर कम्पनी के निदेशक मंडल की संस्तुति के बिना, निविदा और पिछले कार्य दक्षता का मूल्यांकन किये बिना निर्धारण कर लिया गया।

शहरी हाट का प्रबंधन निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन किये बिना संस्था को सौपा गया।

- शहरी हाट प्रबंधन एजेन्सी के नियुक्ति हेतु निविदा नहीं निकाला गया था (जुलाई 2013), जबकि कम्पनी के निदेशक मंडल ने निविदा मंगाने के लिए प्रशासनिक अनुमति प्रदान किया था (जून 2012)।
- कम्पनी ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान एजेंसी को उनके आवेदन के तहत ₹ 9.35 करोड़[49] अग्रिम भुगतान बिना किसी सुरक्षा /बैंक गारण्टी पर किया जो इस पर न्यस्त कार्य क्षेत्र के बाहर था। उसमें से ₹ 5.34 करोड़ मार्च 2013 तक समायोजित नहीं किया गया था। एजेन्सी ने कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के बिना ही कच्चे मालों की खरीद की। कच्चे मालों के तुलनीय दरों के अनुपलब्धता के कारण हमारे द्वारा दर का औचित्य तय नहीं किया जा सका।
- शहरी हाट ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 में क्रमश: 5,155 मीटर और 4,256 मीटर कपड़ा का उत्पादन ₹ 151 प्रति मीटर तथा ₹ 378 प्रति मीटर की औसत लागत से किया। इस प्रकार वर्ष 2011-12 और

[49] कच्चे माल के क्रय पर ₹ 5.51 करोड़, बुनकरों एवं शिल्पियों के मजदूरी भुगतान और डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण पर और पी.डब्ल्यु.सी.एस. एवं सी.एफ.सी. योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये ₹ 3.84 करोड़।

2012-13 के दौरान पन्द्रह क्लस्टर[50] में फेब्रिक की औसत उत्पादन लागत क्रमश: ₹ 85 एवं ₹ 138 प्रति मीटर था। परिणामस्वरूप, शहरी हाट में बुने गये कपड़ों का उत्पादन लागत ₹ 13.57 लाख अधिक हुआ। उच्च उत्पादन लागत का कारण बुनकरों को निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना था, जबकि क्लस्टर में उत्पादन आधारित पारिश्रमिक का भुगतान किया गया।

यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि कम्पनी शिल्पियों और बुनकरों को बिना किसी मध्यस्थ के अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों के बीच बिक्री के लिए स्थायी विपणन केन्द्र उपलब्ध कराने में असफल रही। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कम्पनी ने उत्पादन के लिए कच्चे माल के क्रय पर ₹ 1.24 करोड़ खर्च किया जो शहरी हाट के संचालन के उद्देश्यों के बाहर था। शहरी हाट का सकल बिक्री वर्ष 2011-12 में ₹ 15.85 लाख था जो वर्ष 2012-13 में घटकर ₹ 8.25 लाख हो गया। इस प्रकार शहरी हाट के स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि उचित निविदा प्रक्रिया का अनुपालन तथा निदेशक मंडल की अनुमोदन के पश्चात् शहरी हाट के प्रबंधन के लिए एजेंसी का चयन किया गया था (अक्टूबर 2008) और शहरी हाट का प्रबंधन सौंपा गया था (मार्च 2010), क्योंकि यह कम्पनी का विपणन साझेदार था। पर्याप्त मानव शक्ति के कमी के कारण सभी क्रय प्रक्रियाओं एवं अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा सका।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निदेशक मण्डल के कार्यवृत्त के अनुसार एजेन्सी ने विपणन हेतु प्राधिकृत एजेन्ट के रूप में कार्य करने के लिए कम्पनी को आग्रह किया था एवं निदेशक मण्डल का अनुमोदन (सितम्बर 2008) विपणन साझेदार की नियुक्ति के लिए था न कि शहरी हाट के प्रबंधन एवं हस्तशिल्प के उत्पादन के लिए। इसके अलावा, बिक्री में कमी आई जैसा कि ऊपर में वर्णित है।

क्राफ्टेज एप्रैल्स को निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन न करके अनुचित लाभ पहुँचाया।

2.28 हमने, इसके अलावा, अवलोकित किया कि कम्पनी ने क्राफ्टेज एप्रैल्स के साथ एक अनुबंध किया (अगस्त, 2009) जो क्राफ्टेज कंसलटेन्ट की एक अनुषंगी इकाई है, जिसका स्वामित्व भी एक है। इसके तहत बिना निदेशक मण्डल की स्वीकृति एवं किसी कोटेशन/निविदा मांगे बने बनाये वस्त्रों की

[50] खरसावाँ, आकर्षणी, सिकनी, जियाजोरी, बोआरीजोर, गोड्डा, पोरेयाहाट, फसिया, सरैयाहाट, पचरुखी, मनियारडीह, महुआडाबर, बालथर, जमुनिया एवं हजारीबाग।

सिलाई का कार्य दिया गया। कम्पनी ने मार्च 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि में क्राफ्ट्रेज एप्रैल्स को कम्पनी के लिए कुर्तों के सिलाई हेतु सामानों के क्रय के लिए ₹ 46.06 लाख का भुगतान किया जिसमें मार्च/ अप्रैल 2012 में बिना किसी जमानत के दिये गये ₹ 10 लाख ब्याज रहित अग्रिम शामिल था। ₹ 10 लाख अग्रिम का समायोजन नहीं हो सका था (मार्च 2013)। पुन: यह देखा गया कि क्राफ्ट्रेज एप्रैल्स को सिलाई इकाई के स्थापना हेतु झारखण्ड सरकार के विभाग के अंतर्गत राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा कम्पनी की अनुशंसा पर अनुचित लाभ पहुंचाते हुए भूमि का आवंटन किया गया। कम्पनी ने एजेंसी के साथ विपणन हेतु समझौता किया यद्यपि, एजेंसी द्वारा कोई विपणन कार्य नहीं किया गया था।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि क्राफ्टेज एप्रैल्स को सिलाई का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि प्रतिष्ठान को सिले कपड़े बनाने का पर्याप्त अनुभव था एवं प्रतिष्ठान को अग्रिम भी दिया गया क्योंकि यह नवगठित था।

यह उत्तर कि एक नयी स्थापित प्रतिष्ठान को सिले वस्त्रों को बनाने का अच्छा अनुभव है अपने आप में विरोधात्मक है। पुन: कम्पनी को एक वाणिज्यिक इकाई होने के नाते अपने वित्तीय हितों की रक्षा करना है एवं कार्य दिये जाने एवं भुगतान करने में उचित प्रक्रिया का पालन करना है।

वित्तीय प्रबंधन

2.29 कम्पनी अपने दिन प्रतिदिन के क्रिया कलापों को अपने आंतरिक स्रोतों[51] और झारखण्ड सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान से वेतन एवं अन्य व्ययों[52] का भुगतान कर पूरी करती है। कम्पनी ने रेशम कीट पालन, हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प के विकास हेतु योजना के कार्यान्वयन के लिए झारखण्ड सरकार एवं भारत सरकार से पर्याप्त राशि प्राप्त किया जिसमें कार्यशील पूँजी की राशि शामिल है। वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक कम्पनी का प्रचालन दक्षता ***तालिका - 2.4*** दिखाया गया है

[51] बिक्री से आय, योजना अन्तर्गत प्राप्त पर्यवेक्षण प्रभार, बैंक जमा से प्राप्त ब्याज आदि।

[52] वेतन, कार्यालय व्यय, दुकानों का किराया, दुकानों की आंतरिक सजावट, मेला प्रदर्शनी एवं विज्ञापन इत्यादि के व्यय के भुगतान हेतु झारखण्ड सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान।

तालिका - 2.4

(₹ लाख में)

विवरण	वर्ष			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बिक्री	222.07	653.58	1280.09	1867.89
योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकारी अनुदान	150.31	996.65	2331.42	2119.06
अन्य आय	9.82	8.06	643.81	689.59
कुल आय	**382.20**	**1658.29**	**4255.32**	**4676.54**
वस्तुओं का उत्पादन लागत	216.55	677.06	1126.36	1286.42
प्रशासनिक व्यय	103.39	178.01	472.46	604.38
विक्रय एवं वितरण व्यय	41.54	37.50	210.79	454.96
ब्याज	1.13	0.46	10.86	95.83
ह्रास	17.66	21.36	47.82	71.27
पूर्व अवधि व्यय	-	-	7.75	(-)1.59
कुल व्यय	**380.27**	**914.39**	**1876.04**	**2511.27**
सरकारी अनुदान का उपयोग	-	669.83	2331.42	2119.06
अनुदान के उपयोग को सम्मिलित कर कुल व्यय	380.27	1584.22	4207.46	4630.33
कर भुगतान	**1.93**	**74.07**	**47.87**	**46.21**

(स्रोत: वार्षिक लेखों के संग्रहित आँकड़े)

टिप्पणी:- कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 का लेखा तैयार नहीं किया है।

हमने देखा कि 2008-09 में अन्य आय[53] ₹ 9.82 लाख था जो 2011-12 में बढ़कर ₹ 6.90 करोड़ हो गया जो मुख्यत: झारखण्ड सरकार के योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पर्यवेक्षण प्रभार के रूप में 2010-11 एवं 2011-12 में प्राप्त क्रमशः ₹ 5.01 करोड़ एवं ₹ 5.76 करोड़ के कारण थी।

कम्पनी ने 2008-09 से 2012-13 के दौरान झारखण्ड सरकार से वेतन, अपने दुकानों के किराया एवं सजावट, मेला एवं प्रदर्शनी में भाग लेने, योजनाओं के विज्ञापनों, डिजाइन विकास, कार्यालय व्यय इत्यादि पर व्यय के भुगतान हेतु सहायता के रूप में ₹ 10.13 करोड़[54] का प्रबंधकीय अनुदान प्राप्त किया जिससे कि कम्पनी स्वयं का व्यय वहन करने योग्य हो सके। हमने, तथापि देखा कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए प्रबन्धकीय अनुदान प्राप्त न होने की स्थिति में कम्पनी का कर पूर्व लाभ उपरोक्त वर्षों के लिए हानि में बदल जाता। इस प्रकार, कम्पनी अपने प्रचालन व्ययों का भुगतान करने में असमर्थ थी और अपने स्थापना के छः वर्ष बाद भी झारखण्ड सरकार पर आश्रित थी।

---

[53] पर्यवेक्षण प्रभारों, परामर्शी प्रभारों, बैंक जमा पर ब्याज इत्यादि को सम्मिलित कर।

[54] 2008-09 में 50 लाख, 2009-10 में ₹ 1.63 करोड़, 2010-11 में ₹ 2 करोड़, 2011-12 में ₹ 3 करोड़, 2012-13 में 3 करोड़ सरकारी अनुदान में शामिल है।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि कम्पनी पाँच वर्ष पूर्व निगमित हुई है, इसलिए इसे लाभ-अलाभ की स्थिति पर पहुँचने में समय लग सकता है।

कम्पनी ने अपने वित्तीय हितों को ध्यान में नहीं रखा जैसा कि कंडिका संख्या 2.24 से 2.28 एवं अनुवर्ती कंडिकाओं में विनिर्दिष्ट किया गया है।

साख नीति एवं विविध देनदार

2.30 कम्पनी प्रबंध निदेशक के पूर्व अनुमति से अपने हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प के विभिन्न उत्पादों को केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकार के विभागों/उपक्रमों को उधार पर बिक्री कर रही थी। इसके परिणामस्वरूप लम्बित ऋण 2008-09 में ₹ 37.22 लाख से बढ़कर मार्च 2013 को ₹ 8.30 करोड़ हो गयी। कम्पनी ने ऋणों का वर्षवार विश्लेषण नहीं बनाया था ताकि इसकी वसूली हेतु अनुश्रवण एवं अनुसरण किया जा सके।

यह देखा गया कि कम्पनी ने राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति (एन.जी.ओ.सी) को 2010-11 के दौरान ₹ 1.97 करोड़ के मूल्य का स्मृतिचिह्नों, झण्डे, सजावटी सामान, बैनर्स इत्यादि की आपूर्ति की। एन.जी.ओ.सी ने मात्र ₹ 1.39 करोड़ का भुगतान किया एवं खाता के अनुसार ₹ 58.28 लाख लम्बित था। इस प्रकार ₹ 58.28 लाख कार्य के पूर्ण होने (फरवरी 2011) के 34 माह के पश्चात् भी अप्राप्य रहा। कम्पनी ने एन.जी.ओ.सी से भुगतान के लिए अनुरोध किया (मई 2012) जिसने लम्बित राशि के संबंध में विस्तृत विपत्रों एवं कार्यादेशों की मांग की। कम्पनी के पास उचित अभिलेखों के अभाव में ₹ 58.28 लाख की वसूली की संभावना कम है।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि वे एन.जी.ओ.सी से बकाये को चुकाने के लिए लगातार सम्पर्क में है एवं आश्वस्त किया कि मार्च 2014 तक देनदारों की संख्या में बहुत हद तक कमी आ जायेगी।

2.31 कम्पनी के क्रय नियमावली[55] के अनुसार ₹ 10 लाख तक के आंतरिक सज्जा का कार्य को न्यूनतम तीन कोटेशनों को विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कर मूल्य के औचित्य को सुनिश्चित कर एवं ₹ 10 लाख से अधिक का कार्यों को खुली निविदा के द्वारा देना है।

[55] मार्च 2011 में कम्पनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित।

[56] के वस्तुओं का क्रय, क्रय समिति द्वारा बिना निविदा के एवं दर के औचित्य को सुनिश्चित किये किया गया, इस प्रकार क्रय नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

₹ 96.66 लाख के आंतरिक डिजाइन का कार्य अनियमित रुप से संस्था को देना।

इसी तरह, कम्पनी ने क्राफ्टेज कंसल्टेंट्स (एजेंसी) को अपने धनबाद एवं देवघर के इम्पोरियम के आंतरिक सज्जा का कार्य ₹ 96.66[57] लाख में, जिसमें 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार शामिल था, एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के आधार पर निविदा के बिना या अनुमानित लागत के औचित्य को सुनिश्चित किये बिना ही दिये, जैसा कि कंडिका सख्या 2.27 एवं 2.28 में भी विनिर्दिष्ट है। अग्रतर, कम्पनी ने एजेंसी को ₹ 28.05 लाख का ब्याज रहित अग्रिम बिना किसी सुरक्षा/बैंक गारण्टी के दिया। इस प्रकार, कम्पनी के एम्पोरियम/भण्डार के आंतरिक सज्जा का कार्य कंपनी के क्रय नियमावली में निहित प्रक्रियाओं के पालन के बिना दिया जा रहा था जिसके द्वारा एजेंसी को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा था तथा कम्पनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं किया जा रहा था।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि एजेंसी उनका साझीदार था एवं स्वयं सहायता समूहों के द्वारा कार्य की व्यवस्था किया एवं बढ़इयों के लिए जीवनयापन अवसरों को उत्पन्न किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने अपने क्रय नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

सामग्री प्रबंधन

2.32 मितव्ययी अधिप्राप्ति एवं इन्वेंटरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कम्पनी ने कोई अधिप्राप्ति नीति एवं इन्वेंटरी नियंत्रण तंत्र नहीं बनाया था। कम्पनी ने अपने सामग्री आवश्यकताओं के लिए न तो कोई ए.बी.सी. विश्लेषण किया था और न ही कोई अधिकतम/ न्यूनतम मानक स्तर या पुन: आदेश स्तर को नियत किया था। मार्च 2013 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के दौरान धारित इन्वेंटरी एवं कुल बिक्री ***तालिका - 2.5*** में दर्शाया गया है:

---

[56] दिलीप कॉन्टेक ₹ 8.78 लाख, साकेत सेल्स ₹ 3.69 लाख, पेलिकन इन्टरनेशनल ₹ 2.10 लाख एवं लक्की वाणिज्य ₹ 5.68 लाख।

[57] धनबाद इम्पोरियम ₹ 50.05 लाख, देवघर के इम्पोरियम एवं कैम्प कार्यालय ₹ 46.61 लाख।

तालिका- 2.5

(₹ लाख में)

वर्ष	कुल इन्वेंटरी	टर्नओवर	मासिक बिक्री के संदर्भ में स्टॉक
2008-09	445.75	222.07	24
2009-10	1472.73	653.58	27
2010-11	2599.60	1280.09	24
2011-12	3513.37	1867.89	23
2012-13 (प्रोविजनल)	4271.32	----	---

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

अंतिम स्टॉक महीनो के बिक्री के संदर्भ में 23 और 27 महीनों के बीच था।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि मासिक बिक्री की संख्या के संबंध में अंतिम स्टॉक 23 एवं 27 माह के मध्य निरंतर उच्च स्तर पर था। यदि कम्पनी इन्वेन्टरी नियंत्रण तंत्र को अपनाया होता तो इन्वेन्टरी स्तर को कम किया जा सकता था। कम्पनी ने अपने स्टॉक का आयु-वार विश्लेषण भी नहीं बनाया था।

सरकार ने लेखा परीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) और कहा कि इन्वेन्टरी प्रबंधन में और सुधार की आवश्यकता है एवं 2013-14 के अंत तक सभी प्रचालनों को ऑन-लाइन कर दिया जायेगा।

अधिक उत्पादन के कारण संचित सामग्री का निपटारा नहीं किया जाना

2.33 कम्पनी को फरवरी 2011 में झारखण्ड में हुए 34 वें राष्ट्रीय खेल के लिए ₹ 1.20 करोड़ का 14,450 स्मृति चिन्ह की आपूर्ति का एक आदेश राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति (एन.जी.ओ.सी.) से प्राप्त किया (दिसम्बर 2010)।

हमने देखा कि 14,450 स्मृतिचिह्नों के आदेशित मात्रा के विरुद्ध कम्पनी ने 17,470 स्मृति चिन्ह अर्थात आदेशित मात्रा से 3,020 स्मृतिचिह्नों का अधिक उत्पादन किया। इसके अलावा, स्मृतिचिह्नों की आपूर्तित मात्रा सिर्फ 12,646 था अर्थात आपूर्ति की गयी मात्रा 1,804 कम रही यद्यपि स्मृतिचिह्नों का उत्पादन अधिक मात्रा में किये गये थे। कम आपूर्ति का कारण दर्ज नहीं थे।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि उसने खेल विभाग, झारखण्ड सरकार से अबिक्रीत स्मृतिचिह्नों को बेचने के लिए अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था और यदि खेल विभाग कम्पनी के प्रस्ताव से सहमत नहीं होता है

तो अबिक्रीत स्मृतिचिह्नों को नये उत्पाद बनाने के लिए पुन: उपयोग किया जायेगा।

तथ्य यह है कि अगस्त 2012 में खेल विभाग, झारखण्ड सरकार के आग्रह किये जाने के बावजूद ₹ 37.10 लाख की सामग्री के निपटारे के लिए अब तक कोई कारवाई नहीं की गयी (नवम्बर 2013)।

इस प्रकार अधिक उत्पादन एवं सम्पूर्ण आदेशित मात्रा के प्रेषण में विफलता के कारण ₹ 34.91 लाख मूल्य के 4,824 स्मृतिचिह्न अबिक्रीत पड़े रहे। चूँकि स्मृतिचिह्न एक विशिष्ट अवसर के लिए डिजाइन एवं उत्पादित किये गये थे, उसके बिक्री की संभावना क्षीण है। पुनः, स्मृतिचिह्नों की कम मात्रा में आपूर्ति के कारण ₹ 2.19 लाख मूल्य के पैकिंग सामग्री[58] भी बिना उपयोग का पड़ा रहा।

मानव संसाधन प्रबंधन

2.34 कम्पनी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किया गया था। कम्पनी ने टीम लीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (अगस्त 2008) एवं आवरण सेवा केन्द्र (नवम्बर 2008) को मानव शक्ति का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया था। इसके पश्चात् कम्पनी ने ग्लोबल इन्नोव सोर्स साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड ("ग्लोबल इननोव") को अगस्त 2010 में टीम लीज के स्थान पर नियुक्त किया एवं कम्पनी द्वारा टीम लीज के माध्यम से नियुक्त मानवशक्ति को ग्लोबल इननोव को स्थानांतरित कर दिये गये। कम्पनी ने आउटसोर्सड एजेंसी के माध्यम से 267 लोगों की सेवाओं का उपयोग किया (मार्च 2013)।

हमने निम्नलिखित अवलोकित किया:

- कम्पनी ने कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नीति नहीं बनायी थी एवं मानवशक्ति के स्वीकृत बल को निर्धारित नहीं किया था।
- कम्पनी कर्मचारियों को स्वयं तीन से छ: महीने तक की परिवीक्षा पर नियुक्त करती थी एवं परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् कम्पनी उनके नामों को आउटसोर्सिंग एजेन्सियों के वेतन पत्रक में दर्ज करने के लिए भेजती थी।

[58] एन.जी.ओ.सी. के आवश्यकतानुसार छपाया गया, इसलिये अन्य पैकिंग आवश्यकता में उपयोग नहीं किया जा सकता।

- कम्पनी ने रेशम कीट पालन के सुगम प्रचालन के लिए 25 परियोजना प्रबंधकों की नियुक्ति की यद्यपि उनमें से मात्र सात ही आवश्यक व्यावसायिक योग्यता, यथा सेरिकल्चर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा रखते थे। कम्पनी के द्वारा परियोजना प्रबंधक को छोड़कर विभिन्न पदों के लिए पात्रता एवं योग्यता उल्लेखित नहीं थे।

- कम्पनी ने आउटसोर्सड कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी को शासित नियमों/विनियमों को निर्धारित नहीं किया था जिसे विवेक के आधार पर बढ़ाया जाता था। परिवीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी प्रबंधन के विवेक से आउटसोर्सड कर्मचारियों के नियुक्ति के पश्चात् दो महीने के अंदर वेतन को बढ़ाया गया।

- आउटसोर्सड कर्मचारियों का कम्पनी को छोड़कर जाने की दर बहुत ऊँची थी। अगस्त 2010 से अप्रैल 2013 के दौरान 142 कर्मचारियों ने कार्यभार ग्रहण किया एवं 1 से 1,003 दिनों की सेवा के पश्चात् कम्पनी को छोड़ दिया। यह कम्पनी के कार्यकुशलता को प्रभावित करता है।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) और कहा कि सभी परियोजना प्रबंधक सेरीकल्चर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार 25 परियोजना प्रबंधक में से 18 के पास सेरीकल्चर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा नहीं थे।

अनुश्रवण और आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण

2.35 कम्पनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पालन कर रही थी जैसे कि माल का स्थानांतरण केवल चालान के बनने पर ही होना, विक्रय वसूली ठीक अगले ही दिन बैंक में जमा कर देना, कार्यादेश महाप्रबंधक (प्रचालन) के पूर्व अनुमोदन से जारी करना। हालांकि, निम्नलिखित कमियों को आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र में देखा गया:

- विभाग ने रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की बारीक अनुश्रवण के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया था।

- कम्पनी ने हस्तकरघा और हस्तशिल्प के भौतिक प्रगति का अनुश्रवण के लिए तंत्र नही बनाया।

- विभाग ने कार्यशालाओं के निर्माण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया था जैसा कि कंडिका संख्या 2.15 और 2.17 से 2.19 में उल्लेखित है।

- कम्पनी ने रीलरों और स्पीनरों द्वारा कोकून से उत्पादित धागे का अनुश्रवण के लिए कोई नियंत्रण तंत्र विकसित नहीं किया था और कम्पनी ने व्यक्तिगत रीलरों और स्पीनरों को जारी किए गए कोकूनों की संख्या तथा उनसे प्राप्त धागे का कोई आंकड़ा संकलित नहीं किया था जैसे की कंडिका 2.14 में उल्लेखित हैं।

- यद्यपि कम्पनी के पास क्रय, उत्पादन और बिक्री की मासिक समीक्षा प्रणाली थी, एम्पोरियम की बिक्री को छोड़कर कम्पनी के स्तर पर प्रतिवेदन संकलित नहीं किये गये थे। इस तरह क्रय, उत्पादन और बिक्री की एक समेकित प्रतिवेदन के अभाव में उचित प्रबंधकीय निर्णय संभव नहीं था। यह प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) के अनुश्रवण और अनुवर्तन में कमी ला सकता है।

- विभाग के पास कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र को सत्यापित करने का कोई तंत्र नहीं था जैसा कि कंडिका संख्या 2.15 और 2.19 में उल्लेखित है। विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए था कि खर्च, कार्य की भौतिक प्रगति से मिलना चाहिए।

- कम्पनी ने करघा, रिलिंग और स्पीनिंग मशीनों के क्रय तथा उनके वितरण का योजनावार कोई आंकड़ा और स्टॉक पंजी संधारित नहीं किया जैसा कि कंडिका संख्या 2.15 और 2.19 में उल्लेखित है। इसके अभाव में उपयोग किये गये कोष का अनुश्रवण कंपनी द्वारा नहीं किया जा सका।

- कम्पनी ने अपने आर्थिक हितों की रक्षा नहीं की जैसा कि कंडिका संख्या 2.24 से 2.28, 2.30 और 2.31 में उल्लेखित है।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि विभाग/कम्पनी द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण प्रत्येक महीने किया गया था।

तथ्य यह है कि योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुश्रवण में सुधार की आवश्यकता है।

निदेशक मंडल/लेखापरीक्षा समिति की बैठक

2.36 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 285 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को हर तीन महीने में कम से कम एक बार निदेशक मंडल की बैठक करनी थी और साल में इस तरह की कम से कम चार बैठकें आयोजित करनी थी। यह देखा गया कि कम्पनी ने वर्ष 2012-13[59] की दूसरी तिमाही में बोर्ड का कोई बैठक आयोजित नहीं किया। निदेशक मंडल के नियमित बैठक के अभाव में निदेशक मंडल कम्पनी के गतिविधियों का अनुश्रवण नहीं कर सका।

इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292-ए के तहत प्रत्येक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी जिसकी चूकता पूँजी रुपये पाँच करोड़ से कम नहीं है, उसे बोर्ड स्तर पर एक लेखापरीक्षा समिति गठित करनी चाहिए। हालांकि, कम्पनी ने नवम्बर 2013 तक लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया था। इसके कारण निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा तथा आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

आंतरिक लेखापरीक्षा

2.37 कम्पनी में आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए कोई व्यवस्था अक्टूबर 2010 तक नहीं थी। कम्पनी ने अभी तक (नवम्बर 2013) आंतरिक लेखापरीक्षा मैन्युअल तैयार नहीं की थी। कम्पनी ने चार्टर्ड एकाउंटेंट के एक प्रतिष्ठान को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आउटसोर्स किया। आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की जाँच, वस्तुओं और सेवाओं के लिए खरीद प्रक्रिया का पालन, सम्पत्ति और इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन इत्यादि सम्मिलित था। हालांकि, आंतरिक अंकेक्षक ने रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपयोग किये गये निधि और इम्पोरियम/फ्रैंचाइजी के प्रदर्शन की जाँच नहीं की।

---

[59] कम्पनी ने बोर्ड की बैठक कराने के प्रावधान का अप्रैल 2007 से दिसम्बर 2011 तक आठ बार उल्लंघन किया था जिसमें दो बैठकों के बीच अधिकतम समय अंतराल 7 महीने 3 तीन तक था; जो वर्ष 2013 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 2, झरखण्ड सरकार में पहले ही प्रतिवेदित है।

सरकार ने आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) तथा उपचारात्मक कारवाई का आश्वासन दिया।

निष्कर्ष

विभाग ने रेशम कीट पालन के लिए 12 और पी.पी.सी. की स्थापना के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की, हालांकि, भौतिक दृष्टि से हस्तकरघा और हस्तशिल्प के लिए कोई लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किये गये। विभाग ने 12 पी.पी.सी की स्थापना का लक्ष्य हासिल किया। सी.एस.बी. के मापदंडों के विरुद्ध कोकून का उत्पादन कम था और सहायता अनुदान पूरी तरह नहीं दी गई थी, परन्तु रेशमदूतों से मिलने वाली राशि से उसे समायोजित कर लिया गया था। इसके अलावा, कम्पनी/विभाग द्वारा रेशम धागे के अनुमानित उत्पादन के साथ रिलरों और स्पीनरों को आपूर्ति किये गये कोकून का मिलान नहीं किया गया था। विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यशालाओं के निर्माण और बुनकरों को प्रशिक्षण के संबंध में लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी थी। विभाग ने कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। सभी इम्पोरियम/फ्रैंचाइजी दूकानें घाटे में थी। फ्रैंचाइजी की नियुक्ति, शहरी हाट के प्रबंधन और अन्य कार्यों को निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना दिया गया। एजेंसी और क्राफ्टेज एप्रैल्स को बिना किसी सुरक्षा/बैंक गारण्टी के अग्रिम विमुक्त किये गये थे। कम्पनी अपने परिचालन खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी और कोष की आवश्यकता के लिए झारखण्ड सरकार पर निर्भर थी। 2008-09 में विविध देनदार ₹ 37.22 लाख थे जो मार्च 2013 तक बढ़कर ₹ 8.30 करोड़ हो गये। कम्पनी ने मितव्ययी क्रय और इन्वेंटरी पर कुशल नियंत्रण के लिए कोई क्रय नीति और इन्वेंटरी नियंत्रण तंत्र तैयार नहीं किया था। आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र में कमी देखी गई और व्यापक एम.आई.एस. प्रणाली का अभाव था।

अनुशंसाएं

विभाग को चाहिए कि:

- कम्पनी द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनओं के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुश्रवण और समय-समय पर समीक्षा करना और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए तंत्र को विकसित करना; और

- कोकून के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रभावी कदम उठाना, रेशमदूत को पूर्ण नगद सहायता उनसे प्राप्य राशि के समायोजन के बिना देना।

कम्पनी को चाहिए कि:

- उनको सौंपे गए अधिदेशाधीन कार्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप नियोजन तैयार करना;

- रीलर और स्पीनर को आपूर्ति की गई कोकून से रेशम धागों के उत्पादन का अनुश्रवण;

- इम्पोरियम/फ्रैंचाइजी के माध्यम से बिक्री की लाभप्रदता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और विपणन के लिए प्रभावी कदम उठाना तथा अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए वित्तीय नियमों का अनुपालन;

- बेहतर इनवेंटरी प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक इनवेंटरी नियंत्रण पद्धति को अपनाना; और

- विभिन्न आंतरिक नियंत्रण तंत्र और एम.आई.एस. प्रणाली की स्थापना और सुदृढ़ीकरण।

अध्याय-III

अध्याय-III

3. लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों और सांविधिक निगम के लेन-देन की नमूना जाँच करने पर पाये जाने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सन्निहित है।

सरकारी कम्पनियाँ

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

3.1 केन्दु पत्ती की बिक्री में कमियाँ

प्रस्तावना

3.1.1 झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी), झारखण्ड सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम, झारखण्ड राज्य में केन्दु पत्ती[1], जो तम्बाकू लपेटने एवं बीड़ी[2] बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, के संग्रह एवं विपणन करने हेतु झारखण्ड सरकार का एक मात्र अभिकर्ता है। इसके कार्यकलाप का निष्पादन झारखण्ड केन्दु पत्ती (व्यापार-नियत्रंण) नियम, 1972, झारखण्ड केन्दु पत्ती (व्यापार-नियत्रंण) अधिनियम, 1973 एवं इसके अन्तर्गत नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया जाता है।

केन्दु पत्ती की अग्रिम बिक्री शुद्ध एकमुश्त राशि के आधार पर प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह अर्थात केन्दु पत्ती के संग्रहण मौसम शुरू होने से पहले (अप्रैल से जून) में निविदा द्वारा की जाती है। कम्पनी द्वारा केन्दु पत्ती के प्रत्येक लॉट[3] के बिक्री के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं पर अंतिम निर्णय झारखण्ड सरकार द्वारा गठित बिक्रय समिति[4] के द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् कम्पनी के निगमित कार्यालय में किया जाता है। उच्चतम निविदादाताओं के साथ निविदाओं के अंतिमीकरण के पश्चात् दस

---

[1] वानस्पतिक नाम डायसपायरस मेलानाक्सीलन।

[2] विशेषकर गरीब निवासियों के बीच प्रचलित धूम्रपान।

[3] लॉट प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र होते है, जिसमें क्षेत्र के आकार एवं केन्दु पत्ती की मात्रा के आधार पर एक या एक से अधिक इकाईयाँ सम्मिलित होती हैं।

[4] विक्रय समिति में वित्त विभाग, निगरानी विभाग, वन विभाग एवं कम्पनी के प्रतिनिधि प्रबंध निदेशक सहित सम्मिलित होते है।

दिनों के अन्दर अनुबंध किया जाता है। संग्रहण मौसम में केन्दु पत्ती तोड़ने वाले नई पत्ती संग्रह करते हैं और इनको संग्रहण केन्द्रों पर नियुक्त क्रेता के अधिकृत अभिकर्ता को सुपूर्द कर देते हैं। संग्रहण केन्द्रों पर संग्रहित केन्दु पत्ती की प्राप्ति के बाद, इन पत्तों को सुखाया तथा इन पर पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि ये नरम हो जाए और फिर इन्हें हैसियन बोरों में कस्ती किया जाता है, जो एक मानक बोरा कहलाता है जिसमें 1,000 पोले[5] होते हैं। कस्ती किये गये पत्ती को कम्पनी के या अधिकृत निजी गोदामों में परिवाहित किया जाता है जहाँ ये क्रेता द्वारा भुगतान एवं केन्दु पत्ती के उठाव तक दोहरे ताले प्रणाली में रखे जाते हैं, जिसमें एक ताला निगम का और दूसरा क्रेता का होता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

केन्दु पत्ती के विक्रय से संबंधित अभिलेखों के परीक्षण के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पाई गयी।

अबिक्रीत केन्दु पत्ती लॉट

3.1.2 अबिक्रीत लॉटों का तात्पर्य उन लॉटों से है जिनके लिए कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई या आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर निविदाएँ प्राप्त हुई और बिक्रय समिति द्वारा उस पर अग्रिम बिक्री के लिए विचार नहीं किया गया। ये अबिक्रीत लॉट, केन्दु पत्ती तोड़ने वालों के द्वारा संग्रहित नहीं किये गये और बिना-तोड़े[6] रह गये तथा बीड़ी बनाने के लिए उपयोगी नहीं थे।

हमने पाया कि कम्पनी ने 2009 से 2013 के मौसम के दौरान औसतन 10 से 15 बार अग्रिम बिक्री के लिए निविदाएँ आमंत्रित की ताकि ज्यादा से ज्यादा लॉट की बिक्री सुनिश्चित हो। लगातार अग्रिम बिक्री निविदाओं के बावजूद कुछ लॉट अबिक्रीत रह गए। मौसम 2009 से 2013 के दौरान बिक्रीत और अबिक्रीत केन्दु पत्ती लॉटों का विवरण ***तालिका-3.1.*** में दिये गये हैं।

---

[5] 50 केन्दु पत्ती के बण्डल को पोला कहा जाता है।

[6] केन्दु पत्ती लॉटों की तोड़ाई/संग्रहण मौसम के अवधि अप्रैल से जून अर्थात वर्षा मौसम से पहले होता है। मौसम में केन्दु पत्ती तोड़ने वाले बिक्रीत लॉटों से केन्दु की नई पत्तियाँ संग्रह करते हैं। मौसम के समाप्ति के पश्चात् पत्तियाँ अधिक परिपक्व हो जाती है। इस प्रकार केन्दु पत्ती के लॉट जो अग्रिम बिक्री निविदा के प्रक्रिया में अबिक्रीत रहते हैं, बिना तोड़े रह जाते हैं।

तालिका - 3.1

मौसम	कुल लॉटों की संख्या	बिक्रीत लॉटों की संख्या	अबिक्रीत लॉटों की संख्या	अबिक्रीत लॉटों की अधिसूचित उपज[7] (मानक बोरे)	अबिक्रीत लॉटों का आरक्षित मुल्य (₹ करोड़ में)
2009	297	237	60	132850	1.62
2010	295	240	55	126650	1.42
2011	298	279	19	34750	0.57
2012	296	290	06	17500	0.25
2013	299	200	99	266675	16.04
कुल	**1485**	**1246**	**239**	**578425**	**19.90**

(स्रोत: आँकड़े बिक्रय प्रतिवेदन से संकलित)

मौसम 2009 से 2013 के दौरान, अबिक्रीत केन्दु पत्ती लॉट 6 से 99 के बीच रहे। इस प्रकार, 239 अबिक्रीत लॉट से संबंधित केन्दु पत्ती के 5,78,425 मानक बोरे बिना तोड़े रह गए। केन्दु पत्ती की बिक्री निगम के आय का मुख्य स्रोत है और यह वन में रहने वाले गरीब एवं ग्रामीणों को भी मौसमी रोजगार प्रदान करता है। एक वाणिज्यिक इकाई होने के नाते कम्पनी को, अन्य वैकल्पिक रास्ते यथा विभागीय संग्रहण[8] जैसा कि तत्कालीन बिहार में उन लॉटों पर जो संबंधित संग्रहण मौसम के मार्च माह तक अग्रिम निविदा बिक्री में अबिक्रीत रह जाते थे, इन लॉट की तोड़ाई के लिये एक अग्रिम कार्य योजना बनाकर किया गया था और निदेशक मंडल के अनुमोदन से आरक्षित मूल्य कम कर तलाश करना चाहिए था जैसा कि झारखण्ड केन्दु पत्ती (व्यापार-नियत्रंण) अधिनियम, 1973 में वर्णित है। हालांकि, इस संबंध में कम्पनी द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

इस प्रकार, 239 लॉट से संबंधित केन्दु पत्ती के 5,78,425 मानक बोरे जिनका आरक्षित मूल्य ₹ 19.90 करोड़ था बिना तोड़े रह गये जिससे कम्पनी एवं राज्य कोषागार को राजस्व से एवं पत्ती तोड़ने वालों को रोजगार से वंचित होना पड़ा।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2013) कि आरक्षित मूल्य में कमी अगले मौसम के बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। सीमित क्रेता आपस में संगठित होकर लॉटों को बेचने के लिए आरक्षित मूल्य कम करेंगे जिससे मूल्य में प्रत्येक वर्ष कमी होगी। विभागीय संग्रह के लिए अतिरिक्त स्थापना और अन्य बुनियादी ढांचे

[7] संबंधित केन्दु पत्ती लॉट का उपज, राजपत्र अधिसूचना दिनांक 28 नवम्बर 1984 के अनुसार।

[8] विभागीय संग्रह - झारखण्ड गठन के पूर्व वैसे केन्दु पत्ती लॉट जो निलामी द्वारा नहीं बिक पाते थे, कम्पनी के पर्यवेक्षण में केन्दु पत्ती तोड़ने वालों द्वारा संग्रह करवाये जाते थे और सीधे क्रेताओं को बेचे जाते थे।

में अत्यधिक प्रारम्भिक निवेश की आवश्यकता होगी। इस संबंध में, पहले का अनुभव बहुत उत्साह वर्धक नहीं था। प्रबंधन ने आगे कहा कि इस मुद्दे को निदेशक मंडल के बैठक में रखा जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आरक्षित मूल्य तय करना कम्पनी का आंतरिक मामला है। अत: कम आरक्षित मूल्य के आधार पर संघ गठन का प्रश्न ही नहीं उठता। निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धी बोली के कारण क्रेता ऊँची कीमत अर्पण करेंगे ताकि लॉटों की खरीद कर सके। इसके अलावा, झारखण्ड केन्दु पत्ती (व्यापार-नियत्रंण) अधिनियम, 1973 के प्रावधान के अनुसार आरक्षित मूल्य को सक्षम प्राधिकारी के अनुशंसा पर कम किया जा सकता है। अबिक्रीत लॉट के विभागीय संग्रहण के संबंध में कम्पनी ने अपने निगमन के समय से कोई प्रयत्न नहीं किया यद्यपि केन्दु पत्ती का औसत बाजार मूल्य सभी प्रभारों सहित संग्रहण लागत से अधिक था। इसके अलावा कम्पनी ने अपने उत्तर के समर्थन में लगने वाले निवेश और अतिरिक्त स्थापना खर्च का विवरण उपलब्ध नहीं किया था।

दोषपूर्ण धारा के कारण क्रेताओं को अनुचित फायदा

3.1.3 अनुबन्ध के शर्तों तथा बंधेजों के धारा 1 के अनुसार यदि केन्दु पत्ती का परिदान अधिसूचित मात्रा से अधिक[9] किया जाता है तो क्रेता उस अतिरिक्त मात्रा का भुगतान सभी शुल्क एवं करों सहित करेगा। अधिसूचित मात्रा से अधिक प्राप्त केन्दु पत्ती की अतिरिक्त मात्रा के मूल्य की गणना मानक बोरों के औसत बिक्री दर के 50 प्रतिशत प्रति मानक बोरा के आधार पर किया जाएगा।

मौसम 2008 से 2012 के दौरान, 407 बिक्रित लॉटों में 10,55,325 मानक बोरों की अधिसूचित उपज के विरूद्ध, केन्दु पत्ती के 3,04,286 मानक बोरों का अतिरिक्त मात्रा संग्रहित हुआ; इस प्रकार इन लॉटों में कुल सकल संग्रहण 13,59,611 मानक बोरे हुए जो अधिसूचित उपज के 11.15 से 35.94 प्रतिशत तक थे। इन अतिरिक्त संग्रहित केन्दु पत्ती का बिक्रय मूल्य ₹ 15.10 करोड़[10] संगणित किया गया- ***परिशिष्ट - 3.1.***

---

[9] अतिरिक्त संग्रहण को क्रेता द्वारा अनिवार्य रूप से लिया जाएगा।

[10] (एक मुश्त विक्रय मूल्य/अधिसूचित उपज) x प्रत्येक लॉट के अतिरिक्त संग्रहण मानक बोरा में; गणना प्रत्येक लॉट के लिये जहाँ अतिरिक्त संग्रहण दर्ज थे।

क्रेता ने कम्पनी को अनुबंध की धारा के अनुसार संग्रहित पत्तियों के अतिरिक्त मात्रा के लिये संबंधित लॉट के अधिसूचित उपज के औसत मूल्य प्रति मानक बोरा का मात्र 50 प्रतिशत भुगतान किया। जबकि क्रेता उन पत्तियों के अतिरिक्त मात्रा के लिए बीड़ी बनाने वालों से पूरा मूल्य पाया। हमने पुन: अवलोकित किया कि कुल संग्रहण अतिरिक्त मात्रा सहित वन उत्पादकता संस्थान (आई.एफ.पी.), राँची द्वारा आकलित उपज के अन्दर थे।

इस प्रकार अनुबंध के त्रुटिपूर्ण धारा के तहत केन्दु पत्ती के अतिरिक्त संग्रहण पर 50 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जाना कम्पनी के वित्तीय हित के लिए हानिकारक है जिसके परिणामस्वरूप क्रेताओं को ₹ 7.55 करोड़ का अनुचित फायदा प्रदान किया गया-***परिशिष्ट - 3.1.***

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2013) कि अधिसूचित उपज के अतिरिक्त संग्रहण को प्रोत्साहित करने वाली वर्तमान नीति जिसके तहत औसत बिक्री दर के 50 प्रतिशत लिया जाता है, क्रेताओं को अधिक पत्ती संग्रह करने को प्रेरित करता है। यह कम्पनी को अतिरिक्त राजस्व देता है, अन्यथा क्रेता लक्ष्य से ज्यादा केन्दु पत्ती संग्रहण में रुचि नहीं लेंगे।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त सग्रंह को 50 प्रतिशत दर पर दिया जाना, कम्पनी के वित्तीय हित के लिए हानिकारक है। कम्पनी ने अधिसूचित उपज में संशोधन नहीं किया और केन्दु पत्ती के संभावित उपज का दोहन नहीं किया जैसा वन उत्पादक्ता संस्थान द्वारा आकलित किया गया। अधिसूचित उपज का संशोधन न करने और अपने व्यवस्था का अद्यतन न करने के परिणामस्वरूप क्रेताओं को सहायता पहुँचाया गया। इसके अलावा वन उत्पादक्ता संस्थान के प्रतिवेदन का अंगीकरण दिसम्बर 2010 से लंबित था जिससे अधिसूचित उपज में वृद्धि होती।

अनुबंध के शर्तों का अनुपालन न करने से केन्दु पत्ती के बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव

3.1.4 अनुबंध की धारा 7(बी)(i) के अनुसार, क्रेता को विक्रय मूल्य जमा करने के पश्चात् बिक्रीत पत्तियों को चार बराबर किस्त में उठाने का विकल्प है। इसके अलावा, अनुबंध की धारा 11 के अनुसार, यदि क्रेता नियत तिथि पर किस्त जमा करने में चूक करता है या अनुबंध के किसी अन्य शर्तों के अनुपालन में विफल रहता है तो कम्पनी अनुबंध को रद्द, प्रतिभूति राशि को जब्त और उक्त केन्दु पत्ती के विक्रय के लिए स्टॉक को जब्त और जब्त

स्टॉक की पुन: बिक्री से, यदि कोई हानि हो, तो उसकी वसूली क्रेता से कर सकती है।

हमने पाया कि कम्पनी ने 2011 मौसम में राँची प्रमंडल के खूँटी-ए लॉट को ₹ 25.75 लाख के शुद्ध एकमुश्त मूल्य पर बेचा और क्रेता[11] से अनुबंध किया (फरवरी 2011)। अनुबंध की वैधता मार्च 2012 तक थी और पत्तियों के सारे स्टॉक को अनुबंध की वैधता अवधि के अंदर उठाना था। क्रेता ने मई-जून 2011 में संग्रहित 753.250 मानक बोरा को विभागीय गोदाम में भंडारित किया।

हमने अवलोकित किया कि क्रेता ने अनुबंध के वैधता अवधि के दौरान कोई भी किस्त जमा नहीं किया। क्रेता द्वारा ₹ 3.20 लाख विस्तार शुल्क जमा करके 30 जून 2012 तक की अवधि विस्तार का आवेदन किया गया (अप्रैल 2012) और पुन: 10 अक्टूबर 2012 तक समय विस्तार के लिए आवेदन किया (सितम्बर 2012) जिसे मंजुर नहीं किया गया। अनुबंध की धारा 11 की अनदेखी करते हुए और केन्दु पत्ती के नश्वर प्रकृति को जानते हुए भी कम्पनी द्वारा न तो अनुबंध को रद्द किया गया न ही केन्दु पत्ती को जब्त किया गया। अनुबंध को विलम्ब से दिसम्बर 2012 को रद्द किया गया एवं प्रतिभूति राशि ₹ 9.65 लाख विस्तार शुल्क सहित जब्त किया गया। कम्पनी द्वारा वैधता अवधि के एक वर्ष दो माह गुजर जाने के पश्चात् जब्त स्टॉक के दो वर्ष पुराने होने एवं पत्तियों के नश्वर प्रकृति के कारण नीलामी द्वारा (मई 2013) बेचने का प्रयास साकार नहीं हो पाया परिणामत: ₹ 12.90 लाख की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर, 2013) कि जब्त केन्दु पत्ती को 2013 में बेचने हेतु रखा गया था, कई चक्रों में निविदा के बावजूद कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

उत्तर कम्पनी द्वारा अनुबंध के धारा 11 को अनदेखा करते हुए जब्त केन्दु पत्ती के निष्पादन हेतु समय पर कदम उठाने में असफल रहने की पुष्टि होती है।

3.1.5 अनुबंध की धारा 7(VI) के अनुसार, अनुबंध संपादन के 10 दिनों के अंदर क्रेता को बेचे गए पत्तियों की अधिसूचित मात्रा का अग्नि एवं चोरी बीमा कम्पनी के पक्ष में कराना है और केन्दु पत्ती का परिदान लेने से पहले संबंधित प्रमंडलीय प्रबंधक को बीमा पॉलिसी की मूल या सत्यापित प्रति

[11] प्रसन कुमार सिन्हा

उपलब्ध कराना है। बीमित राशि किसी भी समय देय राशि से कम नहीं होगा और केन्दु पत्ती के अतिरिक्त संग्रहण के स्थिति में क्रेता को उसका बीमा भी अतिरिक्त संग्रहण के 10 दिनों के अंदर कराना है। इसके अलावा, अनुबंध के शर्तों एवं बंधेजों के धारा 32(बी)(iv) के अनुसार, संग्रहण केन्द्र पर परिदान लिए गए केन्दु पत्ती तथा गोदाम में केन्दु पत्ती के स्टॉक की सुरक्षा की जिम्मेदारी कम्पनी के पर्यवेक्षण में क्रेता की थी। इस संबंध में, निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:

3.1.5.1 कम्पनी ने 2011 मौसम के लिए राँची प्रमंडल के सिमडेगा पूर्व-सी लॉट को ₹ 61.11 लाख के शुद्ध एकमुश्त मूल्य पर बेचा और क्रेता[12] के साथ अनुबंध किया (फरवरी 2011)। अनुबंध की वैधता मार्च 2012 तक था और पत्तियों के सारे स्टॉक को वैधता अवधि के अन्दर उठाना था।

क्रेता ने मई-जून 2011 में संग्रह किए गए 2,649.750 मानक बोरों का भंडारण अपने कंसडेगा गोदाम में किया जो सिर्फ अग्नि जोखिम के लिए ही बीमित था। क्रेता ने जनवरी 2012 तक मात्र 662.437 मानक बोरा ही उठाया और शेष मात्रा अनुबंध की समाप्ति के बाद भी गोदाम में पड़ा रहा। केन्दु पत्ती के नश्वर प्रकृति के जानकारी के बावजूद, अनुबंध की धारा 11 की अनदेखी करते हुए कम्पनी ने न तो अनुबंध को रद्द किया न ही केन्दु पत्ती स्टॉक को जब्त किया। यद्यपि, क्रेता ने 10 अक्टूबर 2012 तक अवधि विस्तार का आवेदन दिया, पर कोई विस्तार मंजुर नहीं किया गया। अनुबंध समाप्त किया गया तथा ₹ 15.28 लाख की प्रतिभूति राशि जब्त की गयी (दिसम्बर 2012)। कम्पनी द्वारा अनुबंध की समाप्ति के उपरांत भौतिक सत्यापन कराया गया (फरवरी 2013), जिसमें 1,567.460 मानक बोरा कम पाया गया जिनका मूल्य कर एवं अन्य शुल्कों सहित ₹ 31.94 लाख[13] था जिसके संबंध में न तो कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया न ही अभी तक हानि की कोई वसूली की गई है (जूलाई 2013)। इस प्रकार, चोरी के विरुद्ध बीमा न होने के कारण कम्पनी को ₹ 31.94 लाख की हानि हुई। इसके अलावा, कम्पनी का निलामी द्वारा ₹ 8.55 लाख[14] के जब्त केन्दु पत्ती के बिक्री का प्रयास, केन्दु पत्ती के नश्वर प्रकृति के कारण साकार नहीं हो पाया (मई 2013)। केन्दु पत्ती स्टॉक के जब्ती एवं जब्त स्टॉक की पुनर्बिक्री हेतु

---

[12] प्रसन कुमार सिन्हा

[13] ₹ 40.49 लाख/1,987.313 मानक बोरे*1,567.460 मानक बोरे

[14] ₹ 40.49 लाख/1,987.313 मानक बोरे *419.853 सिमडेगा पूर्व के मानक बोरे = ₹ 8.55लाख

ससमय कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप संभावित राजस्व से बंचित होना पड़ा।

तथ्यों को स्वीकारते हुए प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2013) कि गोदाम मालिक, क्रेता एवं वनोपज ओवरसियर (एफ.पी.ओ.) के विरुद्ध प्राथमिकी (एफ.आइ.आर.) दर्ज करा दी गयी है। एफ.पी.ओ. को निलंबित कर दिया गया है साथ ही उसके और वनोपज निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। क्रेता के विरुद्ध नीलामवाद भी दायर किया गया है तथापि, तथ्य यथावत् है कि राशि की वसूली किया जाना अभी तक बाकी है।

3.1.5.2 इसी प्रकार के मामले में, कम्पनी ने 2012 मौसम में सिमडेगा पूर्व-सी लॉट और सिमडेगा पूर्व-डी लॉट के केन्दु पत्ती को ₹ 72.11 लाख एवं ₹ 91.21 लाख के शुद्ध एकमुश्त मूल्य पर बेचा। क्रेता ने; सिमडेगा पूर्व-सी लॉट के 3,310.050 मानक बोरा एवं सिमडेगा-डी लॉट के 3,770.790 मानक बोरा को गोदाम में भंडारित किया। क्रेता ने इन लॉटों के लिए ₹ 40.83 लाख[15] की प्रतिभूति राशि जमा की।

क्रेता ने लॉटों का कोई भी किस्त देय तिथि पर जमा नहीं किया। इसके बावजूद, कम्पनी अनुबंध के धारा 11 के प्रावधानों के तहत केन्दु पत्ती को जब्त नहीं किया। गोदाम में आग लग गई (28 अक्टूबर 2012) और केन्दु पत्ती का पूरा स्टॉक जिसका मूल्य ₹ 163.32 लाख[16] था जल गया। कम्पनी केन्दु पत्ती स्टॉक के सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा। तथापि, कम्पनी ने इन लॉटों के विरुद्ध बीमा कम्पनी से बीमित राशि की वसूली हेतु दावा किया (नवम्बर 2012) और प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया। बीमादाता द्वारा दावे का निपटारा किया जाना अभी तक बाकी है (नवम्बर 2013)। कम्पनी की अनुबंध के धारा 11 का अनुपालन न कर पाने और केन्दु पत्ती स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने के कारण ₹ 122.49 लाख[17] की हानि वहन करनी पड़ सकती है।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2013) कि बीमा कम्पनी के सर्वेक्षक द्वारा मांगी गई सभी जरुरी सूचना उपलब्ध करा दी गई थी। तथापि, दावे से एक वर्ष बीत जाने के बाद भी हानि की वसूली नहीं हो सकी है। प्रबंधन ने पुन: कहा कि एफ.पी.ओ. को निलंबित कर दिया गया है साथ ही उसके और एफ.पी.आई. के

---

[15] सिमडेगा पूर्व-सी - ₹ 18.03 लाख जोड़ सिमडेगा पूर्व-डी- ₹ 22.80 लाख

[16] सिमडेगा पूर्व-सी - ₹ 72.11 लाख जोड़ सिमडेगा पूर्व-डी-₹ 91.21 लाख

[17] केन्दु पत्ती का मूल्य - ₹ 163.32 लाख घटाव प्रतिभूति राशि-₹ 40.83 लाख = ₹ 122.49 लाख

विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। क्रेता को काली सूची में डालने के साथ उसके विरुद्ध नीलामवाद भी दायर किया गया है।

तथ्य यथावत् है कि अभी तक राशि की वसूली किया जाना है (नवम्बर 2013)।

3.1.5.3 यह भी पाया गया कि सिमडेगा पूर्व-डी में संग्रहित 3,770.790 मानक बोरा केन्दु पत्ती संग्रहण के विरुद्ध केन्दु पत्ती संग्रहकों को ₹ 7.05[18] लाख, मात्र 1,007.12 मानक बोरा का ही मजदूरी भुगतान केन्दु पत्ती के परिदान लेने के समय किया गया। कम्पनी ने अनुबन्ध के धारा 6 के प्रावधान, जिसके अनुसार संग्रहकों को समय पर भुगतान के लिए परिदान लेने के पूर्व क्रेता से पूर्ण संग्रहण लागत लेना था, अनुपालन न करते हुए क्रेता से 2,763.670 मानक बोरों के संग्रहण लागत वसूल नहीं किया, जिसके कारण मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सका। केन्दु पत्ती सुपुर्दगी के सात महीने बीत जाने के बाद यह तथ्य कम्पनी के संज्ञान[19] में आया हालांकि एफ.पी.ओ. एवं एफ.पी.आई. संग्रहकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे। प्रबंधन के निष्क्रियता के कारण कम्पनी को ₹ 19.35 लाख[20] के मजदूरी का भुगतान करना पड़ा है और इस हद तक हानि वहन करनी पड़ी।

केन्दु पत्ती के स्टॉक के बीमा में अपर्याप्तता

3.1.6 मौसम 2008-12 के दौरान लघु वनोत्पाद प्रमंडल राँची, हजारीबाग, गिरिडीह तथा डाल्टनगंज के क्रेताओं से संबंधित अभिलेखों तथा बीमा पॉलिसियों के नमूना जाँच में हमने निम्न अपर्याप्ताएँ पाई;

- नमूना जाँच किये गये चार प्रमंडलों में, 910 बिक्रीत लॉटों में से मात्र 880 लॉट ही बीमित थे। इसके अतिरिक्त, इन 880 बीमित लॉटों में से 76 लॉट संबंधित लॉटों के शुद्ध एकमुश्त राशि से कम राशि से बीमित थे। चार मामलों में, बीमा पॉलिसी की मूल प्रति या प्रमाणित प्रति जमा नहीं की गयी थी।
- चोरी के जोखिम के विरुद्ध, राँची तथा डाल्टनगंज प्रमंडलीय कार्यालयों में बीमा नहीं कराया गया था, जैसा कि अनुबंध के शर्तों तथा बंधेजों के तहत अपेक्षित था जबकि गिरिडीह तथा हजारीबाग के 208 तथा

---

[18] 1,007.12 मानक बोरे x ₹ 700 प्रति मानक बोरे = ₹ 7.05 लाख

[19] संसद के स्थानीय सदस्य द्वारा

[20] 2,763.670 मानक बोरे x ₹ 700 प्रति मानक बोरे = ₹ 19.35 लाख

268 बीमित लॉटों में से क्रमश: 203 तथा नौ लॉटें ही चोरी के जोखिम के विरुद्ध बीमित थे।

- हजारीबाग प्रमंण्डल के पाँच मामलों में केन्दु पत्ती को बीमा अवधि के समाप्त होने के 12 दिन से 10 माह के बाद उठाया गया। गिरिडीह, हजारीबाग, डाल्टेनगंज एवं राँची प्रमण्डलों के क्रमश: 43, 33, 15 और 12 लॉटों की बीमा पॉलिसियों की वैधता अनुबंध अवधि से जो संग्रहण वर्ष के बाद के वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होती है, पहले ही समाप्त हो गई।
- मौसम 2009 में प्रतापपुर-ई लॉट के स्टॉक का बीमा केन्दु पत्ती स्टॉक के स्थान पर, खतरनाक पदार्थ से संबंधित दुकान, हथियार और गोला बारूद के सौदागर, मोटर वाहन शोरूम सेवा एवं विक्रय सहित, पेट्रोल एवं डीजल कियोस्क का बीमा कराया गया। बीमित वस्तु का गलत वर्गीकरण किसी दुर्घटना के कारण हुए नुकसान के दावे से वंचित कर सकता है।

इस प्रकार, केन्दु पत्ती के पर्याप्त और उचित बीमा सुनिश्चित करने मे विफलता कम्पनी द्वारा अनुश्रवण में कमी को दर्शाता है। अपर्याप्त या अनुचित बीमा के परिणामस्वरुप राजस्व की हानि तथा धन के बाधित रहने के अलावे अवांछित कानूनी कार्यवाहियों/प्रक्रियाओं में समय तथा संशाधनों की बर्बादी हो सकती है।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2013) कि भविष्य में केन्दु पत्ती के स्टॉक को आग और चोरी के जोखिम के विरुद्ध बीमित करने के संबंध में कदम उठाए जाऐंगे। अपर्याप्तता को नोट कर लिया गया है और भविष्य में दोहराया नहीं जाएगा।

सांविधिक निगम

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

3.2 अनुपयुक्त नियोजन की वजह से ₹ 85.23 लाख की निधि का अवरोधन

आवश्यकता का उचित निर्धारण के बिना ए.सी.एस.आर. पैंथर कंडक्टर के क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 85.23 लाख की निधि अवरोधित रही जिससे ₹ 53.55 लाख ब्याज की हानि हुई।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.) अपने विद्युत वितरण प्रणाली के उन्नयन और विस्तार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक विकास कार्यक्रम (ए.डी.पी.) तैयार करता है। ए.डी.पी. के तहत निर्माण कार्य के लिए सामग्री की मात्रा क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर तैयार की जाती है और उस मात्रा की सामग्री की खरीदारी के लिए उस वर्ष के सामग्री बजट में शामिल किया जाता है। ए.डी.पी. के तहत प्रस्तावित व्यय अधिकांशत: झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों से होता है।

महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर द्वारा प्रस्तावित तीन 33 के.वी. स्विचिंग उप-केन्द्रों का निर्माण, 44 कि.मी. 33 के.वी. लाइन स्ट्रे विस्तार तथा 14 कि.मी. 33 के.वी. लाइन के पुनर्वास के लिए, 1.8 कि.मी. ए.सी.एस.आर. पैंथर कंडक्टर[21] और 313.60 कि.मी. डॉग कंडक्टर[22] की आवश्यकता का प्रस्ताव झा.रा.वि.बो. मुख्यालय को भेजा गया (जून 2006)। इस संदर्भ में बोर्ड मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर के लिए तीन स्विचिंग उप-केन्द्र, 8 कि.मी. 33 के.वी. लाईन स्ट्रे विस्तार तथा 10 कि.मी. 33 के.वी. लाईन के पुनर्वास को अनुमोदित किया गया। ए.डी.पी. के तहत वर्ष 2006-07 के सामग्री बजट में 150 कि.मी. पैंथर कंडक्टर की क्रय का प्रावधान किया गया जबकि क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर द्वारा केवल 1.8 कि.मी. पैंथर कंडक्टर की आवश्यकता दर्शायी गई थी।

झा.रा.वि.बो. द्वारा प्रस्तावित 151.65 कि.मी.[23] पैंथर कंडक्टर के क्रय के लिए अध्यक्ष, झा.रा.वि.बो. द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई (अक्टूबर 2006)। तदनुसार, सामग्री के आपूर्ति के लिए दिसम्बर 2006 में निविदा आमंत्रित की गई। उचित निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करते हुए एनभील केवल्स प्रा. लि. को 147 कि.मी. आई.एस.आई. मार्क पैंथर कंडक्टर आपूर्ति के लिए प्रति कि.मी. ₹ 1,20,044.27 के परिवर्तनशील दर पर क्रय आदेश दिया गया (अप्रैल 2008)। आशय पत्र (एल.ओ.आई.) निर्गत (27 मार्च 2008) करने के 45 दिन के अंदर अर्थात मई 2008 तक सामग्री की आपूर्ति

[21] एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित (ए.सी.एस.आर) पैंथर केबल विद्युत उप-केन्द्रों और 33 के.वी. लाईनों में उपयोग हेतु उच्च विदुयुत प्रवाह वहन क्षमता युक्त कंडक्टर है।

[22] ए.सी.एस.आर डॉग कंडक्टर 33 के.वी. लाईन/11 के.वी. लाईन और एल.टी. लाइनों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है।

[23] ए.डी.पी. के लिए 150 कि.मी. और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 1.65 कि.मी.।

की जानी थी। 147 कि.मी. पैंथर कंडक्टर के क्रय आदेश के आलोक में केवल 85.30 कि.मी. पैंथर कंडक्टर का आपूर्ति प्राप्त किया गया।

हमने पाया (मार्च 2013) कि पैंथर कंडक्टर का क्रय अनुमोदित सामग्री बजट 2007-08 के तहत की गई जिसमें 200 कि.मी. पैंथर कंडक्टर के क्रय का प्रावधान बिना क्षेत्रीय कार्यालयों से नवीन आवश्यकता का आकलन प्राप्त किये तदर्थ आधार पर किया गया था।

पैंथर कंडक्टर की 1.80 कि.मी. के माँग के आलोक में केन्द्रीय भंडार, जमशेदपुर को 22.70 कि.मी. कंडक्टर दिया गया जिसमें से केवल 3.28 कि.मी. पैंथर कंडक्टर का उपयोग किया गया (जुलाई 2013)। शेष[24] पैंथर कंडक्टर को अन्य विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के केन्द्रीय भंडार में बिना उनके माँग पत्र के भेज दिया गया। ए.सी.एस.आर. पैंथर कंडक्टर के 85.30 कि.मी. क्रय मात्रा की तुलना में केवल 20.213 कि.मी. (23.70 प्रतिशत) का उपयोग किया गया तथा शेष 65.087 कि.मी., जिसका मूल्य ₹ 85.23 लाख[25] था, बिना उपयोग के भंडार गृह में पड़ा रहा (जुलाई 2013)।

झा.रा.वि.बो. ने कहा (अगस्त 2013) कि पैंथर कंडक्टर का उपयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर और अन्य क्षेत्रों में न होने के कारण प्रस्तावित स्विचिंग केन्द्र एवं पी.एस.एस. का निर्माण भूमि विवाद और अन्य कारणों से वर्ष 2008-2013 तक समापन नहीं होना था। झा.रा.वि.बो. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2006-07 में पैंथर कंडक्टर की निर्धारित माँग जो केवल 1.8 कि.मी. थी, पैंथर कंडक्टर की कुल क्रय से बहुत कम थी। इसके अलावा, झा.रा.वि.बो. ने वर्ष 2013-14 में ए.डी.पी. के तहत 46 पी.एस.एस. के निर्माण के लिए योजना बनाई है जिसमे केवल 27.60[26] कि.मी. पैंथर कडंक्टर की आवश्यकता होगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2008 से 2012 के दौरान भूमि की उपलब्धता की कमी और अन्य समस्याओं के कारण केवल चार पी.एस.एस. का निर्माण हुआ था, पी.एस.एस. के निर्माण के लिए व्यापक अवधि की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, 65.087 कि.मी. पैंथर कंडक्टर के शेष मात्रा का तत्काल उपयोग की कोई संभावना नहीं रही।

---

[24] 62.60 कि.मी. (85.30 कि.मी. - 22.70 कि.मी.)

[25] ₹ 69.78 लाख (53.304 कि.मी.x ₹ 1,30,900 लागत प्रति कि.मी. मूल्य विचलन सहित) + ₹ 15.45 लाख (11.783 कि.मी.x ₹ 1,31,153 लागत प्रति कि.मी. मूल्य विचलन सहित)

[26] प्रत्येक प्रस्तावित पी.एस.एस. में 600 मीटर की आवश्यकता को देखते हुए

अत: झा.रा.वि.बो. द्वारा 65.087 कि.मी. पैंथर कंडक्टर की आवश्यकता से अधिक क्रय पाँच साल तक अनुपयोगी रही जिसके परिणामस्वरूप ₹ 85.23 लाख की निधि अवरोधित हुई। बोर्ड गंभीर वित्तीय बाधाओं से जूझ रहा था और कोष की व्यवस्था मुख्य रूप से झारखण्ड सरकार से प्राप्त ऋण से होती थी। ऐसी स्थिति में बोर्ड को ₹ 53.55[27] लाख का अतिरिक्त परिहार्य ब्याज का बोझ उठाना पड़ा।

मामला सरकार को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर, 2013)।

3.3 जेनरेटर स्टेटर की मरम्मत पर निरर्थक व्यय

पतरातू थर्मल पॉवर स्टेशन की बंद पड़ी इकाई संख्या-3 के जेनरेटर (स्टेटर और रोटर) की मरम्मत पर ₹ 71 लाख की राशि का निरर्थक व्यय किया जो इस इकाई के प्रस्तावित पुनर्वास के लिए कोष की उपलब्धता को सुनिश्चत किए बिना किया गया था, जिसके फलस्वरूप जेनरेटर स्टेटर का उपयोग नहीं हो सका।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्त एवं लेखा संहिता, जो झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अपनाई गई है, के अनुसार पूँजीगत योजना जिसमें 15 लाख से अधिक का व्यय शामिल होता है उसे राज्य सरकार के पूर्व परामर्श के साथ तैयार किया जाता है। झा.रा.वि.बो प्रत्येक वर्ष उत्पादन से संबंधित योजनाओं के लिए कार्य योजना तैयार करती है जिसके लिए निधि का आयोजन मुख्य रूप से झारखण्ड सरकार द्वारा किया जाता हैं। झा.रा.वि.बो अपनी शीर्ष परिषद् से योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद प्रस्ताव का अनुमोदन और कोष का प्रावधान हेतु झारखण्ड सरकार को भेजती है।

पतरातू थर्मल पॉवर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) का 50 मेगावाट का रूस निर्मित ऊर्जा उत्पादन इकाई संख्या-3, अगस्त 2003 से बंद पड़ी थी। झा.रा.वि.बो ने वर्ष 2007-08 के लिए ₹ 100 करोड़ का उत्पादन कार्य योजना बनाई जिसमें पी.टी.पी.एस. के इकाई संख्या 3 के पुनर्वास के लिए ₹ 25.29 करोड़ शामिल थे। झारखण्ड सरकार ने वर्ष 2007-08 के बजट परिव्यय में उक्त कार्य योजना के लिए ₹ 100 करोड़ का प्रावधान किया। झा.रा.वि.बो की शीर्ष परिषद् ने इस प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकृति (अप्रैल 2007) प्रदान की जो झारखण्ड

[27] ₹ 85.23 लाख x13 प्रतिशत x58 महीने/12 = ₹ 53.55

सरकार के अंतिम अनुमोदन पर निर्भर था। झा.रा.वि.बो ने झारखण्ड सरकार के अनुमोदन की प्रत्याशा में ₹ 25.29 करोड़ की अनुमानित लागत पर कार्यादेश देने के लिए निविदा आमंत्रित किया (फरवरी 2008)।

झारखण्ड सरकार ने (मार्च 2009) झा.रा.वि.बो के ₹ 100 करोड़ के उत्पादन कार्य योजना को स्वीकृत किया लेकिन कोष का उपयोग सिर्फ पी.टी.पी.एस. के इकाई संख्या 9 और 10 में चल रहे पुनर्वास के लिए करने का निर्देश दिया और इकाई संख्या 3 के लिए इस राशि का उपयोग प्रतिबंधित किया। कोष की अनुपलब्धता की स्थिति में झा.रा.वि.बो ने इकाई के पुनर्वास के लिए व्यापक निविदा (फरवरी 2010) रद्द कर दी। तत्पश्चात् झारखण्ड सरकार ने इकाई संख्या-3 के पुनर्वास को स्थगित कर दिया (फरवरी 2011)।

हमने पाया कि इसी बीच झा.रा.वि.बो. के संयंत्र प्रबंधन ने इकाई संख्या-3 के जेनरेटर (स्टेटर और रोटर) की अलग से मरम्मत का प्रस्ताव रखा (मई 2007) यद्यपि इसका लागत (₹ 2.53 करोड़) इकाई संख्या-3 के पुनर्वास के लिये अनुमानित लागत (₹ 25.29 करोड़) में शामिल था (मार्च 2007)। झा.रा.वि.बो. की शीर्ष परिषद् द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया (दिसम्बर 2007) और ₹ 3.54 करोड़ के तकनीकि प्राक्कलन को स्वीकृति दी गई (मई 2008)।

झा.रा.वि.बो. ने इकाई संख्या-3 के जेनरेटर के स्टेटर और रोटर की मरम्मत के लिये ₹ 2.12 करोड़ (करों एवं शुल्कों को छोड़कर) का कार्यादेश ए.बी.बी. लिमिटेड को टर्न-की आधार पर दिया (जनवरी 2009)। जेनरेटर के रोटर की मरम्मत का पूरा कार्य और स्टेटर का पुन:रोधन का कार्य और स्टेटर के रिवाइंडिंग के लिये सामग्री की आपूर्ति ए.बी.बी. द्वारा अक्टूबर 2009 में पूरा कर लिया गया था।

हालाँकि, इकाई संख्या-3 के स्टेटर का रिवाइंडिंग, स्टेटर और रोटर का संयोजन और संबंधित कार्य को क्रियान्वित किया जाना अभी तक बाकी था। इकाई में जेनरेटर के उपयोग की संभावना नहीं थी इसलिए जेनरेटर स्टेटर की मरम्मत का शेष कार्य नहीं किया गया। मरम्मत के पश्चात् रोटर का उपयोग अक्टूबर 2010 में पी.टी.पी.एस. के रूस निर्मित 50 मेगावाट इकाई संख्या-4 के जेनरेटर में हुआ जो दिसम्बर 2009 से रोटर की विफलता के कारण बंद पड़ी थी।

झा.रा.वि.बो. ने कार्य के पूर्ण समापन से पहले ही रोक दिया (मई 2013) और वास्तविक कार्य के लिए ₹ 1.65 करोड़ (करों और शुल्कों को छोड़कर) का

संशोधित कार्यादेश कम मूल्य पर निर्गत किया। स्टेटर पर किये गए वास्तविक कार्य जिसका मूल्य ₹ 71 लाख था, अबतक अनुपयोगी रहा (मई 2013)। यह उपकरण केवल इकाई संख्या-4 के स्टेटर के ब्रेकडॉउन की स्थिति में उपयोग किया जा सकता है। इस उपकरण का पी.टी.पी.एस. की अन्य इकाईयों में उपयोग की संभावना क्षीण थी क्योंकि झा.रा.वि.बो. ने रूस निर्मित 50 मेगावाट इकाई संख्या 1, 2 और 3 को तत्काल हटाने का प्रस्ताव दिया था (फरवरी 2011)।

झा.रा.वि.बो. ने कहा (अगस्त 2013) कि इकाई संख्या-3 के जेनरेटर (स्टेटर और रोटर) की मरम्मत के लिए अलग कार्यादेश, इकाई के शीघ्र पुनर्वास के लिए ए.बी.बी. लिमिटेड को दिया गया और कहा कि जेनरेटर स्टेटर का एक अतिरिक्त सेट रखना बेहतर था। इकाई संख्या-4 जो रोटर की विफलता के कारण बंद था उसमें जेनरेटर का मरम्मत किया हुआ रोटर उपयोग कर परिचालन योग्य बनाया गया।

झा.रा.वि.बो. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि झारखण्ड सरकार से प्राप्य कोष की अनिश्चितता के कारण इकाई के व्यापक पुनर्वास का कार्य नहीं सौंपा गया इसलिए इकाई संख्या-3 का यथासमय पुनर्वास संभव नहीं था। इसके अलावा, स्टेटर का एक अतिरिक्त सेट रखने का उत्तर बाद में सोचा गया है क्योंकि कार्यादेश के नियोजन के समय ऐसे कोई विकल्प पर झा.रा.वि.बो. द्वारा विचार नहीं किया गया था।

अत: जेनरेटर (स्टेटर और रोटर) के मरम्मत के लिए कार्यादेश देना, जो इकाई संख्या-3 के पुन:उद्धार योजना जो कोष की अनुपलब्धता के कारण शुरू नहीं किया जा सका, में सम्मिलित था, उचित नहीं था क्योंकि मरम्मत किया हुआ स्टेटर अक्तूबर 2009 से अनुपयोगी बना रहा जिसकी वजह से ₹ 71 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

मामला सरकार को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर, 2013)।

3.4 दण्ड की गैर-उगाही के कारण हानि

₹ 45.72 लाख के कम विपत्रीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 5.29 लाख के ब्याज की हानि हुई जो उपभोक्ताओं से अनुबंधित मांग की 110 प्रतिशत से अधिक के लिए दण्ड की गैर-वसूली/वसूली में देरी के कारण हुई।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.), ईस्टर्न कोल्फील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.) को, जो एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी है, उच्च विभव पर विद्युत आपूर्ति करता था और रेलवे ट्रेक्शन सर्विसेज (आर.टी.एस.) के माध्यम से रेलवे को विद्युत आपूर्ति किया जा रहा था। हमने पाया कि (जनवरी/मई 2013) देवघर विद्युत आपूर्ति अंचल के अधीन ललमटिया में ई.सी.एल. के एक एच.टी.एस. कनेक्शन में अगस्त 2011 से नवम्बर 2011 तक अधिकतम मांग, अनुबंधित माँग के 110 प्रतिशत से अधिक दर्ज हुआ। इसी तरह, संचरण अंचल, राँची के अधीन रेलवे के तीन आर.टी.एस. कनेक्शन (टोलरा, लोधमा और बकसपुर) की अधिकतम मांग अगस्त 2012 से मार्च 2013 तक उसके अनुबंधित मांग के 110 प्रतिशत से अधिक दर्ज हुई। तथापि, झा.रा.वि.बो. ने टैरिफ आदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वास्तविक दर्ज मांग जो अनुबंधित मांग के 110 प्रतिशत से अधिक थी, के लिए दंडात्मक शुल्क लगाए बिना सामान्य दरों पर विपत्र जारी किए। इस प्रकार, दंड शुल्कों के कम विपत्रीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं से कुल ₹ 45.72 लाख की राशि कम प्राप्त हुई।

> झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा निर्गत अन्तरिम टैरिफ आदेश जो 1 अगस्त 2011 से प्रभावी था, के अनुसार उच्च विभव वोल्टेज आपूर्ति सेवा (एच.टी.एस.) उपभोक्ता की दर्ज माँग यदि अनुबंध माँग से 110 प्रतिशत से अधिक हो तो अनुबंध माँग के 110 प्रतिशत तक दर्ज माँग के शुल्क का निर्धारण समान्य शुल्क दरों पर किया जायेगा। अनुबन्ध माँग के 110 प्रतिशत से अधिक दर्ज माँग के शुल्क का निर्धारण समान्य शुल्क दरों के 1.5 गुना पर किया जायेगा।

लेखापरीक्षा की आपत्ति के बाद, झा.रा.वि.बो. ने उपरोक्त उपभोक्ताओं पर दण्ड के रूप में ₹ 45.72 लाख की राशि के अनुपूरक विपत्र जारी किए जिसमें तीन आर.टी.एस. उपभोक्ताओं से ₹ 35.06 लाख की वसूली हुई (जूलाई/अगस्त 2013)। हालांकि, ई.सी.एल. से प्राप्त की जाने वाली ₹ 10.66 लाख की दण्ड राशि की वसूली अब तक नहीं हो सकी (अक्टूबर 2013)।

झा.रा.वि.बो. ने इस तथ्य को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और कहा कि स्मार-पत्र (जूलाई 2013) के बाद भी ई.सी.एल. के द्वारा ₹ 10.66 लाख के दण्ड शुल्क का भुगतान नहीं किया गया।

इस प्रकार, झा.रा.वि.बो. द्वारा टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार दण्ड की वसूली में विफलता के कारण ₹ 10.66 लाख अप्राप्त रहे। फलस्वरुप, दण्ड

शुल्कों की गैर-वसूली/वसूली में देरी के कारण ₹ 5.29[28] लाख राशि के ब्याज का नुकसान उठाना पड़ा।

मामला सरकार को जून 2013 में प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्रतिक्षित थे (दिसम्बर 2013)।

3.5 लाभार्थी राज्यों से प्रस्तावित ऊर्जा परियोजना के खर्च के अंशों का अवसूलीकरण

प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना के लाभार्थी राज्यों से ₹ 1.57 करोड़ के खर्चों के अंशों का वसूली न होने के परिणामस्वरूप झा.रा.वि.बो. पर ₹ 1.16 करोड़ के ब्याज का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया (अक्टूबर 2007) कि झारखण्ड में मौर्या कोल ब्लॉक को एक विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था[29] (एस.पी.वी.) को आवंटित करना था जो संयुक्त रूप से झारखंड, बिहार और उत्तरप्रदेश द्वारा बनाया जाना था जिसमें झारखण्ड में स्थापित की जाने वाली ताप विद्युत परियोजना से उत्पादित ऊर्जा के आहरण का अंश क्रमश: 60 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत होना था। बिजली के क्रय के लिए एस.पी.वी. द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली राज्य के वितरण उपयोगिताओं की तरफ से विकासकर्ता के चयन हेतू मंगाई जाएगी। एस.पी.वी. का अधिग्रहण एक चयनित विकासकर्ता द्वारा एस.पी.वी. के सभी लागत का भुगतान करके किया जाएगा।

झा.रा.वि.बो. द्वारा (फरवरी 2008) पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी.एफ.सी.) को सलाहकार के रूप में एस.पी.वी. के सृजन के लिए और एस.पी.वी. को जल आवंटन, ईंधन संयोजन में सहायता और सांविधिक मंजूरियाँ जैसे पर्यावरण, वन विभाग की मंजूरी आदि एवं परियोजना के विकासकर्ता के चयन में सहायता और सलाह देना था। परामर्श शुल्क के रूप में ₹ 14 करोड़ (कर अतिरिक्त) देय था। झा.रा.वि.बो. ने कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार अग्रिम के रूप में पी.एफ.सी. को ₹ 3.93 करोड़[30] की राशि का भुगतान किया (फरवरी 2008)।

झा.रा.वि.बो. ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कम्पनी के रूप में एस.पी.वी., कर्णपूरा एनर्जी लिमिटेड (के.ई.एल.) का गठन किया (19 सितम्बर 2008) जो झा.रा.वि.बो. के पूर्ण स्वामित्व की थी एवं जिसके निदेशक मंडल

---

[28] 13 प्रतिशत की ब्याज की दर पर जिस पर झा.रा.वि.बो. झारखण्ड सरकार से ऋण लेती है

[29] एक कानूनी पहचान जो एक समझौते के माध्यम से देश के प्रासंगिक कानून के तहत स्थापित हुआ

[30] ₹ 350 लाख (₹ 1400 लाख का 25 प्रतिशत) + ₹ 43.26 लाख (12.36 प्रतिशत सेवा कर)

में बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि थे। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने के.ई.एल. को हरित क्षेत्र ऊर्जा परियोजना (2x660 मेगावाट) के लिए मौर्या कोल ब्लॉक को आवंटित किया (जून 2009)। उपरोक्त कोल ब्लॉक से उत्पादित कोयले का केवल ऊर्जा परियोजना में उपयोग किया जाना था।

प्रस्तावित ऊर्जा परियोजना, राज्य में उपलब्ध संसाधनों के साथ स्थापित किया जाना था जिससे उत्पादित ऊर्जा को बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साझा किया जाना था। परियोजना से संबंधित व्यय लाभुक राज्यों के बीच ऊर्जा में उनके अंशों के अनुपात में साझा किया जाना था। हालांकि, झा.रा.वि.बो. व्यय के बँटवारे के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ कोई व्यवस्था नहीं किया।

यद्यपि, झा.रा.वि.बो. ने परामर्शी सेवाओं पर खर्च को बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों को साझा किए जाने के लिए सूचित किया, लेकिन खर्च के भुगतान के लिए उन राज्यों के साथ अनुसरण नहीं कर पाई। परिणामस्वरूप, परामर्शी शुल्क के लिए ₹ 3.93 करोड़ के खर्च का अंश के रूप में प्राप्य, बिहार से ₹ 98.25 लाख[31] और उत्तर प्रदेश से ₹ 58.95 लाख[32] प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2013)।

हमने पाया कि झा.रा.वि.बो. द्वारा भुगतान किये गये परामर्श शुल्क ₹ 3.93 करोड़ को के.ई.एल. ने अपने खातों[33] में झा.रा.वि.बो. से प्राप्त ऋणों के रूप में दिखाया। हालांकि खाते में यह नहीं दिखाया गया था कि उक्त ऋण पर कोई ब्याज झा.रा.वि.बो. को देय था और इस प्रकार, चयनित विकासकर्ता द्वारा एस.पी.वी. के अधिग्रहण के पश्चात् झा.रा.वि.बो. को उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

झा.रा.वि.बो. ने कहा (नवम्बर 2013) लाभार्थी राज्यों से खर्च पर उनके अंशों की राशि भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि झा.रा.वि.बो. लाभार्थी राज्यों से ₹ 3.93 करोड़ के परामर्शी शुल्क का अनुपातिक अंश प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया था और लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति उठाने पर भुगतान प्राप्ति हेतु केवल एक ही अनुरोध अक्टूबर 2013 में किया गया था।

---

[31] ₹ 3.93 करोड़ क 25 प्रतिशत

[32] ₹ 3.93 करोड़ क 15 प्रतिशत

[33] 19 सितम्बर 2008 से 30 जून 2009 तक की अवधि के लिए और बाद में लेखांकित अवधियों के लिए

इस प्रकार, लाभार्थी राज्यों के साथ इस परियोजना के लिए खर्च के बंटवारे के लिए कोई भी व्यवस्था करने में और उसकी वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही करने में झा.रा.वि.बो. की विफलता के कारण ₹ 1.57 करोड़ की राशि अप्राप्त रही। परिणामस्वरूप, झा.रा.वि.बो. को ₹ 1.16 करोड़[34] की राशि का अतिरिक्त ब्याज का भार वहन करना पडा (अक्टूबर 2013)।

मामला सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2013)।

सामान्य

3.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

3.6.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में रखे गए खातों एवं अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण के साथ प्रारम्भ की गई लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कार्यकारी से प्रतिक्रिया तथा उपयुक्त समय में उत्तर प्राप्त करें।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल के पटल पर क्रमशः जुलाई 2009, अगस्त 2010, अगस्त 2011, सितम्बर 2012 एवं जुलाई 2013 में रखे गये थे। 2007-08 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल एवं वाणिज्यिक) और सा.क्षे.उ. का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित आठ विभागों के अंतर्गत दस सा.क्षे.उ. से संबंधित 31 कंडिका/समीक्षा में से 30 कंडिका/समीक्षा से संबंधित उत्तर सरकार से 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त नहीं हुए हैं जैसा की ***तालिका - 3.2*** इंगित किया गया है:

तालिका - 3.2

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल कंडिका/समीक्षा	संबंधित विभागों की संख्या	कंडिका/समीक्षा की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2007-08	9	3	8
2008-09	5	2	5
2009-10	7	2	7
2010-11	4	3	4
2011-12	6	8	6
कुल	**31**		**30**

विभागवार विश्लेषण ***परिशिष्ट-3.2*** में दिया गया है।

[34] ₹ 157.20 लाख x 13 प्रतिशत x 68 महीने (मार्च 2008 से अक्तूबर 2013)/12

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.6.2 वर्ष 2001-02 से 2010-11 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल एवं वाणिज्यिक) और 2011-12 के सा.क्षे.उ. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, 40 कंडिकाएं तथा नौ समीक्षायें सम्मिलित की गयी थी। इनमें से, 30 सितम्बर 2012 तक सात कंडिकाओं तथा तीन समीक्षाओं पर कोपू द्वारा चर्चा की गयी थी। वर्ष 2001-02 से 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के तीन कंडिकाओं एवं दो समीक्षाओं के संबंध में कोपू ने अनुशंसाएँ की थी।

कोपू की कार्यचालन प्रणाली नियमावली के अनुसार संबंधित विभागों को कोपू की अनुशंसाओं पर कार्रवाई टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.) तीन माह के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालाँकि विभागों द्वारा ए.टी.एन. हमें कोपू द्वारा ए.टी.एन. की चर्चा के समय ही उपलब्ध कराए जाते हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं और समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

3.6.3 लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए तथा तत्काल निस्तारित न हुए लेखापरीक्षा अवलोकनों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य सरकार के संबंधित विभागों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) के माध्यम से संसूचित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर चार सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है। दस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मार्च 2013 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से परिलक्षित होता है कि 386 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 1510 कंडिकाएं सितम्बर 2013 के अंत तक अनिस्तारित रहीं। 30 सितम्बर 2013 के अंत तक विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों का विवरण ***परिशिष्ट-3.3*** में दिया गया है।

इसी प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर प्रारूप कंडिका एवं समीक्षा संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव एवं प्रधान सचिव, वित्त को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा छः सप्ताह के अन्दर तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि एवं उन पर उनकी टिप्पणियों की अपेक्षा सहित प्रेषित की जाती है। जून से अगस्त 2013 के दौरान विभिन्न विभागों को अग्रसारित पाँच प्रारूप कंडिकाओं एवं एक समीक्षा प्रतिवेदन में से सरकार ने केवल समीक्षा के उत्तर दिया था (दिसंबर 2013); प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2013) जिसका विवरण ***परिशिष्ट-3.4*** में है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि (क) उन कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया अस्तित्व में रहे जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं तथा कोपू की अनुशंसाओं पर कार्यवाही टिप्पणियाँ निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रेषित करने में विफल रहे हैं, (ख) एक समयबद्ध कार्यसूची के अनुसार हानि/बकाया अग्रिम/अधिभुगतान को वसूल करने की कार्यवाही हो और (ग) लेखापरीक्षा अवलोकनों के उत्तर देने की प्रणाली को सुदृढ़ कर दिया गया है।

मृदुला सप्रू

राँची **(मृदुला सप्रू)**

दिनांक : **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**

झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

शशी कान्त शर्मा

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांक : **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1.1

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम के संबंध में 31 मार्च 2013 को प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋण तथा मानवशक्ति को दर्शाती अद्यतन विवरणी

(कंडिका 1.8 में संदर्भित)

(कॉलम 5(क) से 6(घ) के आँकड़े ₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समाहित करने का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[5]				2012-13 के अंत में बकाया ऋण				2012-13 के ऋण अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानवशक्ति (31.03.2013 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं संबद्ध													
1.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	27.3.2002	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	318
2.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड	जल संसाधन	22.3.2002	500.00	-	-	500.00	525.00	-	-	525.00	1.05:1	219
प्रक्षेत्रवार कुल				**505.00**	**-**	**-**	**505.00**	**525.00**	**-**	**-**	**525.00**	**1.04:1**	**537**
आधारभूत संरचना													
3.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	15.12.2004	900.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	15
4.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड	गृह	13.03.2002	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	42
5.	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	नगर विकास	23.01.2003	2500.00 (2450.00)	-	-	2500.00 (2450.00)	-	-	-	-	-	17
प्रक्षेत्रवार कुल				**3600.00 (2450.00)**	**-**	**-**	**3600.00 (2450.00)**		**-**	**-**	**-**	**-**	**74**
विनिर्माण													
6.	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	23.08.2006	1000.00	-	-	1000.00	-	-	725.00	725.00	0.73:1	267
7.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम	खान एवं भूतत्व	07.05.2002	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	365

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समाहित करने का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2012-13 के अंत में बकाया ऋण				2012-13 के ऋण अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानवशक्ति (31.03.2013 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
	लिमिटेड												
प्रक्षेत्रवार कुल				**1200.00**	**-**	**-**	**1200.00**	**-**		**725.00**	**725.00**	**0.60:1**	**632**
ऊर्जा													
8.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	26.11.1987	10500.00	-	-	10500.00	66589.87	-	-	66589.87	6.34:1	674
9.	कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड	ऊर्जा	19.09.2008	-	-	5.00	5.00	-	-	1195.75	1195.75	239.15:1	❖
प्रक्षेत्रवार कुल				**10500.00**	**-**	**5.00**	**10505.00**	**66589.87**	**-**	**1195.75**	**67785.62**	**6.45:1**	**674**
सेवायें													
10.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम	पर्यटन	22.3.2002	300.00 (50.00)	-	-	300.00 (50.00)	-		-	-	-	92
11.	झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड	उत्पाद एवं निषेध	26.11.2010	500.00 (300.00)	-	-	500.00 (300.00)	25.00	-	-	25.00	0.05:1	16
12.	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	लोक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	18.06.2010	500.00	-	-	500.00	4396.00	-	-	4396.00	8.79:1	268
13.	झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड	कल्याण	15.03.2012	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार कुल				**1300.00 (350.00)**	**-**	**-**	**1300.00 (350.00)**	**4421.00**	**-**	**-**	**4421.00**	**3.40:1**	**376**
कुल (क) (प्रक्षेत्रवार कुल सभी कार्यरत सरकारी कम्पनियां) (अंश आवेदन राशि)				**17105.00 (2800.00)**		**5.00**	**17110.00 (2800.00)**	**71535.87**	**-**	**1920.75**	**73456.62**	**4.29:1**	**2293**
(ख) कार्यरत सांविधिक निगम								**-**		**-**			
ऊर्जा													
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	ऊर्जा	20.3.2001	-	-	-	-	548281.00	-	21791.27	570072.27	-	5480
प्रक्षेत्रवार कुल				**-**	**-**	**-**	**-**	**548281.00**	**-**	**21791.27**	**570072.27**	**-**	**5480**
कुल (ख) (प्रक्षेत्रवार कुल सभी कार्यरत सांविधिक निगम)				**-**	**-**	**-**	**-**	**548281.00**	**-**	**21791.27**	**570072.27**	**-**	**5480**

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समाहित करने का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी$				2012-13 के अंत में बकाया ऋण				2012-13 के ऋण अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानवशक्ति (31.03.2013 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
सकल योग (क+ख) (अंश आवेदन राशि)				**17105.00 (2800.00)**	**-**	**5.00**	**17110.00 (2800.00)**	**619816.87**	**-**	**23712.02**	**643528.89**	**37.61:1**	**7773**
(ग) अकार्यरत सरकारी कम्पनियां		शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) अकार्यरत सांविधिक निगम		शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग+घ) (अंश आवेदन राशि)				**17105.00 (2800.00)**	**-**	**5.00**	**17110.00 (2800.00)**	**619816.87**	**-**	**23712.02**	**643528.89**	**37.61:1**	**7773**

(स्रोत: सरकारी कम्पनी/सांविधिक निगम द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

(कॉलम 5(क) एवं 5(घ) के कोष्ठक में आँकड़े अंश आवेदन राशि को दर्शाते हैं)

$ प्रदत्त पूँजी में अंश आवेदन राशि शामिल है।

❖ कंपनी के कार्य झा.रा.वि.बो. के अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाते हैं।

सरकार द्वारा ₹ 1.00 लाख अभिदत्त पूँजी अभी तक अप्राप्त है।

परिशिष्ट - 1.2

वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य अंश पूँजी, ऋण, अनुदान तथा सहाय्य, प्राप्त प्रत्याभूति, बकायों की माफी, अपलिखित ऋण तथा अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण तथा मार्च 2013 की समाप्ति पर प्रत्याभूति प्रतिबद्धता, को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 1.11 में संदर्भित)

(कॉलम 3(क) से 6(घ) के आँकड़े ₹ लाख में)

क्र.सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त सहाय्य एवं अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूति और वर्ष के अंत में प्रतिबद्धता		वर्ष के दौरान बकाये की माफी			
		अंश पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	अपलिखित की गई पुनः अदायगी ऋण	अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण	माफ किये गये ब्याज/दण्ड ब्याज	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
(क) कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
आधारभूत संरचना													
1.	जी.आर.डी.ए.	1400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार कुल		**1400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
विनिर्माण													
2.	झारक्राफ्ट	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार कुल		50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कृषि													
3.	झालकों	-	-	-	542.00	-	542.00	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार कुल		**-**	**-**	**-**	**542.00**	**-**	**542.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
सेवायें													
4.	जे.टी.डी.सी.	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	जे.एस.बी.सी.एल.	-	2000.00#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	जे.एस.एफ.एस.सी.एल	-	-	-	7500	-	7500	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार कुल		**50.00**	**2000.00**	**-**	**7500.00**	**-**	**7500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल (क) प्रक्षेत्रवार सभी कार्यरत सरकारी कम्पनियां		**1500.00**	**2000.00**	**-**	**8042.00**	**-**	**8042.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(ख) कार्यरत सांविधिक निगम													

ऊर्जा													
1.	झा.रा.वि.बो.	-	54170.00	-	110725.00	-	110725.00	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार कुल		**-**	**54170.00**	**-**	**110725.00**	**-**	**110725.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल (ख) प्रक्षेत्रवार सभी कार्यरत सांविधिक निगम		**-**	**54170.00**	**-**	**110725.00**	**-**	**110725.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल योग (क+ख)		**1500.00**	**56170.00**	**-**	**118767.00**	**-**	**118767.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(स्रोत: सरकारी कम्पनी/सांविधिक निगम द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

[#] कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹ 1975 लाख की अदायगी किया।

परिशिष्ट - 1.3

अद्यतन वर्ष के लिए तैयार लेखे के अनुसार सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(कंडिका 1.15 में संदर्भित)

(कॉलम 5(क) से (11) के आँकड़े ₹ लाख में)

क्र.सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे तैयार किये गये	निवल लाभ(+)/हानि(-)				आवर्त	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचयी लाभ (+)/ हानि (-)	निवेशित पूँजी@	निवेशित पूँजी से प्रतिफल$	निवेशित पूँजी से प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(क) कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं संबद्ध														
1.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	671.55	-	10.06	661.49	6369.74	-	5.00	1689.02	1694.02	661.49	39.05
2.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड	2009-10	2013-14	(-)133.39	-	0.73	(-)134.12	71.02	36.28	500.00	(-)1040.86	(-)15.86	(-)134.12	-
प्रक्षेत्रवार कुल				**538.16**	**-**	**10.79**	**527.37**	**6440.76**	**36.28**	**505.00**	**648.16**	**1678.16**	**527.37**	**31.43**
आधारभूत संरचना														
3.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2013-14	38.14	-	2.48	35.66	51.00	1.47	500.00	112.13	612.13	35.66	5.83
4.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	186.41	-	6.16	180.25	239.97	-	200.00	1572.11	1772.11	180.25	10.17
5.	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	2011-12	2013-14	320.14	-	1.54	318.61	-	-	1100.00 (1050.00)	736.73	1836.73	318.61	17.35
प्रक्षेत्रवार कुल				**544.69**	**-**	**10.18**	**534.52**	**290.97**	**1.47**	**1800.00 (1050.00)**	**2420.97**	**4220.97**	**534.52**	**12.66**
विनिर्माण														
6.	झारखण्ड सिल्क	2011-12	2013-14	200.50	95.83	71.27	33.40	1867.89	(-)15.17	950.00	63.16	1013.16	129.23	12.76

क्र.सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे तैयार किये गये	निवल लाभ(+)/हानि(-)				आवर्त	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचयी लाभ (+)/ हानि (-)	निवेशित पूँजी@	निवेशित पूँजी से प्रतिफल$	निवेशित पूँजी से प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड									(150.00)				
7.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2013-14	1409.10	-	15.00	1394.10	5190.59	-	200.00	9824.24	10024.24	1394.10	13.91
प्रक्षेत्रवार कुल				**1609.60**	**95.83**	**86.27**	**1427.5**	**7058.48**	**(-)15.17**	**1150.00 (150.00)**	**9887.40**	**11037.40**	**1523.33**	**13.80**
ऊर्जा														
8.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड[1]	1999-2000	2013-14	5183.65	9957.73	9276.61	(-)14050.69	19587.66	-	10000.00	(-)27772.19	154848.92	(-)4092.96	-
9.	कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड	$$	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
प्रक्षेत्रवार कुल				**5183.65**	**9957.73**	**9276.61**	**(-)14050.69**	**19587.66**	**-**	**10000.00**	**(-)27772.19**	**154848.92**	**(-)4092.96**	**-**
सेवायें														
10.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2004-05	2012-13	15.61	-	4.19	11.42	103.38	1.47	50.00	44.30	94.30	11.42	12.11
11.	झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	(-)6.98	-	-	(-) 6.98	-	-	500.00 (300.00)	(-)6.98	493.02	(-)6.98	-
12.	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	$$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड	$$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार कुल				**8.63**	**-**	**4.19**	**4.44**	**103.38**	**1.47**	**550.00 (300.00)**	**37.32**	**587.32**	**4.44**	**0.76**
कुल (क) क्षेत्रवार सभी कार्यरत				**7884.73**	**10053.56**	**9388.04**	**(-)11556.86**	**33481.25**	**24.05**	**14005.00**	**(-)14778.34**	**172372..77**	**(-)1503.30**	**-**

क्र.सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे तैयार किये गये	निवल लाभ(+)/हानि(-)				आवर्त	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचयी लाभ (+)/ हानि (-)	निवेशित पूँजी@	निवेशित पूँजी से प्रतिफल$	निवेशित पूँजी से प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
सरकारी कम्पनियां										(1500.00)				
(ख) कार्यरत सांविधिक निगम														
ऊर्जा														
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	2011-12	2013-14	(-)259417.34	49948.78	11736.75	(-)321102.87	222904.99	2743.00	-	(-)929014.77	81166.54	(-)271154.09	-
प्रक्षेत्रवार कुल				**(-)259417.34**	**49948.78**	**11736.75**	**(-)321102.87**	**222904.99**	**2743.00**	**-**	**(-)929014.77**	**81166.54**	**(-)271154.09**	**-**
कुल (ख) प्रक्षेत्रवार सभी कार्यरत सांविधिक निगम				**(-)259417.34**	**49948.78**	**11736.75**	**(-)321102.87**	**222904.99**	**2743.00**	**-**	**(-)929014.77**	**81166.54**	**(-)271154.09**	**-**
कुल योग (क+ख)				**(-)251532.61**	**60002.34**	**21124.79**	**(-)332659.76**	**256386.24**	**2767.05**	**14005.00 (1500.00)**	**(-)943793.11**	**253539.31**	**(-)27265739.39**	**-**

टिप्पणी: झारखण्ड राज्य में कोई अकार्यरत सरकारी कंपनी/सांविधिक निगम नहीं है।

लेखा टिप्पणी के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षक एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का निवल प्रभाव शामिल है, और लाभ में वृद्धि/हानि में कमी को (+) तथा लाभ में कमी/हानि में वृद्धि को (-) से दर्शाया गया है।

@ कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची - VI के आवश्यकतानुसार निवेशित पूँजी अंशधारकों की निधि तथा दीर्घावधि ऋण के योग को दर्शाती है। झा.रा.वि.बो. के संदर्भ में विनियोजित पूँजी, निवल अचल परिसंपत्तियों, प्रगतिशील पूँजीगत व्यय और कार्यशील पूँजी के योग को दर्शाती है क्योंकि अनुसूची - VI झा.रा.वि.बो. पर लागू नहीं है

$ निवेशित पूँजी से प्रतिफल लाभ एवं हानि लेखे में भारित ब्याज तथा लाभ के जोड़कर निकाली गई है।

$$ कम्पनी ने अभी तक पहला लेखा जमा नहीं किया है।

[1] टी.वी.एन.एल. (1988-99 और 1999-2000), जे.एस.एम.डी.सी. (2008-09) तथा जी.आर.डी.ए. (2008-09 से 2011-12) की पूरक लेखापरीक्षा प्रगति पर है।

परिशिष्ट - 1.4

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के वित्तीय परिणाम को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 1.15 में संदर्भित)

(राशि: ₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12
क. सम्पत्ति			
सकल ब्लॉक	1982.01	2351.60	2500.79
घटाव: मूल्य ह्रास	1064.55	1115.61	1232.97
निवल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	917.46	1235.99	1267.82
चालू पूँजीगत व्यय	1815.03	1813.99	1752.26
सम्पत्ति उपयोग में नहीं	2.29	2.29	2.29
निवेश	162.10	200.27	179.07
कुल चालू सम्पत्ति	4013.19	4740.45	5450.15
घाटा	5356.29	6079.12	9290.15
कुल (क)	**12266.36**	**14072.11**	**17941.74**
ख. दायित्व			
कार्यशील पूँजी हेतु उधार	73.92	218.98	274.93
पूँजीगत दायित्व पर बकाया भुगतान	3745.38	4481.13	5383.28
पूँजीगत दायित्व	264.39	210.10	205.58
राज्य सरकार से प्राप्त निधि	3005.93	2958.65	2743.16
योगदान, अनुदान और सहाय्य	1494.91	1570.38	1676.22
कुल चालू दायित्व	3681.83	4632.87	7658.57
कुल (ख)	**12266.36**	**14072.11**	**17941.74**
ग. विनियोजित पूँजी*	**3063.85**	**3157.56**	**811.66**

* विनियोजित पूँजी, निवल अचल परिसंपत्तियों (प्रगतिशील पूँजीगत व्यय सहित) और कार्यशील पूँजी के योग को दर्शाता है

परिशिष्ट - 1.5

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकारी परिणाम को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 1.15 में संदर्भित)

(राशि: ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.		विवरण	2009-10	2010-11	2011-12
1.	क)	राजस्व प्राप्तियाँ	1634.37	2010.69	2229.05
	ख)	राजस्व सहाय्य, अनुदान एवं अन्य आय	701.44	652.85	961.23
	ग)	कुल	2335.81	2663.54	3190.28
2.		राजस्व व्यय (पूंजीगत अपलिखित व्यय, अमूर्त परिसम्पत्तियों रहित परंतु मूल्य ह्रास एवं ब्याज को छोड़कर)*	2385.22	3036.58	3531.75
3.		वर्ष का सकल आधिक्य (+)/घाटा (-) (ना.)	(-) 49.41	(-)373.04	(-)341.47
4.		गत वर्ष से संबंधित समायोजन (ना.)	(-)147.44	97.26	(-)2252.70
5.		वर्ष का अंतिम सकल आधिक्य (+)/ घाटा (-) (3+4)	(-)196.85	(-)275.78	(-)2594.17
6.		विनियोग			
	क)	ह्रास	49.79	50.99	117.37
	ख)	पूंजी/ऋण पर ब्याज	609.75	554.67	622.13
	ग)	अन्य ऋण, अग्रिम आदि पर ब्याज	-	-	
	घ)	ऋण पर कुल ब्याज (ख+ग)	609.75	554.67	622.13
	ङ)	घटाव - पूंजीगत ब्याज	149.82	158.61	122.64
	च)	राजस्व में भारित शुद्ध ब्याज (घ-ङ)	459.93	396.06	499.49
7.		राज्य सरकार से प्राप्त सहाय्य के लेखांकन से पहले आधिक्य (+)/घाटा(-) {5-6क-6च-1ख(केवल अनुदान)}	(-)1106.57	(-)1172.83	(-)3961.03
8.		शुद्ध आधिक्य (+)/घाटा(-) (5-6क-6च)	(-)706.57	(-)722.83	(-)3211.03
9.		विनियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल** (8+6च)	(-)246.64	(-)326.76	(-)2711.54
10.		विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल का प्रतिशत***	-	-	-

नोट: * राजस्व व्यय में ह्रास और ऋण पर ब्याज शामिल नहीं है।

** विनियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल, शुद्ध आधिक्य/घाटा जोड़ लाभ हानि खाता पर भारित कुल ब्याज (घटाव: पूंजी पर ब्याज) को दर्शाता है।

*** विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल का प्रतिशत आकलित नहीं किया गया है, क्योंकि सभी वर्षो में घाटा था।

परिशिष्ट - 1.6

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिनके लेखे बकाया हैं, में किए गए निवेश को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 1.21 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	सा.क्षे.उ. का नाम	वर्ष जबतक लेखाओं को अंतिमीकृत किया गया है	अद्यतन अंतिमीकृत किए गए लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	अवधि जिस दौरान लेखे बकाया हैं	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में, जिसके लेखे बकाया है, किए गए निवेश			
					अंश पूँजी	ऋण	अनुदान	अन्य
कार्यरत सरकारी कम्पनी/निगम								
क. सरकारी कम्पनियाँ								
1.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड	2009-10	500.00	2010-11	-	-	-	-
				2011-12	-	-	-	-
				2012-13	-	-	542.00	-
2.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम	2004-05	50.00	2005-06	25.00	-	-	-
				2006-07	-	-	-	-
				2007-08	-	-	-	-
				2008-09	-	-	-	-
				2009-10	25.00	-	-	-
				2010-11	50.00	-	-	-
				2011-12	100.00	-	-	-
				2012-13	50.00	-	-	-
3.	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	2011-12	1100.00 (1050.00)	2012-13	1400.00	-	-	-
4.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	1999-2000	10000.00	2000-01	-	-	-	-
				2001-02	-	1500.00	-	-
				2002-03	-	1500.00	-	-
				2003-04	-	-	-	-
				2004-05	-	500.00	-	-
				2005-06	500.00	1400.00	-	-
				2006-07	-	800.00	-	-
				2007-08 to 2012-13	-	-	-	-
5.	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	2011-12	950.00 (150.00)	2012-13	50.00	-	-	-
6.	झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड	2011-12	500.00 (300.00)	2012-13	-	2000.00	-	-
7.	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	-	-	2010-11	500.00	-	9400.00	
				2011-12	-	4396.00	20000.00	
				2012-13	-	-	7500.00	-
	कुल (क)		**13100.00 (1500.00)**		**2700.00**	**12096.00**	**37442.00**	**-**

क्र.सं.	सा.क्षे.उ. का नाम	वर्ष जबतक लेखाओं को अंतिमीकृत किया गया है	अद्यतन अंतिमीकृत किए गए लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	अवधि जिस दौरान लेखे बकाया हैं	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में, जिसके लेखे बकाया है, किए गए निवेश			
					अंश पूँजी	ऋण	अनुदान	अन्य
ख. सांविधिक निगम								
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	2011-12	-	2012-13	-	54170.00	110725.00	-
	कुल (ख)				**-**	**54170.00**	**148167.00**	-
	कुल (क)+(ख)		**13100.00 (1500.00)**		**2700.00**	**66266.00**	**148167.00**	**-**

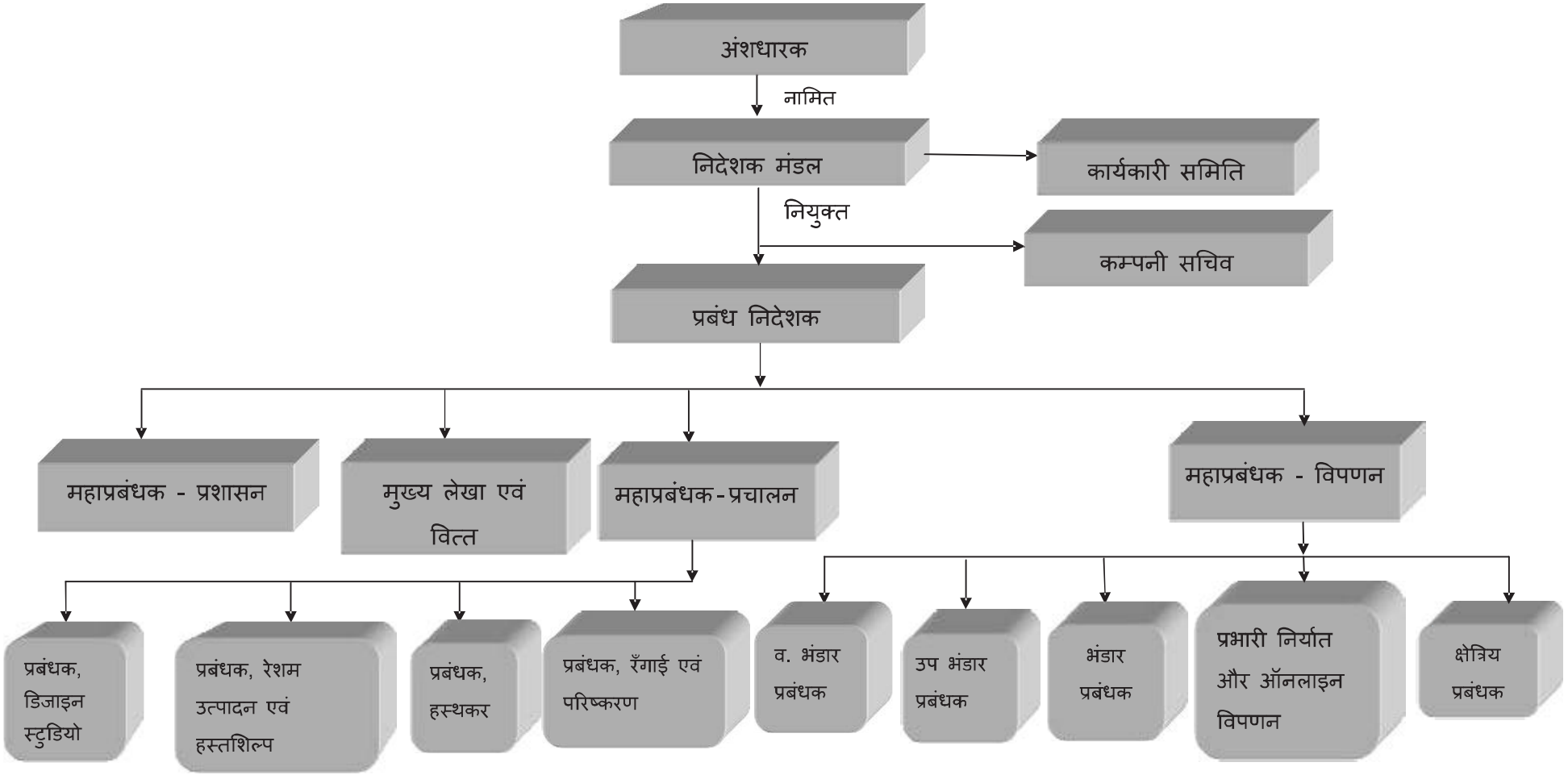
(स्रोत: सरकारी कम्पनी/सांविधिक निगम द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

कोष्ठक में आँकड़े अंश आवेदन राशि को दर्शाते हैं)

परिशिष्ट - 2.1

झारक्राफ्ट की संगठन संरचना

(कंडिका 2.2 में संदर्भित)



परिशिष्ट - 2.2

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान उत्पादित कोकून का ब्योरा दर्शाती विवरणी

(कंडिका 2.10 में संदर्भित)

(संख्या लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1.	बुनियादी डी.एफ.एल. के उत्पादन के लिए संरक्षित कोकून	28.50	47.80	73.54	139.34	289.18
2.	बुनियादी डी.एफ.एल. का उत्पादन	4.07	4.45	9.08	9.82	27.42
3.	बुनियादी डी.एफ.एल. जिसका उत्पादन होना था	5.42	9.08	13.97	26.47	54.94
4.	बुनियादी डी.एफ.एल. का क्रय	3.04	1.51	2.78	7.05	14.38
5.	कुल उपलब्ध बुनियादी डी.एफ.एल. (2+4)	7.11	5.96	11.86	16.87	41.80
6.	कुल बुनियादी डी.एफ.एल. जो उपलब्ध होना था (3+4)	8.46	10.59	16.75	33.52	69.32
7.	वाणिज्यिक डी.एफ.एल. का उत्पादन	44.00	21.64	69.69	143.49	278.82
8.	वाणिज्यिक डी.एफ.एल. जिसका उत्पादन होना था (6*40/5)	67.64	84.74	134.02	268.20	554.60
9.	क्षेत्रीय प्रजाति के वाणिज्यिक डी.एफ.एल. (लरिया, मोडिया आदि) का उत्पादन	0.94	0.53	1.41	2.14	5.02
10.	कुल उपलब्ध वाणिज्यिक डी.एफ.एल. (7+9)	44.94	22.17	71.10	145.63	284.54
11.	कुल वाणिज्यिक डी.एफ.एल. जो उपलब्ध होना था (8+9)	68.58	85.27	135.43	270.34	560.02
12.	उत्पादित वाणिज्यिक कोकून	1855.31	1910.92	2266.52	8016.02	14048.77
13.	वाणिज्यिक कोकून जिसका उत्पादन होना था (11*40)	2743.20	3410.64	5417.23	10813.47	22384.54
14.	कम उत्पादित कोकून (13-12)	887.89	1499.72	3150.71	2797.45	8335.77
15.	उत्पादन में कमी (% में) (14/13*100)	32.37	43.97	58.16	25.87	37.24
16.	औसत लागत[1] (₹)	0.95	1.05	0.96	1.07	-
17.	संभावित हानि (₹ करोड़ में)	8.43	15.75	30.25	29.93	84.36

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

नोट: वर्ष 2012-13 से संबंधित सूचनायें विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी.

[1] खरसावाँ में चल रहा दर 2008-09 = ₹ (1.25+0.64)/2= ₹ 0.95, 2009-10= ₹ (1.37+0.73)/2= ₹ 1.05, 2010-11= ₹ (1.25+0.66)/2= ₹ 0.96 और 2011-12= ₹ (1.50+0.63)/2= ₹ 1.07

परिशिष्ट - 2.3

क्लस्टर विकास योजना के लिए मंजूर राशि, लक्ष्य एवं उपलब्धि का ब्योरा दर्शाती विवरणी

(कंडिका 2.17 में संदर्भित)

स्वीकृती की तिथि	कलस्टरों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	लक्ष्य (संख्या में)					उपलब्धि (संख्या में)				
			सी.एफ.सी कार्यशाला	रँगाई भवन	बुनाई प्रशिक्षण	रँगाई प्रशिक्षण	डिजाइन प्रशिक्षण	सी.एफ.सी कार्यशाला	रँगाई भवन	बुनाई प्रशिक्षण	रँगाई प्रशिक्षण	डिजाइन प्रशिक्षण
फरवरी 2008	10	541.35	10	10	200	200	200	शून्य	शून्य	200	200	120
अक्टूबर 2008	11	635.25	11	11	220	220	220	शून्य	शून्य	220	220	160
नवंबर 2009	5	283.50	5	शून्य	100	100	100	शून्य	शून्य	60	100	शून्य
दिसंबर 2010	5	283.50	5	शून्य	100	100	100	शून्य	शून्य	40	शून्य	शून्य
फरवरी 2011	4	226.80	4	शून्य	80	80	80	शून्य	शून्य	40	शून्य	शून्य
कुल	**35**	**1970.40**	**35**	**21**	**700**	**700**	**700**	शून्य	शून्य	**560**	**520**	**280**

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना और योजना से संकलित आँकड़े)

परिशिष्ट - 2.4

ग्रुप एप्रौच योजना के संबंध में स्वीकृत राशि, लक्ष्य एवं उपलब्धि का ब्योरा दर्शाती विवरणी

(कंडिका 2.18 में संदर्भित)

स्वीकृती की तिथि	स्वीकृत समुहों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	लक्ष्य (संख्या में)			उपलब्धि (संख्या में)		
			कार्यशाला का निर्माण	प्रशिक्षण		कार्यशाला का निर्माण	प्रशिक्षण	
				बुनाई	रँगाई		बुनाई	रँगाई
अक्टूबर 2008	11	0.66	07	80	140	06	60	120
फरवरी 2009	12	0.70	07	100	120	06	80	100
नवंबर 2009	19	1.13	19	शून्य	शून्य	15	शून्य	शून्य
फरवरी 2011	48	2.86	48	शून्य	शून्य	35	शून्य	शून्य
कुल	**90**	**5.35**	**81**	**180**	**260**	**62**	**140**	**220**

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना और योजना से संकलित आँकड़े)

परिशिष्ट - 2.5

पी.डब्ल्यु.सी.एस. योजना से संबंधित स्वीकृत राशि, लक्ष्य एवं उपलब्धि को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 2.19 में संदर्भित)

वर्ष	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	लक्ष्य (संख्या में)		उपलब्धि (संख्या में)	
		कार्यशालाओं का निर्माण होना था	बुनकरों को प्रशिक्षण देना था	कार्यशालाओं का निर्माण हुआ	बुनकरों को प्रशिक्षण दिया
2008-09	3.00	14	शून्य	शून्य	शून्य
2009-10	4.00	23	460	7	288
2010-11	8.10	40	600	16	928
2011-12	8.70	100	2000	7	866
2012-13	7.32	59	1180	शून्य	1542
कुल	**31.12**	**236**	**4240**	**30**	**3624**

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना और योजना से संकलित आँकड़े)

परिशिष्ट - 3.1

अधिसूचित उपज से अधिक संग्रहित केन्दु पत्ते की अतिरिक्त मात्रा के लिये भुगतान की राशि को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 3.1.3 में संदर्भित)

मौसम	लॉटों की संख्या	अधिसूचित मात्रा (मानक बोरा)	कुल संग्रहण (मानक बोरा)	अतिरिक्त संग्रहण (मानक बोरा) (घ - ग)	अतिरिक्त मात्रा का पूर्ण बिक्रय मूल्य (₹)	बिक्रय मुल्य (च के 50 प्रतिशत) (₹)	अधिसूचित उपज से अधिक संग्रहण का प्रतिशत (ड़/ग x 100)
क	ख	ग	घ	ड़	च	छ	ज
2008	85	232375	288440	56065	15092754	7546377	24.13
2009	86	228200	290296	62096	20085336	10042668	27.21
2010	90	211075	270629	59554	25013258	12506629	28.21
2011	24	45650	50739	5089	4334934	2167467	11.15
2012	122	338025	459507	121482	86474136	43237068	35.94
कुल	**407**	**1055325**	**1359611**	**304286**	**151000418**	**75500209**	**28.83**

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

परिशिष्ट -3.2

कंडिकायें/समीक्षायें, जिसका उत्तर अप्राप्त था, की विवरणी

(कंडिका 3.6.1 में संदर्भित)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		ले.प.प्र. में कंडिकाओं की सं.	कंडिकाओं की सं. जिसका उत्तर अप्राप्त था	ले.प.प्र. में कंडिकाओं की सं.	कंडिकाओं की सं. जिसका उत्तर अप्राप्त था	ले.प.प्र. में कंडिकाओं की सं.	कंडिकाओं की सं. जिसका उत्तर अप्राप्त था	ले.प.प्र. में कंडिकाओं की सं.	कंडिकाओं की सं. जिसका उत्तर अप्राप्त था	ले.प.प्र. में कंडिकाओं की सं.	कंडिकाओं की सं. जिसका उत्तर अप्राप्त था
1.	ऊर्जा	7	7	4	4	6	6	2	2	3	3
2.	वन एवं पर्यावरण	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
3.	गृह	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1
4.	खान एवं भू-तत्व	1						1	1		
5.	जल संसाधन, उद्योग, ऊर्जा, गृह, पर्यटन, वन एवं पर्यावरण, शहरी विकास, खान एवं भू-तत्व	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	कुल	**9**	**8**	**5**	**5**	**7**	**7**	**4**	**4**	**6**	**6**

परिशिष्ट - 3.3

विभागावार लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) की विवरणी

(कंडिका 3.6.3 में संदर्भित)

क्र. सं.	विभाग का नाम	सा.क्षे.उ. की सं.	लम्बित नि.प्र. की सं.	लम्बित कंडिकाओं की सं.	जिस वर्ष से कंडिका लम्बित है
1.	ऊर्जा	2	309	1221	2005-06
2.	वन एवं पर्यावरण	1	26	94	2006-07
3.	खान एवं भू-तत्व	1	4	18	2010-11
4.	पर्यटन	1	13	59	2007-08
5.	उद्योग	2	4	6	2008-09
6.	गृह	1	12	55	2006-07
7.	जल संसाधन	1	16	45	2006-07
8.	नगर विकास	1	2	12	2009-10
कुल		**10**	**386**	**1510**	

परिशिष्ट - 3.4

विभागावार प्रारूप कंडिकाओं की विवरणी जिसके उत्तर अप्राप्त थे

(कंडिका 3.6.3 में संदर्भित)

क्रम. सं.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की सं.	निर्गत करने की अवधि
1.	ऊर्जा	4	जून/जुलाई 2013
2.	वन एवं पर्यावरण	1	अगस्त 2013
	कुल	**5**	